



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09102021-230295  
CG-DL-E-09102021-230295

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1  
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 305]  
No. 305]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 8, 2021/आश्विन 16, 1943  
NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 8, 2021/ASVINA 16, 1943

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय  
(वाणिज्य विभाग)  
(व्यापार उपचार महानिदेशालय)  
अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 अक्टूबर, 2021

अंतिम जांच परिणाम  
(मामला सं. एडीडी-एसएसआर- 01/2021)

**विषय:** चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "1,1,1,2- टेट्राफ्लूरोइथेन अथवा आर-134 ए" के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच की निर्णायक समीक्षा।

**फा.सं. 7/1/2021-डीजीटीआर.**—समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (इसके पश्चात् इसे 'अधिनियम' के रूप में भी कहा गया है) और समय-समय पर यथासंशोधित तत्संबंधी सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, आकलन और संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण) नियमावली, 1995 (इसके पश्चात् इसे 'पाटनरोधी नियमावली' अथवा 'नियमावली' के रूप में भी कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी (इसके पश्चात् इसे "प्राधिकारी" के रूप में भी कहा गया है) को मैसर्स एसआरएफ लिमिटेड (इसके पश्चात् इसे "आवेदक" अथवा "याचिकाकर्ता" के रूप में भी कहा गया है) से एक आवेदन प्राप्त हुआ, जिसके तहत चीन जन. गण. (इसके पश्चात् इसे "संबद्ध देश" के रूप में भी कहा गया है) के मूल की अथवा वहां से निर्यातित "1,1,1,2- टेट्राफ्लूरोइथेन अथवा आर-134 ए" (इसके

पश्चात् इसे “संबद्ध वस्तु” अथवा “विचाराधीन उत्पाद” अथवा “पीयूसी” के रूप में भी कहा गया है) के आयातों पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा शुरू करने के लिए अनुरोध किया गया है।

**क. मामले की पृष्ठभूमि**

2. प्राधिकारी ने दिनांक 19 अगस्त, 2009 की अधिसूचना सं. 14/24/2019- डीजीएडी के तहत चीन जन. गण. और जापान के मूल की अथवा वहां से निर्यातित “1,1,1,2-टेट्राफ्लूरोइथेन अथवा आर-134 ए” के आयातों के संबंध में मूल पाटनरोधी जांच शुरू की थी। प्राधिकारी द्वारा 10 मई, 2011 की अधिसूचना सं. 14/24/2009- डीजीएडी के तहत चीन जन. गण. और जापान के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करते हुए अन्तिम जांच परिणाम अधिसूचना जारी की थी। राजस्व विभाग द्वारा दिनांक 15 जुलाई, 2011 की अधिसूचना सं. 61/2011- सीमा शुल्क (एडीडी) के तहत निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क (एडीडी) लगाए गए थे।
3. प्राधिकारी ने दिनांक 10 अप्रैल, 2015 की अधिसूचना सं. 15/23/2014- डीजीएडी के तहत चीन जन. गण. के मूल की अथवा वहां से निर्यातित “1,1,1,2-टेट्राफ्लूरोइथेन अथवा आर-134 ए” के आयातों के संबंध में प्रथम निर्णायक समीक्षा जांच शुरू की थी। प्राधिकारी द्वारा दिनांक 30 मई, 2016 की अधिसूचना सं. 15/23/2014- डीजीएडी के तहत अन्तिम जांच परिणाम अधिसूचना जारी की गई थी, जिसके तहत चीन जन. गण. के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क को आगे बढ़ाने की सिफारिश की गई थी। राजस्व विभाग द्वारा दिनांक 11 जुलाई, 2016 की अधिसूचना सं. 30/2016- सीमा शुल्क (एडीडी) के तहत पाटनरोधी शुल्कों को आगे बढ़ाया गया था।
4. प्राधिकारी ने दिनांक 27 फरवरी, 2017 की अधिसूचना सं. 15/22/2016- डीजीएडी के तहत चीन जन. गण. के मूल की अथवा वहां से निर्यातित “1,1,1,2-टेट्राफ्लूरोइथेन अथवा आर-134 ए” के आयातों के संबंध में एक नई शिपर समीक्षा जांच शुरू की थी। प्राधिकारी द्वारा दिनांक 26 जुलाई, 2018 की अधिसूचना सं. 15/22/2016- डीजीएडी के तहत अन्तिम जांच परिणाम अधिसूचना जारी की गई थी, जिसके तहत शिपर समीक्षा जांच को समाप्त किया गया था।
5. अधिनियम की धारा 9क (5) के अनुसार, लगाया गया पाटनरोधी शुल्क, जब तक कि पहले हटा न लिया जाए, उसे लगाए जाने की तारीख से पांच वर्षों की अवधि समाप्त होने पर उसका प्रभाव समाप्त हो जाएगा और प्राधिकारी को यह समीक्षा करनी अपेक्षित होती है कि क्या पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति होने पर पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है। इसके अलावा, नियमावली के नियम 23(1ख) के तहत यह प्रावधान है कि :-  
*“अधिनियम के अंतर्गत लगाया गया कोई निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क उसके लगाए जाने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक प्रभावी रहेगा बशर्ते निर्दिष्ट प्राधिकारी उक्त अवधि से पूर्व अपनी खुद की पहल पर या घरेलू उद्योग की ओर से किए गए विधिवत् पुष्टिकृत अनुरोध के आधार पर उक्त अवधि समाप्त होने से पूर्व उचित अवधि के भीतर इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि उक्त शुल्क की समाप्ति से पाटन एवं घरेलू उद्योग को क्षति जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है।”*
6. उपरोक्त के अनुसार, प्राधिकारी को घरेलू उद्योग द्वारा अथवा उसकी ओर से किए गए एक विधिवत साक्ष्य सहित अनुरोध के आधार पर समीक्षा करनी अपेक्षित होती है कि क्या पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति पर पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है।
7. प्राधिकारी ने आवेदक द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर, भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित दिनांक 19 फरवरी, 2021 की अधिसूचना सं. 7/1/2021-डीजीटीआर के तहत एक सार्वजनिक सूचना जारी की, जिसके तहत नियमावली के नियम 23 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क (5) के अनुसार, संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के संबंध में पाटनरोधी शुल्क लगाना जारी रखने और यह जांच करने की जरूरत की समीक्षा की गई कि क्या उक्त पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति होने से घरेलू उद्योग को पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है।
8. जांच का निष्कर्ष लंबित रहने के चलते, दिनांक 24 मई, 2021 की अधिसूचना सं. 30/2021- सीमा शुल्क (एडीडी) के तहत दिनांक 10 जनवरी, 2022 तक, जिसमें यह तारीख भी शामिल है, पाटनरोधी शुल्कों को आगे बढ़ाया गया था।

9. वर्तमान समीक्षा के दायरे में दिनांक 30 मई, 2016 की अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना सं. 15/23/2014- डीजीएडी के सभी पहलुओं को शामिल किया गया है, जिसके तहत संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क को आगे बढ़ाने की सिफारिश की गई थी।

**ख. प्रक्रिया**

10. संबद्ध जांच के संबंध में नीचे दी गई प्रक्रिया का अनुसरण किया गया है :-

- क. प्राधिकारी ने भारत में संबद्ध देश के दूतावास को पाटनरोधी नियमावली के नियम 5 के उप नियम (5) के अनुसार वर्तमान जांच शुरू करने की कार्यवाई करने से पूर्व निर्णायक समीक्षा जांच के लिए आवेदन प्राप्त होने के बारे में अधिसूचित किया था।
- ख. प्राधिकारी ने संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क के संबंध में निर्णायक समीक्षा जांच शुरू करते हुए भारत के राजपत्र असाधारण में प्रकाशित दिनांक 19 फरवरी, 2021 की एक सार्वजनिक सूचना जारी की।
- ग. प्राधिकारी ने भारत में संबद्ध देश के दूतावास, ज्ञात आयातकों, आयातक/ प्रयोक्ता संघों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को, आवेदक द्वारा उपलब्ध कराए गए पतों के अनुसार, दिनांक 19 फरवरी, 2021 की जांच शुरुआत अधिसूचना की एक प्रति भेजी। हितबद्ध पक्षकारों को निर्धारित समय सीमा के भीतर निर्धारित रूप में और निर्धारित तरीके से संगत सूचना प्रदान करने और अपने विचारों को लिखित में अवगत कराने के लिए परामर्श दिया गया था।
- घ. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6 (3) के अनुसार ज्ञात उत्पादकों/ निर्यातकों और भारत में संबद्ध देश के दूतावास को आवेदन के अगोपनीय पाठ की एक प्रति प्रदान की।
- ङ. भारत में संबद्ध देश के दूतावास को, निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने के लिए उसके देश से निर्यातकों/ उत्पादकों को परामर्श देने का भी अनुरोध किया गया था। उत्पादकों/ निर्यातकों को भेजे गए पत्र और प्रश्नावली की एक प्रति भी संबद्ध देश से ज्ञात उत्पादकों/ निर्यातकों के नामों और पतों के साथ उसे भेजी गई थी।
- च. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध पर दिनांक 25 मार्च, 2021 के पत्र के तहत दिनांक 15 अप्रैल, 2021 तक प्रश्नावली का उत्तर दाखिल करने के लिए समय का विस्तार प्रदान किया था।
- छ. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6 (4) के अनुसार संबद्ध देश में निम्नलिखित ज्ञात उत्पादकों/ निर्यातकों को प्रश्नावली भेजी :-
  - i. मै. झेजियांग जुहुआ ग्रुप आई/ ई कं. लि.
  - ii. मै. शानडोंग डोंगहुई केमिकल लि.
  - iii. मै. सिनकेम इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन केमिकल्स (ताइकैंग) कं. लि.
  - iv. मै. जियांग्सु कंगताई फ्लुओराइन केमिकल कं. लि.
  - v. मै. चांगशु 3एफ झोंगहाओ न्यू केमिकल मैटिरियल्स कं. लि.
  - vi. मै. झेजियांग फोटेक इंटरनेशनल कं. लि.
  - vii. मै. डु पोंट चाइना होल्डिंग कं. लि.
  - viii. मै. झेजियांग पुजियांग वाइलियन केमिकल कं. लि.
  - ix. मै. मित्सुई डु पोंट फ्लुओरोकेमिकल्स कं. लि.
  - x. मै. जियांग्सु ब्लूस्टार इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन टेक्नोलॉजी कं. लि.
  - xi. मै. सिनकेम मॉडर्न इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन केमिकल्स (जियान) कं. लि.
  - xii. मै. जियांग्सु जिन क्सुई ग्रुप कं. लि.

- xiii. मै. जियांग्सु योंगहे फ्लेरोकेमिकल कं. लि.
- xiv. झेजियांग सनमेई केमिकल इन्ड. कं. लि.
- ज. उपरोक्त अधिसूचना के प्रत्युत्तर में, निम्नलिखित उत्पादकों/ निर्यातकों और उनके संगत निर्यातकों/ व्यापारियों ने उत्तर दिया है और निर्यातक प्रश्नावली उत्तर तथा/ अथवा विधिक अनुरोध प्रस्तुत/ दाखिल किए हैं :-
- मै. सिनकेम इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन केमिकल्स (ताइकैंग) कं. लि. (उत्पादक/ निर्यातक)
  - मै. शांक्सी सिनोकेम लानतियान न्यू केमिकल मैटिरियल कं. लि. (उत्पादक/ निर्यातक)
  - मै. शानडोंग डोंगहुई केमिकल कं. लि. (उत्पादक/ निर्यातक)
  - मै. झेजियांग सनमेई केमिकल इन्ड. कं. लि. (उत्पादक/ निर्यातक)
  - मै. झेजियांग क्यूहुआ फ्लुओर- केमिस्ट्री कं. लि. (उत्पादक/ निर्यातक)
  - मै. झेजियांग क्यूझोऊ लियानझोउ रेफ्रिजरेट्स कं. लि. (उत्पादक/ निर्यातक)
  - मै. सिनोकेम लानतियान ट्रेडिंग कं. लि. (घरेलू विक्रेता)
  - मै. सिनोकेम जियान जिनकूल न्यू केमिकल मैटिरियल्स कं. लि. (व्यापारी)
  - मै. सिनोकेम लानतियान फ्लुओरो मैटिरियल्स कं. लि. (घरेलू विक्रेता)
  - मै. सिनोकेम मॉडर्न इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन केमिकल (जियान) कं. लि. (पूर्व उत्पादक)
- झ. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6 (4) के अनुसार आवश्यक सूचना की मांग करते हुए निम्नलिखित ज्ञात आयातकों तथा भारत में संबद्ध वस्तुओं के प्रयोक्ताओं को प्रश्नावली भेजी :-
- मै. ई. आई. डु पोंट इंडिया प्रा. लि.
  - मै. नावाइन फ्लूओराइन इंटरनेशनल लि.
  - मै. स्टालियन इंटरप्राइजेज
  - मै. वैल्यू रेफ्रिजरेट्स प्रा. लि.
  - मै. मंगली पेट्रोकेम लि.
  - मै. केपीएल इंटरनेशनल लि.
  - मै. किरो रेफ्रिजरेट्स प्रा. लि.
  - मै. हनीवेल इंटरनेशनल (आई) प्रा. लि.
  - मै. ओ. वी. फ्लुओरो केम्स प्राइवेट लिमि.
  - मै. ब्रेन्नटैंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
  - मै. सिपला लिमिटेड
- च. उपरोक्त अधिसूचना के उत्तर में किसी भी आयातक अथवा प्रयोक्ता ने उत्तर नहीं दिया अथवा आयातक/ प्रयोक्ता प्रश्नावली उत्तर/ विधिक अनुरोध प्रस्तुत नहीं किए और/ अथवा हितबद्ध पक्षकार के रूप में पंजीकृत नहीं किया।
- ट. सभी हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची डीजीटीआर की वेबसाइट पर अपलोड की गई थी और साथ में उन सभी को यह अनुरोध किया गया था कि सभी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को अपने अनुरोधों के अगोपनीय पाठ का ईमेल करें क्योंकि सार्वजनिक फाइल कोविड-19 वैश्विक महामारी के चलते फिजिकल तौर पर सुलभ नहीं थी।

- ठ. वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए जांच की अवधि (पीओआई) 1 अक्टूबर, 2019 से 30 सितंबर, 2020 (12 माह) की है। क्षति जांच की अवधि पर वर्ष 2017-18, 2018-19, 2019-20 और जांच की अवधि के रूप में विचार किया गया है।
- ड. प्राधिकारी ने जांच की अवधि सहित क्षति अवधि के लिए संबद्ध वस्तुओं हेतु वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशलय (डीजीसीआई एंड एस) से सौदा-वार आयात के आंकड़े प्राप्त किए हैं और सौदों की विधिवत जांच करने के बाद आंकड़ों का विश्लेषण किया है।
- ढ. घरेलू उद्योग और प्रतिवादी निर्यातकों द्वारा प्रदान किए गए आंकड़ों का, वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए आवश्यकता के अनुसार सत्यापन किया गया था।
- ण. भारत में संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन की लागत और तर्कसंगत लाभों के आधार पर क्षतिरहित कीमत (इसके पश्चात इसे "एनआईपी" के रूप में भी कहा गया है), सामान्यतः स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी) के अनुसार और नियमावली के अनुबंध-III के अनुसार घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना को ध्यान में रखते हुए, निर्धारित की गई ताकि यह पता चल सके कि क्या पाटन मार्जिन से कमतर पाटनरोधी शुल्क लगाना, घरेलू उद्योग की क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगा।
- त. नियमावली के नियम 6 (6) के अनुसार, प्राधिकारी ने दिनांक 24 मई, 2021 को वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई मौखिक सुनवाई में अपने विचार प्रकट करने के लिए हितबद्ध पक्षकारों को एक अवसर प्रदान किया था। जिन पक्षकारों ने मौखिक सुनवाई में अपने विचार प्रस्तुत किए थे, उन्हें मौखिक रूप से व्यक्त किए गए अपने विचारों को लिखित अनुरोधों में दाखिल करने और उसके साथ प्रत्युत्तर (रिज्वाइंडर), यदि कोई हो, तो उसे भी दाखिल करने के लिए अनुरोध किया गया था। पक्षकारों ने अन्य हितबद्ध पक्षकारों के साथ उनके अगोपनीय अनुरोध साझा किए और उन्हें इनका खंडन प्रस्तुत करने का परामर्श दिया।
- थ. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध, उठाए गए तर्कों और विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा जांच की अवधि के दौरान प्रदान की गई सूचना पर, जहां तक ये साक्ष्य के साथ हैं और वर्तमान जांच में संगत हैं, विचार किया गया है।
- द. प्राधिकारी ने जांच के दौरान, हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रदान की गई सूचना के सही होने के संबंध में स्वयं को संतुष्ट किया है, जो कि इस अंतिम जांच परिणाम का आधार हैं, जहां तक कि ये संभव हैं और जहां तक इसे संगत और संभव पाया गया, घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत किए गए आंकड़ों/ दस्तावेजों की पुष्टि की गई है।
- ध. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रदान की गई सूचना की, गोपनीयता के दावों की पर्याप्तता के संबंध में जांच की गई थी। प्राधिकारी ने संतुष्ट होने पर, गोपनीयता के दावों को, आवश्यकता के अनुसार स्वीकार किया है और ऐसी सूचना पर गोपनीय होने के रूप में विचार किया है तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट नहीं की है। जहां तक संभव हुआ, गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करने वाले पक्षकारों को, गोपनीय आधार पर दाखिल की गई सूचना का पर्याप्त अगोपनीय पाठन प्रदान करने के लिए निदेश दिया गया था।
- न. नियमावली के अनुसार, प्राधिकारी ने मामले के ऐसे अनिवार्य तथ्यों को प्रकट किया है, जो दिनांक 30.09.2021 को एक प्रकटीकरण विवरण के रूप में इसके अंतिम जांच परिणामों का आधार होंगे और हितबद्ध पक्षकारों को उस पर टिप्पणियां करने के लिए दिनांक 6.10.2021 तक का समय प्रदान किया गया था। हितबद्ध पक्षकारों की टिप्पणियों पर, जहां तक ये संगत पाई गईं, प्राधिकारी द्वारा विचार किया गया है और इस जांच परिणाम में विचार किया गया है।
- प. जहां कहीं भी किसी हितबद्ध पक्षकार ने इसे सुलभ कराने से इंकार किया है अथवा जांच की अवधि के दौरान सूचना को अन्यथा प्रदान नहीं किया है अथवा जांच में पर्याप्त रूप से उसे छिपाया है, तो प्राधिकारी ने ऐसे हितबद्ध पक्षकारों को असहयोगी माना है और इस अंतिम जांच परिणाम में, उपलब्ध तथ्यों के आधार पर दर्ज किया है।
- फ. इस अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना में "\*\*\*\*" किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर प्रदान की गई सूचना को दर्शाता है और प्राधिकारी द्वारा नियमावली के तहत उस पर विचार किया गया है।
- व. प्राधिकारी द्वारा संबद्ध जांच के लिए अपनाई गई विनिमय दर 1 यूएस डॉलर = 74.38 रु. है।

**ग. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु**

**ग.1 अन्य हितवद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध**

11. अन्य हितवद्ध पक्षकारों द्वारा, विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं :-

- क. विचाराधीन उत्पाद को पैक की गई सामग्री और बिना पैक की गई सामग्री के लिए कोई अन्तर किए बिना परिभाषित किया गया है और यहां तक कि समग्र आयात संबंधी आंकड़े, संबद्ध देश के लिए कुछेक मापदंडों को छोड़कर इस ढंग से प्रस्तुत किए गए हैं जैसे कि याचिकाकर्ता द्वारा मनमाने ढंग से चुनाव किया गया हो।
- ख. पैक किए गए और बिना पैक किए गए रूप में प्रस्तावित पृथक जांच को घरेलू उद्योग द्वारा सिद्ध नहीं किया गया है।

**ग.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध**

12. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध इस प्रकार हैं :-

- क. विचाराधीन उत्पाद "1,1,1,2- टेट्राफ्लूरोइथेन अथवा आर- 134 ए" है। चूंकि वर्तमान जांच एक निर्णायक समीक्षा है, अतः विचाराधीन उत्पाद वही है, जो विगत में परिभाषित किया गया था। उत्पाद में समय अवधि के साथ कोई बदलाव नहीं आया है।
- ख. घरेलू उद्योग द्वारा निर्मित उत्पाद, संबद्ध देश से आयातित उत्पाद के समान वस्तु है। समान वस्तु के मामले के संबंध में, प्राधिकारी द्वारा विगत जांचों में भी पहले विचार किया जा चुका है।
- ग. उत्पाद के पैक किए गए रूपों और बिना पैक किए गए रूपों में, विचाराधीन उत्पाद की लागत और कीमत में अन्तर है और यह उत्पाद विवरण में अलग से उल्लेख किए जाने के लिए एक अलग उत्पाद नहीं बनता। घरेलू उद्योग ने पैक और पैक न किए जाने के संबंध में महत्वपूर्ण विवरण, कीमत कटौती, पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन का विवरण प्रदान किया है। पैक किए गए और पैक न किए गए रूपों के लिए पृथक पाटन और क्षति मार्जिन की गणना की जानी चाहिए और उसके बाद विचाराधीन उत्पाद के लिए गणना करनी चाहिए, जैसा कि विगत जांच में किया गया है।

**ग.3 प्राधिकारी द्वारा जांच**

13. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद "1,1,1,2- टेट्राफ्लूरोइथेन अथवा आर- 134 ए" है। विचाराधीन उत्पाद वही है, जिसे विगत में की गई जांच में परिभाषित किया जा चुका है, जिसे अंतिम जांच परिणामों में इस प्रकार परिभाषित किया गया था :

वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद 1,1,1,2 टेट्राफ्लूरोइथेन अथवा सभी प्रकार के आर 134ए हैं जिसे टेट्राफ्लूरोइथेन जेनेट्रान 134ए, सुवा 134ए, अथवा एचएफसी 134सी, एचएफए 134ए अथवा नॉइफ्लूरेन भी कहा जाता है। यह एक हेलेोएल्केन प्रशीतक है जिसके थर्मोडायनेमिक गुणधर्म आर-12 (डाइक्लोरो डाइफ्लूरोमीथेन) के समान होते हैं परन्तु ओजोन डिप्लीशन क्षमता नहीं होती। इसका रासायनिक सूत्र सीएच<sub>2</sub>एचएफसीएफ होता है और क्रथनांक -26.3 डि. से. (-15.34 डिग्री एफ) होता है। यह एक अक्रिय गैस है जिसका उपयोग प्राथमिक रूप से घरेलू प्रशीतन तथा ऑटोमोबाइल एयर कंडीशनरों में उच्च तापमान प्रशीतन हेतु किया जाता है। सम्बद्ध वस्तु के अन्य उपयोगों में प्लास्टिक फोम क्लोईंग क्लीनिंग सॉल्वेंट के रूप में उपयोग भेषजों (उदाहरणार्थ ब्रॉकोडायलेटर) की डिलीवरी हेतु प्रोपेलेंट के रूप में गैस डस्टरो तथा एयर ड्रायरों में सम्पीडित वायु से नमी हटाने में इसका उपयोग किया जाता है।

सम्बद्ध वस्तु का आयात सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम के अध्याय 29 के अंतर्गत भारतीय व्यापार वर्गीकरण (सुमेलीकृत वस्तु विवरण एवं कोडिंग प्रणाली) उप शीर्ष 2903 तहत "हाइड्रोकार्बनों के हैलेजन युक्त व्युत्पन्न" उप शीर्ष 29033919 के तहत अन्य फ्लोरीनयुक्त व्युत्पन्न के अंतर्गत किया जा रहा है। तथापि याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि विचाराधीन उत्पाद के लिए कोई निर्धारित सीमा शुल्क कोड नहीं है और इसका आयात विभिन्न सीमा शुल्क उप शीर्षों के अन्तर्गत किया जा रहा है। तथापि सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और इस जांच के दायरे पर किसी भी प्रकार से बाध्यकारी नहीं है।

तथापि, सीजीएमपी अनुमोदित फार्मा ग्रेड को पी यू सी के दायरे से बाहर रखा गया है, क्योंकि इसका न तो घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादन और तथा न ही संबद्ध देश से आयात किया जाता है।"

उत्पाद को अध्याय 29 के तहत शीर्षक 2903, हाइड्रोकार्बन्स के हैलोजेनेटेड डेरिवेटिव्स जैसे "अन्य फ्यूओरिनेटेड डेरिवेटिव्स" के रूप में उप शीर्षक 29033919 के तहत वर्गीकृत किया गया है। सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और वर्तमान आवेदन और प्रस्तावित समीक्षा जांच के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।"

14. चूंकि वर्तमान जांच एक निर्णायक समीक्षा जांच है, अतः विचाराधीन उत्पाद वही रहा, जिसे विगत में आयोजित जांच में परिभाषित किया जा चुका है। संबद्ध वस्तुएं सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम के अध्याय 29 के तहत उप शीर्ष 2903 39 19 के अंतर्गत वर्गीकृत की गई हैं। तथापि, सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और यह विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।
15. प्राधिकारी रिकॉर्ड पर उपलब्ध सूचना से यह नोट करते हैं कि विचाराधीन उत्पाद संबद्ध देश से आयातित विचाराधीन उत्पाद के समान वस्तु है। यह उत्पाद पैक किए गए रूप में और पैक न किए गए रूप में, दोनों तरह से बेचा जा रहा है और दोनों रूप में अंतर केवल विचाराधीन उत्पाद की लागत और कीमत का है लेकिन दोनों, उत्पाद विवरण में उल्लिखित किए जाने के लिए कोई अलग उत्पाद नहीं बनते। घरेलू उद्योग ने पैक किए गए और पैक न किए गए रूप में आयात विवरण, कीमत कटौती का विवरण, पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन प्रदान किया है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद भौतिक और रासायनिक गुणों, निर्माण करने की प्रक्रिया एवं प्रौद्योगिकी, कार्यों और उपयोगों, उत्पाद विनिर्देशनों, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण की दृष्टि से संबद्ध देश से आयात किए गए उत्पादों के साथ तुलनीय हैं। दोनों ही तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। उपभोक्ताओं ने दोनों को एक दूसरे से बदलकर प्रयोग किया है और प्रयोग कर रहे हैं। अतः प्राधिकारी ने यह पाया है कि घरेलू उद्योग उत्पादित संबद्ध वस्तुएं नियमावली के नियम 2 (घ) के संदर्भ में, संबद्ध देश से आयात किए गए उत्पाद के समान वस्तु हैं।

#### घ. घरेलू उद्योग का दायरा और आधार

##### घ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

16. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा घरेलू उद्योग के दायरे और इसके आधार के संबंध में कोई भी अनुरोध नहीं किए गए हैं।

##### घ.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

17. घरेलू उद्योग द्वारा घरेलू उद्योग के दायरे और उसके आधार के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं :-

क. आवेदक, नामतः मैसर्स एसआरएफ लिमिटेड संबद्ध देश में संबद्ध वस्तुओं के किसी निर्यातक अथवा भारत में संबद्ध वस्तुओं के किसी आयातक से संबद्ध नहीं है।

ख. आवेदक के पास समान वस्तु के भारतीय उत्पादन का 100 प्रतिशत हिस्सा भी है।

##### घ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

18. पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) में घरेलू उद्योग को इस प्रकार से परिभाषित किया गया है :

"(ख)" घरेलू उद्योग" का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा ऐसे उत्पादकों से है जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा भाग बनता है सिवाए उस स्थिति के जब ऐसे उत्पादक आरोपित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं अथवा वे स्वयं उसके आयातक होते हैं, तो ऐसे मामले में "घरेलू उद्योग" पद का अर्थ शेष उत्पादकों के संदर्भ में लगाया जा सकता है।"

19. यह आवेदन मैसर्स एसआरएफ लिमिटेड द्वारा दाखिल किया गया है। आवेदक के पास कुल भारतीय उत्पादन का 100 प्रतिशत हिस्सा है। आवेदक के पास संबद्ध वस्तुओं के भारतीय उत्पादन में अधिकांश हिस्सा है। आवेदक ने यह प्रमाणित किया है कि वह न तो संबद्ध देश में विचाराधीन उत्पाद के किसी निर्यातक या उत्पादक से संबद्ध है और न ही भारत में विचाराधीन उत्पाद के किसी आयातक से संबद्ध है।
20. प्राधिकारी ने यह पाया है कि आवेदक नियमावली के नियम 2 (ख) के तहत घरेलू उद्योग है और यह विचार किया है कि आवेदन में नियमावली के नियम 5 (3) के संदर्भ में आधार के मापदंड को पूरा किया गया है।

**ड. गोपनीयता****ड.1 अन्य हितवद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध**

21. अन्य हितवद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीयता के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं :-

- क. याचिकाकर्ता ने एक अधूरी याचिका दाखिल की है और कोई तर्कसंगत औचित्य स्पष्ट किए बिना अनुबंध- 6 (लागत संबंधी सूचना) के तहत गोपनीयता का दावा करने के लिए सूचना का पर्याप्त अगोपनीय सारांश भी प्रदान नहीं किया है।
- ख. नियमावली के अनुसार तर्क प्रदान करने के बाद गोपनीयता का दावा किया गया है। कमियां होने का दावा गलत है।

**ड.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध**

22. घरेलू उद्योग द्वारा गोपनीयता के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं :-

- क. अन्य हितवद्ध पक्षकारों द्वारा दाखिल किए गए उत्तरों में कमियां हैं और इनमें व्यापार सूचना 10/2018 का उल्लंघन किया गया है, जिससे घरेलू उद्योग को अपने अधिकारों की सुरक्षा से रोका गया है। निर्यातकों ने सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध सूचना को गोपनीय होने, कारोवारी स्वामित्व के आधारों के लिए जानबूझकर अत्यधिक गोपनीयता होने का दावा किया और यहां तक कि उत्तर प्रदान में भी विफल रहे हैं।
- ख. लागत संबंधी सूचना एक कारोवारी स्वामित्व से संबंधित सूचना है और इसे सारांश में नहीं बताया जा सकता है। घरेलू उद्योग ने अनवर जूट स्पिनिंग मिल्स लि. बनाम भारत संघ/ निर्दिष्ट प्राधिकारी मामले में सेस्टेट के आदेशों का हवाला दिया है और उन पर भरोसा किया है। निर्यातक अपने प्रकटीकरण के लिए तर्क दे रहे हैं, जबकि उन्होंने स्वयं ही प्रकटन नहीं किया है।

**ड.3 प्राधिकारी द्वारा जांच**

23. सूचना की गोपनीयता के संबंध में नियमावली के नियम 7 के तहत प्रावधान इस प्रकार है :

“गोपनीय सूचना : (1) नियम 6 के उप नियम (2), (3) और (7), नियम 12 के उप नियम (2), नियम 15 के उपनियम (4) और नियम 17 के उप नियम (4) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जांच की प्रक्रिया में नियम 5 के उप नियम (1) के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के प्रतियां या किसी पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर निर्दिष्ट प्राधिकारी को प्रस्तुत किसी अन्य सूचना के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी उसकी गोपनीयता से संतुष्ट होने पर उस सूचना को गोपनीय मानेंगे और ऐसी सूचना देने वाले पक्षकार से स्पष्ट प्राधिकार के बिना किसी अन्य पक्षकार को ऐसी किसी सूचना का प्रकटन नहीं करेंगे।

(2) निर्दिष्ट प्राधिकारी गोपनीय अधिकारी पर सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों से उसका अगोपनीय सारांश प्रस्तुत करने के लिए कह सकते हैं और यदि ऐसी सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार की राय में उस सूचना का सारांश नहीं हो सकता है तो वह पक्षकार निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस बात के कारण संबंधी विवरण प्रस्तुत करेगा कि सारांश करना संभव क्यों नहीं है।

(3) उप नियम (2) में किसी बात के होते हुए भी यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि गोपनीयता का अनुरोध अनावश्यक है या सूचना देने वाला या तो सूचना को सार्वजनिक नहीं करना चाहता है या उसकी सामान्य रूप में या सारांश रूप में प्रकटन नहीं करना चाहता है तो वह ऐसी सूचना पर ध्यान नहीं दे सकते हैं।”

24. प्राधिकारी ने हितवद्ध पक्षकारों के गोपनीयता के दावों की जांच की है और संतुष्ट होने पर गोपनीयता के संबंध में दावों की अनुमति दी है। प्राधिकारी यह विचार करते हैं कि जो सूचना गोपनीय प्रकृति की है (उदाहरण के लिए, क्योंकि इसका प्रकटीकरण होने से उसके प्रतिस्पर्धी को महत्वपूर्ण प्रतिस्पर्धात्मक फायदा मिलेगा अथवा क्योंकि उनका प्रकटीकरण होने से सूचना प्रदान करने वाले व्यक्ति पर अथवा एक ऐसे व्यक्ति पर, जिससे वह व्यक्ति सूचना अर्जित करता है, पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा) अथवा जो पक्षकारों द्वारा एक जांच में गोपनीय आधार पर प्रदान की जाती है, वह भलाई के कारण से प्राधिकारी द्वारा स्वीकार की जानी चाहिए। ऐसी सूचना को, इसे प्रस्तुत करने वाले पक्षकार की विशेष अनुमति के बिना प्रकट नहीं किया जा सकता।



25. प्राधिकारी ने आवेदक और प्रतिवादी हितवद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए गोपनीयता के दावों पर विचार किया है और इससे संतुष्ट होने पर, प्राधिकारी ने गोपनीयता के दावे की अनुमति दी है। प्राधिकारी ने सभी हितवद्ध पक्षकारों को, विभिन्न हितवद्ध पक्षकारों द्वारा नियमावली के नियम 6 (7) के तहत अनुरोध किए जाने पर, निरीक्षण के लिए, प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों का अगोपनीय पाठ उपलब्ध कराया है।

### च. विविध अनुरोध

#### च.1 अन्य हितवद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

- 26 अन्य हितवद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित विविध अनुरोध किए गए हैं :-

- क. घरेलू उद्योग वर्ष 2009 से अनुचित संरक्षण की मांग कर रहा है और उसे विदेशी उत्पादकों और निर्यातकों पर, अपना एकाधिकार बनाए रखने के एकमात्र प्रयोजन के साथ आक्षेप लगाने के लिए व्यापार उपचारी उपायों का दुरुपयोग करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। पाटनरोधी शुल्कों को आगे बढ़ाने से याचिकाकर्ता को अनुचित फायदा मिलेगा।
- ख. जांच की अवधि अक्टूबर, 2019 से मार्च, 2020 (छः माह) तक होनी चाहिए न कि अक्टूबर, 2019 से सितंबर, 2020 (12 माह) तक होनी चाहिए क्योंकि कोविड संकट ने मार्च, 2020 के बाद सभी व्यापारी क्रियाकलापों को नष्ट कर दिया है। सभी क्षेत्रों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है क्योंकि घरेलू मांग और निर्यात में तेजी से आकस्मिक गिरावट आई है।
- ग. ऐसी कोई विशेष अथवा आपवादिक परिस्थितियां नहीं हैं, जिसके कारण पाटनरोधी शुल्क को जारी रहना अपेक्षित है। ड्राई सेल बैट्रियों और नाइलोन फिलामेंट यार्न का हवाला दिया गया है, जिनमें कि शुल्क को जारी रखने की सिफारिश की गई थी क्योंकि उसने अपना अपेक्षित प्रयोजन पूरा कर लिया था।
- घ. शुल्क को आगे बढ़ाए जाने के अंतिम प्रयोक्ताओं और डाउनस्ट्रीम उद्योग पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है, जो कि मूल्यवर्धित उत्पादों के निर्माण के लिए अन्तर्राष्ट्रीय रूप से प्रतिस्पर्धी कच्ची सामग्री पर निर्भर हैं, जिनसे वे अन्य दक्षिण एशियाई देशों के साथ मुकाबला कर सकते हैं, जिनसे जीविका को काफी हानि हो रही है, मांग और आपूर्ति के बीच व्यापक अन्तर, एमएसएमई द्वारा तैयार वस्तुओं के निर्यात में कमी और उत्पाद के निर्माताओं के बीच बाजार असमानता उत्पन्न हो रही है।
- ड. व्यापार संरक्षण के माध्यम से पाटनरोधी उपायों को अनुचित रूप से लागू करना, उद्योग के संरक्षण में भूमिका नहीं निभा सकता और इससे एक अनुचित प्रतिस्पर्धी वातावरण उत्पन्न होगा और दीर्घकाल में उनके संबंधित उद्योगों के मूलभूत हितों का नुकसान पहुंचेगा।
- च. चूंकि जांच की अवधि, जहां तक संभव हो, जांच शुरू होने के बाद बंद होने की तारीख के आस-पास की होनी चाहिए, एक लम्बी अवधि का चयन किया जाना चाहिए जैसा कि कोल्ड रोलड स्टील, हीट रोलड स्टील, टायर क्योरिंग प्रेस, सीमलेस ट्यूब पाइप और लौह अथवा गैर-धातु स्टील के होलो प्रोफाइल, पॉलियूरेथिन लेदर और सौर सेलों के संबंध में हाल की जांचों में स्वीकार किया गया है। सौर सेलों की जांच शुरू करने की सूचना में यह नोट किया गया है कि 18 माह की जांच की अवधि महामारी के कारण से थी।
- छ. जांच की अवधि के बाद के आंकड़े हितवद्ध पक्षकारों को परिचालित किए जाने चाहिए, जिसके बाद दूसरी मौखिक सुनवाई का आयोजन किया जाना चाहिए। चूंकि शुल्क को दिनांक 10 जनवरी, 2022 तक आगे बढ़ाया गया है, अतः संशोधित आयातों की मांग की जानी चाहिए और जांच की अवधि के बाद के आंकड़ों का विश्लेषण किया जाना चाहिए।
- ज. यह आरोप कि चीन के उत्पादक शुल्क को आमेमित कर रहे हैं, आधारहीन है। संबद्ध आयातों में गिरावट आना इसका प्रमाण है। इसके साथ ही, विगत जांचों में मार्जिन, वर्तमान मामले की तरह से उपलब्ध तथ्यों के आधार पर नहीं था। आमेमित को केवल मार्जिन की तुलना करके ही निर्धारित नहीं किया जा सकता। इसके लिए पर्याप्त साक्ष्य होने चाहिए। गैर-संबद्ध देश से पहुंच कीमत कमतर रही हैं।

- झ. शुल्क को बढ़ाने के लिए दावा अस्वीकार किया जाना चाहिए क्योंकि घरेलू उद्योग को निरंतर क्षति नहीं हुई है। विगत जांच में मार्जिन उपलब्ध तथ्यों के आधार पर थे, न कि वर्तमान मामले की तरह। अतः यह शुल्क को बढ़ाने के लिए एक आधार नहीं हो सकता।

## च.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

27. घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित विविध अनुरोध किए गए हैं :-

- क. चीन के उत्पादक पहले लगाए गए पाटनरोधी शुल्क को आमेलित कर रहे हैं, जैसाकि विगत निर्णायक समीक्षा की तुलना में अत्यंत अधिक क्षति मार्जिन और पाटन मार्जिन द्वारा प्रमाणित है।
- ख. शुल्कों की मात्रा में वृद्धि पर विचार किया जाना चाहिए, क्योंकि निर्यातकों ने भारत में विचाराधीन उत्पाद के पाटन में तेजी लाई है और पाटनरोधी शुल्क को समाप्त करने से घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति होगी।
- ग. पाटनरोधी शुल्क एक संरक्षण नहीं है और यह केवल अनुचित कीमत का सामना करने के लिए एक उपाय है। घरेलू उद्योग को अधिक संरक्षण नहीं है।
- घ. पाटनरोधी शुल्क का विस्तार करने की मांग इसलिए की गई है क्योंकि निरंतर पाटन हो रहा है और इसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को क्षति तथा साथ ही शुल्कों के समाप्त होने की स्थिति में क्षति की संभावना हो रही है। यह जांच प्राधिकारी द्वारा केवल याचिकाकर्ता के दावों से प्रथम दृष्टया संतुष्ट होने के बाद ही शुरू की गई थी। निर्यातक आदतन पाटित कीमतों पर विचाराधीन उत्पाद का निर्यात कर रहे हैं।
- ड. एक निर्णायक समीक्षा में किसी कारणात्मक संबंध की कोई जरूरत नहीं है। पाटन, क्षति का प्राथमिक कारण नहीं हो सकता। संबद्ध आयातों की मात्रा और बाजार अंश में कोविड की अवधि के दौरान वृद्धि हुई है, जबकि घरेलू उद्योग के बाजार अंश में विगत वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में गिरावट आई है।
- च. जहां तक जांच की अवधि का संबंध है, जांच की अवधि नियम 3 (क) को देखते हुए अक्टूबर, 2019 से मार्च, 2020 तक की अवधि नहीं हो सकती, क्योंकि जांच की अवधि छः माह पुरानी होनी चाहिए।
- छ. चूंकि संबद्ध देश से पाटन में, विगत जांचों की तुलना में वृद्धि हुई है, पाटनरोधी शुल्कों में वृद्धि की जानी चाहिए। प्राधिकारी ने यूएस, कनाडा, यूरोपीय संघ और ब्राजील में प्राधिकारियों के साथ-साथ शुल्कों की अवधि के बावजूद, विभिन्न निर्णायक समीक्षा जांचों में शुल्कों की सिफारिश की है। ड्राई सेल बैट्रियों के मामले के तथ्य पूरी तरह से अलग थे और इसका तर्क आगामी मामलों में लागू नहीं हो सकता था।
- ज. किसी भी प्रयोक्ता अथवा आयातक ने जांच में भाग नहीं लिया था, क्योंकि पाटनरोधी शुल्क से उन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा। घरेलू उद्योग के पास भारतीय मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त क्षमताएं हैं और इस प्रकार डाउनस्ट्रीम उद्योग के समक्ष कभी भी आपूर्ति की कमी की समस्या नहीं आईगी। किसी भी हितवद्ध पक्षकार ने कथित पाटन के संगत साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए हैं, जबकि 10 वर्षों से शुल्क लागू रहे हैं।
- झ. जहां तक जांच की अवधि के बाद के आंकड़ों का संबंध है, जांच की अवधि के बाद की सूचना किसी निर्णायक समीक्षा जांच में एक अनिवार्य अपेक्षा नहीं है। प्राधिकारी ने पाटन की संभावना और उसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को क्षति को, कई विगत मामलों में जांच की अवधि के बाद के आंकड़ों पर विचार किए बिना साबित किया है।

## च.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

28. प्राधिकारी ने पक्षकारों के अनुरोधों पर विचार किया है और यह निर्धारित किया है कि :-

- क. जहां तक अत्यधिक संरक्षण का संबंध है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि कोई निर्णायक समीक्षा कितनी बार आयोजित की जा सकती है और पाटन रोधी शुल्क को आगे बढ़ाया जा सकता है, इस पर कोई प्रतिबंध नहीं है। नियमों में प्राधिकारी से यह निर्धारित किए जाने की अपेक्षा है कि क्या पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने से घरेलू उद्योग को पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है। यह भी नोट किया गया है कि पाटनरोधी शुल्क का विस्तार करने की सिफारिश केवल तभी की गई है जब अपेक्षित कानूनी अपेक्षाएं पूरी की गई हों। यह भी नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग 71 उत्पादों के उत्पादन में शामिल है और वर्तमान में पाटनरोधी शुल्क केवल चार उत्पाद पर ही लगाया गया है।

ख. जहां तक प्रयोक्ता उद्योग पर पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव के तर्क का संबंध है, यह नोट किया जाता है कि किसी भी प्रयोक्ता/ प्रयोक्ता संघ ने वर्तमान जांच में सहयोग नहीं किया है। इससे यह धारणा उत्पन्न होती है कि भारत में प्रयोक्ता उद्योग पर संबद्ध वस्तुओं के संबंध में पाटनरोधी शुल्क को आगे बढ़ाने से प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ रहा है। यद्यपि, संबद्ध वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क 10 वर्षों से अधिक समय से लागू है, लेकिन यह दर्शाने के लिए कोई साक्ष्य नहीं है कि इससे संबद्ध आयातों में कटौती हुई है, जिसके कारण भारत में प्रयोक्ता उद्योग अथवा उपभोक्ताओं पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। इसके अलावा, यहां तक कि यदि यह विचार किया जाता है कि पाटनरोधी शुल्क को आगे बढ़ाए जाने से, संबद्ध वस्तुओं का उपयोग करके निर्मित किए गए उत्पादों के कीमत संबंधी स्तरों पर प्रभाव पड़ सकता है। यह नोट किया जाता है कि भारतीय बाजार में उचित प्रतिस्पर्धा पाटनरोधी शुल्क के कारण कभी नहीं आएगी। पाटनरोधी उपायों को लागू करने का उद्देश्य, घरेलू उद्योग की गिरावट को रोकने के लिए और संबद्ध वस्तुओं के उपभोक्ताओं को व्यापक चयन की उपलब्धता बरकरार रखने में मदद करने के लिए पाटन की प्रक्रियाओं से प्राप्त अनुचित लाभों को दूर करना है।

ग. जहां तक जांच की अवधि का संबंध है, नियमावली में यह प्रावधान है :-

जांच की अवधि -

(i) जांच शुरू करने की तारीख की स्थिति के अनुसार छ: माह से अधिक पुरानी नहीं होगी;

(ii) सामान्यतः बारह माह की अवधि की होगी और लिखित में दर्ज किए गए कारणों से, निर्दिष्ट प्राधिकारी न्यूनतम छ: माह अथवा अधिकतम अठारह माह की अवधि पर विचार कर सकते हैं।

घ. प्राधिकारी ने वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए जांच की अवधि (पीओआई) के लिए 1 अक्टूबर, 2019 से 30 सितंबर, 2020 (12 माह) के रूप में विचार किया है। क्षति जांच की अवधि पर वर्ष 2017-18, 2018-19, 2019-20 और जांच की अवधि के रूप में विचार किया गया है। जांच की अवधि उपयुक्त पाई गई है और पाटनरोधी नियमावली के अनुसार है।

ड. जहां तक जांच की अवधि के बाद के आंकड़ों का संबंध है, यह नोट किया जाता है कि जांच की अवधि के बाद के आंकड़े एक निर्णायक समीक्षा जांच में अनिवार्य नहीं हैं। प्राधिकारी द्वारा नीचे दिए गए अनुसार किए गए विश्लेषण की संभावना, यह विश्लेषण करने के लिए पर्याप्त हैं कि संबद्ध वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क को आगे बढ़ाने की जरूरत है।

## छ. पाटन का आकलन – कार्य-प्रणाली और मापदंड

### सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन का निर्धारण

#### छ.1 अन्य हितवद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

29. अन्य हितवद्ध पक्षकारों द्वारा सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं :-

क. इस मामले में, इस बात पर ध्यान दिए बिना सामान्य मूल्य की गणना में प्रतिनिधिक देश की कार्य-प्रणाली का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए कि क्या चीन जन.गण. को एक बाजार अर्थव्यवस्था देश के रूप में विचार किया गया है। भारत के पास गैर-बाजार अर्थव्यवस्था कार्य-प्रणाली का उपयोग करके सामान्य मूल्य की गणना करने का कोई आधार नहीं है।

ख. भारत 'संधि का पालन' करने के लिए बाध्य है और संगत करारों के तहत अपनी बाध्यता को पूरा करना चाहिए तथा संगत घरेलू विनियमों में संशोधन करके चीन जन. गण. को पूर्ण बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा प्रदान करे।

ग. प्राधिकारी सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए यूएसए से आयात संबंधी कीमत का उपयोग नहीं कर सकते क्योंकि यह प्राधिकारी के विगत जांच परिणामों के खिलाफ जाएगा। इस प्रकार की जांच प्रदान की जानी चाहिए कि क्या ऐसी कार्य-प्रणाली, जिसे पहले अस्वीकार किया जा चुका है, आगे की समीक्षाओं में अपनाई जा सकती है।

घ. घरेलू उद्योग यह स्पष्ट करने में विफल रहा है कि क्या कारखाना बाह्य सामान्य मूल्य निकालने के लिए आयात कीमत (सीआईएफ) के लिए क्या समायोजन किए गए थे।

ड. पाटन मार्जिन का दावा बढ़ा-चढ़ाकर दिखाया गया है और गलत है, यहां तक कि तब भी, जब सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए आधार के संबंध में घरेलू उद्योग का दावा स्वीकार कर लिया गया है।

**छ.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध**

30. घरेलू उद्योग द्वारा सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं :-

- क. प्राधिकारी केवल तभी सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए अनुबंध-1 के पैरा 1-6 का अनुसरण करेंगे, यदि चीन जन. गण. से प्रतिवादी कंपनियां यह साबित करती हैं कि उनकी लागत और कीमत संबंधी सूचना इस प्रकार की है कि कोई व्यक्तिगत सामान्य मूल्य और पाटन मार्जिन निर्धारित किया जा सकता है। यदि चीन जन. गण. से प्रतिवादी कंपनियां यह प्रदर्शित करने के लिए समर्थ नहीं हैं कि उनकी लागतों और कीमत की सूचना अपनाई जा सकती है, अतः प्राधिकारी एक व्यक्तिगत पाटन मार्जिन का दावा अस्वीकार करेंगे।
- ख. जब तक चीन जन. गण. में उत्पादक/निर्यातक यह साबित नहीं कर देते कि उनकी लागतें और कीमतें विश्वसनीय हैं, उनकी घरेलू लागतें तथा कीमतें सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए स्वीकार नहीं की जा सकती। उत्पादकों और निर्यातकों की यह प्रदर्शित करने में विफलता को देखते हुए कि वे बाजार अर्थव्यवस्था स्थिति के तहत संचालित हो रहे हैं, सामान्य मूल्य का निर्धारण, पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 के प्रावधानों के अनुसार किया जाना चाहिए।
- ग. चीन जन. गण. को मात्र घरेलू विनियमों के आधार पर एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में नहीं माना जा रहा है, बल्कि चीन के एक्सेसन प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15 (क) (i) के आधार पर भी माना जा रहा है, जिसने यहां तक कि दिनांक 11 दिसंबर, 2016 के बाद भी प्रचालन करना जारी रखा है।
- घ. चीन जन. गण. एक्सेसन प्रोटोकॉल के तहत अपनी बाध्यताओं को पूरा करने में विफल रहा है और बाजार द्वारा स्थापित की जाने वाली कीमतों की अनुमति देने के लिए बदलावों को हटाने में विफल रहा है, जिसके परिणामस्वरूप यहां तक कि यूएसए और यूरोपीय संघ सहित अन्य डब्ल्यूटीओ सदस्यों ने चीन जन. गण. के साथ एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में व्यवहार करना जारी रखा।
- ड. आवेदक का यह दावा है कि चूंकि सामान्य मूल्य का निर्धारण, एक बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में इस कारण से कीमत अथवा निर्मित मूल्य के आधार पर नहीं किया जा सकता कि संगत सूचना सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है, अतः चीन जन. गण. के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण, एक बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश से भारत सहित अन्य देश को कीमत के आधार पर किया जाना चाहिए। आवेदक ने भारत में यूएसए से संबद्ध वस्तुओं की, आयात कीमत का उपयोग किया है।
- च. यूएसए एक उपयुक्त बाजार अर्थव्यवस्था वाला तीसरा देश है, क्योंकि यह भारत में संबद्ध वस्तुओं का एक बड़ी मात्रा के साथ एक बड़ा उत्पादक और निर्यातक है और चीन जन.गण. अर्थव्यवस्था और विकास के स्तर में यूएसए के साथ मुकाबले में है। यूएसए में उत्पादित संबद्ध वस्तुएं भी चीन जन. गण. और भारत में उत्पादित वस्तुओं के समान वस्तु हैं जिनकी समान विनिर्माण प्रक्रिया है। यूएसए से भारत को निर्यात भी सामान्य व्यापार प्रक्रिया में है।
- छ. आवेदक ने सीआईएफ कीमत को लिया है और उसे समुद्री मालभाड़ा, स्वदेशी मालभाड़ा, समुद्री बीमा, बंदरगाह व्यय, कमीशन, बैंक प्रभारों और वेट के लिए उसका समायोजन किया है ताकि निर्यात कीमत का निर्धारण हो सके।
- ज. पाटन मार्जिन न केवल न्यूनतम से अधिक है बल्कि संबद्ध देश के लिए भी अधिक है।
- झ. कुइतुन जिनजियांग कैमिकल इंडस्ट्री कं. लि. बनाम भारत संघ मामले में सेस्टेट ने यह पाया है कि विकास का स्तर, सामान्य मूल्य के रूप में एक प्रतिनिधि देश की आयात कीमत पर विचार रकते समय एक संगत विचार नहीं है। निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा यूएसए की आयात कीमत को सामान्य मूल्य के रूप में अस्वीकार किए जाने में विगत के जांच परिणाम सेस्टेट के आदेश के खिलाफ हैं और इसीलिए प्राधिकारी पर बाध्यकारी नहीं हैं।

**छ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच**

31. धारा 9क (1) (ग) के तहत, किसी वस्तु के संबंध में सामान्य मूल्य से तात्पर्य है कि :

- (i) व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की तुलनीय कीमत जब वह उप नियम (6) के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित निर्यातक देश या क्षेत्र में खपत के लिए नियत हो, अथवा

(ii) जब निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की कोई विक्री न हुई हो अथवा जब निर्यातक देश या क्षेत्र की बाजार विशेष की स्थिति अथवा उसके घरेलू बाजार में कम विक्री मात्रा के कारण ऐसी विक्री की उचित तुलना न हो सकती हो तो सामान्य मूल्य निम्नलिखित में से कोई एक होगा:-

(क) समान वस्तु की तुलनीय प्रतिनिधिक कीमत जब उसका निर्यात उप-धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार निर्यातक देश या क्षेत्र से या किसी उचित तीसरे देश से किया गया हो; अथवा उप-धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित प्रशासनिक, विक्री और सामान्य लागत एवं लाभ हेतु उचित वृद्धि के साथ उद्गम वाले देश में उक्त वस्तु की उत्पादन लागत;

(ख) वशर्ते यदि उक्त वस्तु का आयात उद्गम वाले देश से भिन्न किसी देश से किया गया है और जहां उक्त वस्तु को निर्यात के देश से होकर केवल यानांतरण किया गया है अथवा ऐसी वस्तु का उत्पादन निर्यात के देश में नहीं होता है, अथवा निर्यात के देश में कोई तुलनीय कीमत नहीं है, वहां सामान्य मूल्य का निर्धारण उद्गम वाले देश में उसकी कीमत के संदर्भ में किया जाएगा।

32. प्राधिकारी ने संबद्ध देश से ज्ञात उत्पादकों/ निर्यातकों को यह परामर्श देते हुए प्रश्नावली भेजी कि वे प्राधिकारी द्वारा निर्धारित रूप में और तरीके से सूचना प्रदान करें। निम्नलिखित उत्पादकों/ निर्यातकों ने निर्धारित प्रश्नावली उत्तर दाखिल करके इस जांच में सहयोग किया है :-

- i. मै. सिनकेम इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन केमिकल्स (ताइकैंग) कं. लि. (उत्पादक/ निर्यातक)
- ii. मै. शांक्सी सिनोकेम लानतियान न्यू केमिकल मैटिरियल कं. लि. (उत्पादक/ निर्यातक)
- iii. मै. शानडोंग डोंगहुई केमिकल कं. लि. (उत्पादक/ निर्यातक)
- iv. मै. झेजियांग सनमेई केमिकल इन्ड. कं. लि. (उत्पादक/ निर्यातक)
- v. मै. झेजियांग क्यूहुआ फ्लुओर-केमिस्ट्री कं. लि. (उत्पादक/ निर्यातक)
- vi. मै. झेजियांग क्यूझोऊ लियानझोउ रेफ्रिजरेट्स कं. लि. (उत्पादक/ निर्यातक)
- vii. मै. सिनोकेम लानतियान ट्रेडिंग कं. लि. (घरेलू विक्रेता)
- viii. मै. सिनोकेम जियान जिनकूल न्यू केमिकल मैटिरियल्स कं. लि. (व्यापारी)
- ix. मै. सिनोकेम लानतियान फ्लुओरो मैटिरियल्स कं. लि. (घरेलू विक्रेता)
- x. मै. सिनोकेम मॉडर्न इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन केमिकल (जियान) कं. लि. (पूर्व उत्पादक)

### चीन के उत्पादकों के लिए बाजार अर्थव्यवस्था की स्थिति

33. डब्ल्यूटीओ में चीन के एक्सेसन प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15 में निम्नानुसार प्रावधान है :

“जीएटीटी 1994 का अनुच्छेद VI, टैरिफ और व्यापार संबंधी सामान्य करार, 1994 (“पाटनरोधी करार”) के अनुच्छेद VI के कार्यान्वयन संबंधी करार और एससीएम करार एक डब्ल्यूटीओ सदस्य में चीन के मूल के आयातों की संलिप्तता की कार्यवाहियों में लागू होंगे जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:-

(क) जीएटीटी 1994 के अनुच्छेद- VI और पाटनरोधी करार के तहत कीमत तुलनात्मकता का निर्धारण करने में, आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य या तो जांचाधीन उद्योग के लिए चीन की कीमतों अथवा लागतों का उपयोग करेंगे अथवा उस पद्धति का उपयोग करेंगे, जो निम्नलिखित नियमों के आधार पर घरेलू कीमतों या चीन में लागतों के साथ सख्ती से तुलना करने पर आधारित नहीं है:

(i) यदि जांचाधीन उत्पादक साफ-साफ यह दिखा सकते हैं कि समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग में उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और विक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां रहती हैं तो निर्यात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य मूल्य की तुलनीयता का निर्धारण करने में जांचाधीन उद्योग के लिए चीन के मूल्यों अथवा लागतों का उपयोग करेगा।

- (ii) आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य उस पद्धति का उपयोग कर सकता है जो चीन में घरेलू कीमतों अथवा लागतों के साथ सख्त अनुपालन पर आधारित नहीं है, यदि जांचाधीन उत्पादक साफ-साफ यह नहीं दिखा सकते हैं कि उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग हैं।
- (ख) एससीएम समझौते के पैरा II, III और V के अंतर्गत कार्यवाहियों में अनुच्छेद 14(क), 14(ख), 14(ग) और 14(घ) में निर्धारित राजसहायता को बताते समय एससीएम समझौते के प्रासंगिक प्रावधान लागू होंगे, तथापि, उसके प्रयोग करने में यदि विशेष कठिनाईयां हों, तो आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य राजसहायता लाभ की पहचान करने और उसको मापने के लिए तब पद्धति का उपयोग कर सकते हैं जिसमें उस संभावना को ध्यान में रखती है और चीन में प्रचलित निबंधन और शर्तें उपयुक्त बेंचमार्क के रूप में सदैव उपलब्ध नहीं हो सकती हैं। ऐसी पद्धतियों को लागू करने में, जहां व्यवहार्य हो, आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य के द्वारा चीन से बाहर प्रचलित निबंधन और शर्तों का उपयोग के बारे में विचार करने से पूर्व ऐसी विद्यमान निबंधन और शर्तों को ठीक करना चाहिए।
- (ग) आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य उप-पैरा (क) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को पाटनरोधी कार्य समिति के लिए अधिसूचित करेगा तथा उप पैराग्राफ (ख) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को कमिटी ऑन सब्सिडीज और काउंटर वेलिंग मैसर्स के लिए अधिसूचित करेगा।
- (घ) आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य को राष्ट्रीय कानून के तहत चीन ने एक बार यह सुनिश्चित कर लिया है कि यह एक बाजार अर्थव्यवस्था है, तो उप पैराग्राफ के प्रावधान (क) समाप्त कर दिए जाएंगे, वशर्तें आयात करने वाले सदस्य के राष्ट्रीय कानून में प्राप्ति की तारीख के अनुरूप बाजार अर्थव्यवस्था संबंधी मानदंड हो। किसी भी स्थिति में उप पैराग्राफ (क) (III) के प्रावधान प्राप्ति की तारीख के बाद 15 वर्षों में समाप्त होंगे। इसके अलावा, आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य के राष्ट्रीय कानून के अनुसरण में चीन के द्वारा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां एक विशेष उद्योग अथवा क्षेत्र में प्रचलित हैं, उप पैराग्राफ (क) के गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के प्रावधान उस उद्योग अथवा क्षेत्र के लिए आगे लागू नहीं होंगे।"

34. यह नोट किया जाता है कि जबकि अनुच्छेद 15 (क) (ii) में दिए गए प्रावधान 11 दिसंबर, 2016 को समाप्त हो गए हैं, लेकिन ऐक्सेस प्रोटोकॉल की बाध्यता 15(क) (i) के साथ पठित डब्ल्यूटीओ के अनुच्छेद 2.2.1.1. के तहत प्रावधान में नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 8 में विनिर्दिष्ट मानदंड अपेक्षित हैं, जिन्हें बाजार अर्थव्यवस्था के दर्जे का दावा करने के संबंध में अनुपूरक प्रश्नावली में प्रदान की जाने वाली सूचना/ आंकड़ों के ज़रिए पूरा किया जाना है। यह नोट किया जाता है कि चूंकि चीन जन.गण. से प्रतिवादी उत्पादकों/ निर्यातकों ने निर्धारित रूप में और निर्धारित तरीके से इस प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है। अतः सामान्य मूल्य की गणना, नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 के प्रावधानों के अनुसार की जानी है।

35. संबद्ध देश से सभी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत का निर्धारण नीचे दिए अनुसार किया गया है :-

#### छ.4 सामान्य मूल्य का निर्धारण

36. नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 नीचे दिए अनुसार पढ़ा जाता है :

"गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देशों से आयात के मामले में, उचित लाभ मार्जिन को शामिल करने के लिए भारत में समान उत्पाद के लिए वास्तविक रूप से भुगतान किया गया अथवा भुगतान योग्य, आवश्यकतानुसार पूर्णतया समायोजित कीमत रहित, सामान्य मूल्य का निर्धारण तीसरे देश के बाजार अर्थव्यवस्था में कीमत अथवा परिकलित मूल्य के आधार पर अथवा भारत सहित ऐसे किसी तीसरे देश से अन्य देशों के लिए कीमत अथवा जहां यह संभव नहीं है, या किसी अन्य उचित आधार पर किया जाएगा। संबद्ध देश के विकास के स्तर तथा संबद्ध उत्पाद को देखते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा यथोचित पद्धति द्वारा एक समुचित बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश का चयन किया जाएगा और चयन के समय पर उपलब्ध कराई गई किसी विश्वसनीय सूचना पर यथोचित रूप से विचार किया जाएगा। बाजार अर्थव्यवस्था वाले किसी अन्य तीसरे देश के संबंध में किसी समयानुरूपी मामले में की जाने वाली जांच के मामले में जहां उचित हों, समय-सीमा के भीतर कार्रवाई की जाएगी। जांच से संबंधित पक्षकारों को किसी अनुचित विलंब के बिना बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के चयन के विशेष में सूचित किया जाएगा और अपनी टिप्पणियां देने के लिए एक समुचित समयावधि प्रदान की जाएगी।"

37. प्राधिकारी नोट करते हैं कि किसी उपयुक्त बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में उत्पाद की कीमत अथवा निर्मित मूल्य न तो प्राधिकारी द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं और न ही किसी अन्य पक्षकार द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं और ये किसी सार्वजनिक स्रोत से प्राधिकारी के पास उपलब्ध हैं। यह नोट किया जाता है कि हितवद्ध पक्षकारों ने ऐसी कोई सत्यापन किए जाने योग्य सूचना प्रदान नहीं की है, जिसे प्राधिकारी द्वारा स्वीकार किया जा सके। तथापि, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि सत्यापन योग्य साक्ष्य और प्रकाशित सूचना यूएसए से भारत को संबद्ध वस्तुओं की आयात कीमत के संबंध में उपलब्ध हैं। यूएसए भी भारत में संबद्ध वस्तुओं का एक बड़ा उत्पादक और निर्यातक है और समान निर्माण प्रक्रिया शामिल है। इसके अलावा, यूएसए से आयातों में संबद्ध देश के बाद संबद्ध वस्तुओं के दूसरे सबसे अधिक आयातक शामिल हैं। अतः प्राधिकारी यूएसए को चीन जन. गण. के लिए एक उपयुक्त प्रतिनिधिक देश मानते हैं। इसके साथ ही, भारत को बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश से आयात कीमत के आधार पर सामान्य मूल्य का निर्धारण करने पर कुड़तुन जिनजियांग कैमिकल इंडस्ट्री के मामले में सेस्टेट द्वारा रोक लगा दी गई थी। यूएसए से भारत में आयातित संबद्ध वस्तुएं संबद्ध देश में और भारत में उत्पादित वस्तुओं के समान वस्तुएं हैं। इस प्रकार से निर्धारित किया गया सामान्य मूल्य नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दिया गया है।

#### छ.5 निर्यात कीमत का निर्धारण

##### **सिनोकेम इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन केमिकल्स (टाइकैंग) कंपनी लि. (उत्पादक) और शांक्सी सिनोकेम लानतियान न्यू केमिकल मैटिरियल कं. लि. (उत्पादक)**

38. जांच की अवधि के दौरान, सिनोकेम इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन केमिकल्स (टाइकैंग) कंपनी लि. ने भारत को पैक किए गए और बिना पैक किए गए रूपों में, दोनों में \*\*\* यूएस डॉलर के इनवायस मूल्य के \*\*\* मी. टन विचाराधीन उत्पाद का निर्यात किया है, जिसमें से \*\*\* मी. टन विचाराधीन उत्पाद भारत को सिनोकेम इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन केमिकल्स (टाइकैंग) कं. लि. द्वारा एक अन्य उत्पादक नामतः हनीवेल ड्रेडिंग (शंघाई) कं. लि. चीन जन. गण. के माध्यम से निर्यात किया गया है। तथापि, इस व्यापारी ने प्राधिकारी के पास अपना उत्तर दाखिल नहीं किया है और इसीलिए प्राधिकारी ने उत्पादक के लिए निर्यात कीमत का अन्तिम निर्धारण करने के लिए इस व्यापारी द्वारा किए गए निर्यातों के लिए सर्वोत्तम उपलब्ध तथ्यों का प्रयोग किया है।
39. यह भी नोट किया जाता है कि जांच की अवधि के दौरान, शांक्सी सिनोकेम लान्तिन न्यू कैमिकल मैटिरियल कं. लि. जो कि संबद्ध वस्तुओं का एक उत्पादक/ निर्यातक है, ने भारत को बिना पैक किए गए रूप में \*\*\* यूएस डॉलर इनवायस मूल्य के \*\*\* मी. टन विचाराधीन उत्पाद का सीधे निर्यात किया है। शांक्सी सिनोकेम न्यू कैमिकल मैटिरियल कं. लि., सिनोकेम इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन कैमिकल्स (ताइकैंग) कं. लि. की एक संगत कंपनी है।
40. सिनोकेम इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन कैमिकल्स (ताइकैंग) कं. लि और शांक्सी सिनोकेम न्यू कैमिकल मैटिरियल कं. लि., चीन जन. गण. ने समुद्री मालभाड़ा, बीमा, स्वदेशी यातायात, बंदरगाह और अन्य संगत व्यय, ऋण लागत और पैकिंग व्यय, जिसकी अनुमति प्रदान की गई है, के संबंध में समायोजनों का दावा किया है। तदनुसार, सिनोकेम इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन कैमिकल्स (ताइकैंग) कं. लि और शांक्सी सिनोकेम न्यू कैमिकल मैटिरियल कं. लि., चीन जन. गण. के लिए कारखाना बाह्य स्तर पर भारित औसत निर्यात कीमत का निर्धारण किया गया है और इसे नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है।

##### **शानडोंग डोंगयुई केमिकल कं. लि. (उत्पादक)**

41. जांच की अवधि के दौरान शानडोंग डोंगयुई केमिकल कं. लि. ने \*\*\* यूएस डॉलर के इनवायस मूल्य के पैक किए गए रूप में भारत को \*\*\* मी. टन विचाराधीन उत्पाद का सीधे निर्यात किया है। शानडोंग डोंगयुई केमिकल कं. लि. ने समुद्री मालभाड़ा, स्वदेशी यातायात, बंदरगाह और अन्य संगत व्यय, पैकिंग व्यय तथा बैंक प्रभारों, जिनकी अनुमति प्रदान कर दी गई है, के संबंध में समायोजनों का दावा किया है। तदनुसार, शानडोंग डोंगयुई केमिकल कं. लि. के लिए कारखाना बाह्य स्तर पर निवल निर्यात कीमत का निर्धारण किया गया है और उसे नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है।

##### **झेजियांग सनमेई केमिकल इन्ड. कं., लि. (उत्पादक)**

42. जेजियांग सनमेई केमिकल इन्ड. कं., लि. संबद्ध वस्तुओं का एक उत्पादक व निर्यातक है, जिसने जांच की अवधि में बिना पैक किए गए रूप में सीधे भारत को मी. टन संबद्ध वस्तुओं का निर्यात किया है। समुद्री मालभाड़ा, समुद्री बीमा, स्वदेशी यातायात, बंदरगाह व्यय, जिसकी अनुमति प्रदान कर दी गई है, के संबंध में समायोजनों का दावा किया गया है। तदनुसार, कारखाना बाह्य स्तर पर निवल निर्यात कीमत का निर्धारण किया गया है और उसे नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है।

**झेजियांग क्यूहुआ फ्लूओर-केमिस्ट्री कं. लि. और झेजियांग क्यूहोऊ लियांगझोऊ रेफिजरेट्स कं., लि.**

43. झेजियांग क्यूहुआ फ्लूओर-केमिस्ट्री कं. लि. ("क्यूहुआ") और इसकी संगत कंपनी, नामतः झेजियांग क्यूहोऊ लियांगझोऊ रेफिजरेट्स कं., लि. ("लियांगझोऊ"), चीन जन.गण. में संबद्ध वस्तुओं के उत्पादक हैं और संबद्ध वस्तुओं को भारत में सीधे असंगत ग्राहकों को निर्यात किया है।
44. जांच की अवधि के दौरान, क्यूहुआ और लियांगझोऊ ने क्रमशः \*\*\* मी. टन और \*\*\* मी. टन संबद्ध वस्तुओं का पैक किए गए रूप में और बिना पैक किए गए रूप में, दोनों में भारत में असंबद्ध ग्राहकों को सीधे निर्यात किया है। प्रतिवादी उत्पादकों/निर्यातकों ने समुद्री माल भाड़ा, बीमा, स्वदेशी यातायात, हैंडलिंग प्रभारों, बैंक प्रभारों तथा ऋण लागत, जिसके लिए प्राधिकारी द्वारा अनुमति प्रदान कर दी गई है, के संबंध में समायोजनों का दावा किया है। क्यूहुआ और लियांगझोऊ की इस प्रकार से निर्धारित की गई कारखाना बाह्य निर्यात कीमत नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाई गई है।

**चीन जन.गण से असहयोगी निर्यातक**

45. चीन जन. गण. से अन्य निर्यातकों के संबंध में निर्यात कीमत का निर्धारण, नियमावली के नियम 6(8) के प्रावधानों के अनुसार, उपलब्ध तथ्यों के तहत किया गया है। इस प्रयोजन के लिए, प्राधिकारी ने डीजीसीआई एंड एस में यथा सूचित आयातों और असहयोगी उत्पादक तथा निर्यातकों के प्रभावली उत्तरों पर विचार किया है।

**छ.6 पाटन मार्जिन का निर्धारण**

46. यह नोट किया जाता है कि संबद्ध जांच में कई सहयोगी उत्पादक और निर्यातक एक दूसरे से संबद्ध हैं और संगत कंपनियों का एक समूह है। प्राधिकारी की यह संगत प्रथा रही है कि संगत निर्यात करने वाले उत्पादकों और निर्यातकों को पाटन मार्जिन का निर्धारण करने के लिए एक ही संस्था के रूप में माना जाए और इस प्रकार से उनके लिए एक ही पाटन मार्जिन स्थापित किया जाना है। यह विशेष रूप से किया जाता है, क्योंकि व्यक्तिगत पाटन मार्जिन की गणना किए जाने से पाटनरोधी उपायों की प्रवंचना को बढ़ावा मिल सकता है, इस प्रकार से संगत निर्यात करने वाले उत्पादकों को सबसे कम व्यक्तिगत पाटन मार्जिन वाली कंपनी के माध्यम से भारत को उनके निर्यातों को चलाने के लिए उन्हें अप्रभावी बनाया गया है।
47. संबद्ध वस्तुओं के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत पर विचार करके संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के लिए पाटन मार्जिन का निर्धारण किया गया है, जो इस प्रकार है :-

क्र. सं.	उत्पादक	सीएनवी (यूएस डॉलर/ मी. टन)	एनईपी (यूएस डॉलर/ मी. टन)	पाटन मार्जिन (यूएस डॉलर/ मी. टन)	पाटन मार्जिन (%)	पाटन मार्जिन (%)
1.	सिनोकेम इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन केमिकल्स (टाइकैंग) क. लि. और शांक्सी सिनोकेम लानतियान न्यू केमिकल मैटिरियल कं. लि.	***	***	***	***	60-70
2.	शानडोंग डोंगयुई केमिकल कं.लि.	***	***	***	***	110-120
3.	झेजियांग सनमेई केमिकल इन्ड.कं., लि.	***	***	***	***	50-60
4.	झेजियांग क्यूहुआ फ्लूओर-केमिस्ट्री कं. लि. और झेजियांग क्यूहोऊ लियांगझोऊ रेफिजरेट्स कं. लि.	***	***	***	***	45-55
5.	अन्य सभी	***	***	***	***	125-135

**ज. क्षति का आकलन और कारणात्मक संबंध****ज.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध**



48. अन्य हितवद्ध पक्षकारों द्वारा क्षति और कारणात्मक संबंध के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं :-

- क. याचिकाकर्ता ने, जैसा कि वार्षिक रिपोर्ट 2019-20 में उल्लेख किया गया है, दाहेज साइट के अस्थायी रूप से शटडाउन के संबंध में सूचना पर रोक लगाई है। अतः क्षति का कारण शटडाउन होना है न कि चीन जन.गण. से किए गए आयात हैं।
- ख. याचिकाकर्ता का दावा उनकी 49वीं रिपोर्ट में दी गई सूचना के विपरीत है।
- ग. याचिकाकर्ता ने अनुचित संरक्षण प्राप्त करने के लिए बनावटी क्षति का दावा किया है। विचाराधीन उत्पाद के आयातों में वृद्धि होने का दावा आधारहीन है। संबद्ध देश से आयात की मात्रा में गिरावट, अन्य देशों से आयात की मात्रा में गिरावट से अधिक है। घरेलू उद्योग चीन जन.गण. को लक्ष्य बना रहा है, जबकि क्षति अन्य देशों से आयातों के कारण से भी हुई हो सकती है।
- घ. जांच की अवधि में, कोविड-19 के कारण से कुल मांग के साथ घरेलू उद्योग की विक्रियों में गिरावट हुई है, जैसा कि घरेलू उद्योग द्वारा मौखिक सुनवाई में पहले ही स्वीकार किया जा चुका है। आयातों के कारण से घरेलू उद्योग को बड़ी क्षति नहीं हो रही है। इसके अलावा, घरेलू उद्योग के बाजार अंश में वृद्धि हुई है जबकि संबद्ध आयातों और अन्य देशों से आयातों में गिरावट आई है।
- ङ. जांच की अवधि के दौरान हानि का दावा कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट के साथ मेल नहीं खाता और इसीलिए इसकी पूरी तरह से जांच की जानी चाहिए।
- च. यदि कोई हानि है भी, तो वह याचिकाकर्ता की क्षमताओं का कम उपयोग होने तथा कैप्टिव खपत में वृद्धि होने के कारण से है। मांग में गिरावट आने के बावजूद, क्षमता का विस्तार और विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन भी क्षति होने के लिए एक कारण है। यदि याचिकाकर्ता के पास मांग से अधिक क्षमता होती तो उसने किसी भी हानि की वसूली के लिए अपनी कीमत में वृद्धि की होती। उपलब्ध सूचना यह दर्शाती है कि घरेलू उद्योग का क्षमता उपयोग ऐतिहासिक रूप से कम रहा है और जांच की अवधि में तो कम है।
- छ. कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि केवल तभी संभव है, जब कंपनी लाभ कमा रही हो। याचिकाकर्ता ने संरक्षण पाने के लिए बनावटी क्षति दर्शाने हेतु आंकड़ों में मनमर्जी से फेरबदल किया है।
- ज. नकदी लाभ में जांच की अवधि में 16 से 36 गुना वृद्धि हुई है और इसलिए गिरावट होने का कारण कोविड-19 है न कि संबद्ध आयातों के कारण गिरावट हुई है। घरेलू उद्योग का समग्र निष्पादन पूरी क्षति अवधि और जांच की अवधि के दौरान बेहतर रहा है।
- झ. दिनांक 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए 49वीं वार्षिक रिपोर्ट में पीवीटी, व्याज पूर्व लाभ, मूल्यहास और कर (पीवीआईडीटी), वित्त वर्ष 2018-19 की तुलना में जांच की अवधि में कुल आय में अत्यधिक वृद्धि दर्शाई गई है।
- ञ. भारत में संबद्ध उत्पाद के लिए मांग 8000 मी. टन से 9000 मी.टन की रेंज में रही है, जबकि भारत में क्षमता 13000 मी. टन से 15000 मी. टन के बीच है। भारतीय मांग के बड़े हिस्से की पूर्ति याचिकाकर्ता द्वारा स्वयं की जाती है और चीन जन.गण. से आयात काफी कम हैं।
- ट. संबद्ध देश से आयातों और कथित क्षति के बीच कोई कारणात्मक संबंध नहीं है। कारणात्मक संबंध न होना, पहुंच कीमत, कीमत कटौती और लाभप्रदता के बीच सह-संबंध की कमी से स्पष्ट है।
- ठ. क्षमता बढ़ने के संबंध में अधिक निर्धारित लागत के कारण भी पर्याप्त क्षति हुई है, जो कि वर्तमान मांग से काफी अधिक है और इसे चीन जन. गण. से आयातों के कारण न माना जाए।
- ड. यह दावा नहीं किया जा सकता कि वर्तमान क्षति और कारणात्मक संबंध एक निर्णायक समीक्षा जांच के आवेदन में असंगत हैं क्योंकि याचिकाकर्ता ने स्वयं ही यह दावा किया है कि क्षति और चीन जन. गण. से आयातों के बीच एक कारणात्मक संबंध है।
- ढ. याचिकाकर्ता ने विक्रियों की लागत में गिरावट आने के बावजूद कीमतों में कटौती नहीं की, जिससे अधिक कीमत दर्शाई गई है।

- ण. चीन जन. गण. से पहुंच कीमत और याचिकाकर्ता की लाभप्रदता के बीच विलोम संबंध है, जो यह दर्शाता है कि कुछ ऐसा था, जो याचिकाकर्ता के लाभों को छिपा रहा था। आरओसीई में भी इसी प्रकार की गतिविधि दर्शाई गई है। लाभों में कमी आने का कारण, ब्याज लागतों में वृद्धि होना और पूंजीगत व्यय में वृद्धि तथा क्षमता वृद्धि के कारण मूल्यहास होना है।
- त. यूएस से आयात महत्वपूर्ण मात्राओं में हैं और संबद्ध देश से आयात की मात्रा से अधिक हैं। यह स्पष्ट नहीं है कि कैसे यूएस से आयातों के कारण हुई क्षति को अलग किया जाएगा और चीन जन. गण. से संबद्ध आयातों पर नहीं डाला जाएगा।

## ज.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

49. घरेलू उद्योग द्वारा क्षति और कारणात्मक संबंध के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं :-

- क. भारतीय बाजार में पाटित कीमतों पर आयात होना जारी रहा है।
- ख. संबद्ध आयातों में जांच की अवधि में निरपेक्ष संदर्भ में और भारत में उत्पादन और खपत के संबंध में वृद्धि हुई है।
- ग. आयातों से घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती हो रही है और कम कीमत पर बिक्री हो रही है।
- घ. आयातों से घरेलू कीमतों का हास हो रहा है।
- ङ. घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में क्षति अवधि के दौरान काफी गिरावट आई है।
- च. घरेलू उद्योग के निष्पादन में नकदी लाभों, पीवीआईटी और नियोजित पूंजी पर प्रतिफल के संदर्भ में क्षति अवधि के दौरान काफी गिरावट आई है। शुल्कों को समाप्त किए जाने से घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में और भी प्रभाव पड़ेगा।
- छ. घरेलू उद्योग की वस्तुसूची में क्षति अवधि के दौरान काफी वृद्धि हुई है।
- ज. घरेलू उद्योग के उत्पादन, विक्रियों और क्षमता उपयोग में जांच की अवधि में काफी गिरावट हुई है।
- झ. पाटित संबद्ध आयातों और घरेलू उद्योग को हुई क्षति के बीच एक कारणात्मक संबंध मौजूद है।
- ञ. जहां तक दाहेज संयंत्र के अस्थायी तौर पर शटडाउन का संबंध है, यह शटडाउन अवधि की पहली तिमाही में था और यह विशिष्ट रासायनिक कारोबारी घटक के संबंध में था। विचाधीन उत्पाद रिफ्रीजेनेट कारोबारी घटक का भाग है न कि विशिष्ट रासायनिक कारोबारी घटक का भाग है और इसीलिए घरेलू उद्योग द्वारा दावा की गई क्षति शटडाउन के कारण से नहीं है।
- ट. जहां तक अन्य देशों से आयातों का संबंध है, जिनके कारण क्षति हो रही है, चीन जन.गण. का हिस्सा भारत में कुल आयातों में सर्वाधिक है और चीन के आयात की कीमतें वर्ष 2018-19 को छोड़कर क्षति अवधि के दौरान सबसे कम रही है।
- ठ. जहां तक वार्षिक रिपोर्ट के साथ हानियों का मेल करने का संबंध है, घरेलू उद्योग ने घरेलू निष्पादन के लिए ही क्षति का दावा किया है, जबकि वार्षिक रिपोर्ट में गैर-विचाराधीन उत्पाद सहित समग्र निष्पादन, निर्यात बाजारों में निष्पादन आदि शामिल हैं।
- ड. क्षमता में वृद्धि किए जाने की जरूरत है ताकि आवेदक की अपनी कैप्टिव जरूरत और भारत में मांग को पूरा किया जा सके तथा विचाराधीन उत्पाद की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित हो सके। यहां तक कि यदि क्षमता पर उसी स्तर पर विचार किया जाता है, तो भी यह क्षमता उपयोग में गिरावट दर्शाएगी, जो कि भारत में पाटित आयातों की मौजूदगी जारी रहने के कारण से है।
- ढ. जहां तक कैप्टिव खपत का संबंध है, घरेलू उद्योग की कैप्टिव खपत में जांच की अवधि में गिरावट आई है जबकि आयातों में वृद्धि हुई है। घरेलू उद्योग को हानि कैप्टिव खपत में वृद्धि होने के कारण से नहीं है।
- ण. घरेलू उद्योग ने रोजगार, वेतन अथवा उत्पादकता के आधार पर क्षति का दावा नहीं किया है। निर्यातक प्राधिकारी को असंगत तर्कों को उठाकर तथ्यों से भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं।
- त. घरेलू उद्योग के लाभों में गिरावट स्पष्ट रूप से यह दर्शाती है कि घरेलू उद्योग लागत के अनुपात में अपनी कीमतें रखने में असमर्थ है।

- थ. घरेलू उद्योग की व्याज और मूल्यह्रास लागत में वर्ष 2018-19 की तुलना में जांच की अवधि के दौरान गिरावट आई है।
- द. घरेलू उद्योग ने वर्तमान अवधि में यूएसए के लिए कोई याचिका दाखिल नहीं की है। इसके अलावा, यूएसए से आयातों की कीमत, चीन जन. गण. से आयात कीमतों से काफी अधिक हैं। घरेलू उद्योग को क्षति चीन जन. गण. से पाटित आयातों के कारण से है।
- ध. जहां तक कोविड-19 की स्थिति का संबंध है, घरेलू उद्योग की स्थिति पर अवश्य विचार किया जाना चाहिए न कि आदर्श स्थितियों के प्रसंग में, बल्कि घरेलू उद्योग की इन विशिष्ट परिस्थितियों में विचार किया जाना चाहिए। कंपनियां कोविड-19 के कारण वैश्विक तौर पर प्रभावित हुई हैं।

### ज.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

50. घरेलू उद्योग द्वारा क्षति और कारणात्मक संबंध से संबंधित मामलों के संबंध में किए गए अनुरोधों की जांच की गई है। प्राधिकारी द्वारा किए गए क्षति विश्लेषण यहां स्वतः ही हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए विभिन्न अनुरोधों को स्पष्ट करते हैं।
51. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग की क्षति के संबंध में सभी हितबद्ध पक्षकारों के तर्कों और प्रति तर्कों को नोट किया है। प्राधिकारी द्वारा इस प्रकार से किए गए क्षति विश्लेषण हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए विभिन्न अनुरोधों का यहाँ समाधान करता है।
52. जहां तक अनुरोध का संबंध है कि घरेलू उद्योग को कथित क्षति अन्य कारणों से है और घरेलू उद्योग की वार्षिक रिपोर्ट में दिए गए विवरण के अनुसार कोई क्षति नहीं है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि यहां किया गया क्षति संबंधी विश्लेषण स्वतः स्पष्ट है।
53. जहां तक इस अनुरोध का संबंध है घरेलू उद्योग को कथित क्षति दाहेज साइट के अस्थायी रूप से शटडाउन होने के कारण से है, घरेलू उद्योग द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि यह शटडाउन अवधि की प्रथम तिमाही में था और यह विशेष रूप से रासायनिक कारोबारी घटक के संबंध में था, जो कि विचाराधीन उत्पाद का कारोबारी घटक नहीं है।
54. अनुबंध-II के साथ पठित नियमावली के नियम 11 में व्यवस्था की गई है कि क्षति निर्धारण में उन कारकों की जांच शामिल होगी जो घरेलू उद्योग को क्षति की ओर इंगित करते हैं “..... सभी संगत तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, जिसमें पाटित आयातों की मात्रा, समान वस्तुओं के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर उनके प्रभाव और ऐसी वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर ऐसे आयातों के परिणामी प्रभाव शामिल हैं।”
55. नियमावली के नियम 23 में व्यवस्था की गई है कि किसी समीक्षा के मामले में नियम 6,7,8,9,10,11,16,17,18,19 और 20 के प्रावधान आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे। यदि घरेलू उद्योग का निष्पादन यह दर्शाता है कि चालू क्षति अवधि के दौरान इसने क्षति का सामना नहीं किया है, तो प्राधिकारी यह निर्धारित करेंगे कि क्या वर्तमान शुल्क की समामि से घरेलू उद्योग को क्षति की पुनरावृत्ति की संभावना है।
56. प्राधिकारी ने संबद्ध देश से आयातों के कारण पाटन और क्षति के संभावित पहलुओं की जांच आरंभ करने से पहले घरेलू उद्योग को वर्तमान क्षति, यदि कोई हो, की जांच की है। इस बात की जांच की गई है कि क्या कुल रूप में या उत्पादन या खपत के संबंध में कोई वृद्धि हुई है। कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव पर विचार करते हुए, इस बात की जांच करना जरूरी समझा गया है कि क्या भारत में समान वस्तु की कीमत की तुलना में पाटित आयातों द्वारा महत्वपूर्ण कटौती की गई है या क्या ऐसे आयातों के प्रभाव ने अन्यथा रूप से महत्वपूर्ण सीमा तक कीमतों में ह्रास किया है या कीमतों में वृद्धि को रोका है जो अन्यथा महत्वपूर्ण मात्रा तक घटित हुई होती। भारत में घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच करने के लिए, उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले कारकों जैसे उत्पादन, क्षमता उपयोग, विक्री मात्रा, स्टॉक, लाभप्रदता, निवल विक्री आय, पाटन की मात्रा और मार्जिन आदि पर नियमावली के अनुबंध-II के अनुसरण में विचार किया गया है। प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विभिन्न अनुरोधों को ध्यान में रखा है और रिकॉर्ड पर उपलब्ध तथ्यों और प्रयोज्य कानूनों पर विचार करते हुए इसका विश्लेषण किया है। यहां नीचे प्राधिकारी द्वारा किया गया क्षति विश्लेषण स्वयंमेव पक्षकारों द्वारा किए गए विभिन्न अनुरोधों का उल्लेख करता है।

#### ज.3.1 घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों का मात्रा प्रभाव

- क. मांग/स्पष्ट खपत का आकलन

57. प्राधिकारी ने वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ भारतीय उत्पादकों की घरेलू विक्रियों और सभी स्रोतों से आयातों के जोड़ के रूप में भारत में उत्पाद की मांग अथवा स्पष्ट खपत को ध्यान में रखा है-

विवरण	इकाई	2017-18	2018-19	2019-20	पीओआई
घरेलू उद्योग की विक्रियां	मी.टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीवद्ध	100	115	114	94
समर्थकों सहित अन्य भारतीय उत्पादकों की विक्रियां	मी.टन	-	-	-	-
संबद्ध देश- चीन	मी.टन	2,053	1,214	1,074	1,309
अन्य देशों से आयात	मी.टन	2,975	2,864	2,964	2,171
कुल भारतीय मांग	मी.टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीवद्ध	100	98	97	82

58. यह देखा गया है कि क्षति अवधि और जांच की अवधि में संबद्ध वस्तुओं की मांग में गिरावट आई है। हालांकि, मांग में गिरावट के बावजूद, 2018-19, 2019-20 की तुलना में जांच की अवधि में संबद्ध आयातों में वृद्धि हुई है।

#### ख. संबद्ध देश से आयात मात्रा

59. पाटित आयातों की मात्रा के संबंध में, प्राधिकारी द्वारा यह विचार किया जाना जरूरी है कि क्या पाटित आयातों में या तो कुल रूप में या भारत में उत्पादन अथवा खपत के सापेक्ष में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। क्षति विश्लेषण के प्रयोजनार्थ, प्राधिकारी ने, डीजीसीआईएंडएस से प्राप्त सौदा-वार आयात आंकड़ों पर भरोसा किया है। तथ्यात्मक स्थिति इस प्रकार है:-

विवरण	इकाई	2017-18	2018-19	2019-20	पीओआई
संबद्ध देश- चीन	मी.टन	2,053	1,214	1,074	1,309
प्रवृत्ति	सूचीवद्ध	100	59	52	64
निम्न के संबंध में संबद्ध देश से आयात					
कुल आयात	%	41	30	27	38
प्रवृत्ति	सूचीवद्ध	100	73	65	92
उत्पादन	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीवद्ध	100	54	46	65
खपत	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीवद्ध	100	60	54	78

60. यह देखा गया है कि:

- क. संबद्ध देश से आयातों में 2018-19 में गिरावट आई और 2019-20 में इन में और अधिक गिरावट आई किंतु उसके बाद जांच की अवधि में इनमें वृद्धि हुई।
- ख. संबद्ध देश से आयातों ने भारत में उत्पादन और खपत के संबंध में समान प्रवृत्ति दर्शायी है। 2018-19 और 2019-20 की तुलना में जांच की अवधि के दौरान उत्पादन और खपत के संबंध में संबद्ध देश से आयातों में वृद्धि हुई है।
- ग. पाटनरोधी शुल्क के लागू होने के बावजूद जांच की अवधि के दौरान आयातों में वृद्धि हुई है।

#### ज.3.2 पाटित आयातों का कीमत प्रभाव

61. कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में, यह विश्लेषण किया जाना जरूरी है कि क्या भारत में समान उत्पादों की कीमत की तुलना में कथित पाटित आयातों द्वारा महत्वपूर्ण कीमत कटौती की गई है अथवा क्या ऐसे आयातों के प्रभाव ने अन्यथा रूप से कीमतों में ह्रास किया है या कीमतों में वृद्धि को रोका है, जो अन्यथा सामान्य अवधि में घटित हुई होती। संबद्ध देश से पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों पर प्रभाव की कीमत कटौती, कीमत ह्रास और कीमत

न्यूनीकरण, यदि कोई हो, के संदर्भ में जांच की गई है। इस विश्लेषण के प्रयोजनार्थ घरेलू उद्योग के उत्पादन की लागत, क्षति रहित कीमत (एनआईपी) और निवल विक्री आय (एनएसआर) की संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के आयातों की पहुंच कीमत के साथ तुलना की गई है।

#### क. कीमत कटौती

62. कीमत कटौती विश्लेषण के प्रयोजनार्थ, घरेलू उद्योग की विक्री कीमत की संबद्ध देश की आयात कीमत के साथ तुलना की गई है। तदनुसार, संबद्ध देश से पाटित आयातों के कटौती प्रभावों को निम्नानुसार तैयार किया गया है:-

विवरण	इकाई	2017-18	2018-19	2019-20	पीओआई
<b>कुल</b>					
निवल विक्री प्राप्ति	₹/कि.ग्रा.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीवद्ध	100	102	106	105
पहुंच कीमत	₹/कि.ग्रा.	270	332	307	271
कीमत कटौती	₹/कि.ग्रा.	***	***	***	***
कीमत कटौती	%	***	***	***	***
कीमत कटौती	% रेंज	20-30	0-10	10-20	20-30
<b>बिना पैक किए गए</b>					
निवल विक्री प्राप्ति	₹/कि.ग्रा.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीवद्ध	100	102	108	107
पहुंच कीमत	₹/कि.ग्रा.	221	300	238	210
कीमत कटौती	₹/कि.ग्रा.	***	***	***	***
कीमत कटौती	%	***	***	***	***
कीमत कटौती	% रेंज	20-30	0-10	20-30	30-40
<b>पैक किए गए</b>					
निवल विक्री प्राप्ति	₹/कि.ग्रा.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीवद्ध	100	102	100	97
पहुंच कीमत-चीन	₹/कि.ग्रा.	309	360	334	309
कीमत कटौती	₹/कि.ग्रा.	***	***	***	***
कीमत कटौती	%	***	***	***	***
कीमत कटौती	% रेंज	30-40	20-30	20-30	20-30

63. यह देखा गया है कि संबद्ध देश से आयात, पैक और बिना पैक किए गए, दोनों रूपों में, घरेलू उद्योग की घरेलू विक्री कीमत से कम कीमत पर प्रवेश कर रहे हैं जिसके परिणामस्वरूप सकारात्मक कीमत कटौती हो रही है।

#### ख. कीमत ह्रास और कीमत न्यूनीकरण

64. यह निर्धारित करने के लिए कि क्या पाटित आयात घरेलू कीमतों में ह्रास या न्यूनीकरण कर रहे हैं और क्या ऐसे आयातों के प्रभाव ने महत्वपूर्ण मात्रा तक कीमतों में ह्रास किया है या कीमतों में वृद्धि को रोका है, जो अन्यथा रूप से सामान्य अवधि में घटित हुई होती, क्षति अवधि में लागतों और कीमतों में परिवर्तनों की जांच की गई है। नीचे दी गई तालिका तथ्यात्मक स्थिति को दर्शाती है:-

विवरण	इकाई	2017-18	2018-19	2019-20	पीओआई
विक्री की लागत- घरेलू	₹/कि.ग्रा.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीवद्ध	100	123	133	137
निवल विक्री प्राप्ति	₹/कि.ग्रा.	***	***	***	***

प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	102	106	105
पहुंच कीमत	₹/कि.ग्रा.	270	332	307	271
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	123	113	100
पिछले वर्ष में गिरावट					
विक्रियों की लागत- घरेलू	₹/कि.ग्रा.	-	63	28	11
विक्री कीमत- घरेलू	₹/कि.ग्रा.	-	7	14	(3)
पहुंच कीमत	₹/कि.ग्रा.	-	61	(25)	(35)

65. यह देखा है क्षति अवधि में आयातों की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की लागतों से भिन्न रही है। जहां क्षति अवधि में लागतों में वृद्धि हुई है, घरेलू उद्योग लागत में वृद्धि के अनुपात में अपनी विक्री कीमत में वृद्धि करने में असमर्थ रहा है जिसके परिणाम स्वरूप कीमत ह्रास हुआ।

### ज.3.3 घरेलू उद्योग के आर्थिक मापदंड

66. नियमावली के अनुबंध-II में यह व्यवस्था की गई है कि घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में समस्त संगत आर्थिक कारकों और संसूचकों का उद्देश्यपरक और निष्पक्ष मूल्यांकन किया जाना चाहिए जिनका घरेलू उद्योग की हालत पर प्रभाव पड़ता हो, जिसमें विक्री, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्से, उत्पादकता, निवेश पर आय अथवा क्षमता उपयोग में वास्तविक और संभावित गिरावट; वे कारक जो घरेलू कीमतों, पाटन मार्जिन की मात्रा पर प्रभाव डालते हों; नकदी प्रवाह, मालसूची, रोजगार, मजदूरी, विकास, पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता शामिल है। घरेलू उद्योग से संबंधित विभिन्न क्षति मानदंडों पर नीचे विचार किया गया है।
67. प्राधिकारी ने विभिन्न हितवद्ध पक्षकारों द्वारा उनके अनुरोधों में किए गए विभिन्न तथ्यों और तर्कों को ध्यान में रखते हुए क्षति संबंधी मापदंडों की उद्देश्य परक जांच की है।

#### i. उत्पादन, क्षमता, क्षमता उपयोग और विक्रियां

68. क्षति अवधि में घरेलू उद्योग की क्षमता, उत्पादन, विक्रियों और क्षमता उपयोग को नीचे तालिका में दिया गया है:-

विवरण	इकाई	2017-18	2018-19	2019-20	पीओआई
क्षमता	मी.टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	100	115	130
पीयूसी उत्पादन मात्रा	मी.टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	109	113	99
क्षमता उपयोग	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	109	98	76
घरेलू विक्रियां	मी.टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	115	114	94

69. यह देखा गया है कि:

- घरेलू उद्योग ने 2019-20 और बाद में जांच की अवधि में भी अपनी स्थापित क्षमता में विस्तार किया है।
- 2019-20 तक घरेलू उद्योग के उत्पादन में वृद्धि हुई किंतु बाद में जांच की अवधि में इसमें गिरावट आई।
- 2018-19 में क्षमता उपयोग में वृद्धि हुई किन्तु 2019-20 में और बाद में जांच की अवधि में महत्वपूर्ण गिरावट आई।
- 2018-19 में घरेलू उद्योग की घरेलू विक्रियों में वृद्धि हुई लेकिन 2019-20 और बाद में जांच की अवधि में महत्वपूर्ण गिरावट आई।

## ii. मांग में बाजार हिस्सा

70. घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से को नीचे सारणी में दर्शाया गया है:-

विवरण	इकाई	2017-18	2018-19	2019-20	पीओआई
घरेलू उद्योग	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीवद्ध	100	118	118	116
संबद्ध देश चीन जन.गण.	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीवद्ध	100	60	54	78
अन्य देश	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीवद्ध	100	98	103	89
कुल	%	100	100	100	100

71. यह देखा गया है कि आधार वर्ष की तुलना में जहां घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में वृद्धि हुई है और अन्य देशों के बाजार हिस्से में गिरावट आई है, पिछले वर्ष की तुलना में जांच की अवधि के दौरान संबद्ध देश के बाजार हिस्से में वृद्धि हुई है। मांग में गिरावट और विद्यमान पाटनरोधी शुल्क के बावजूद संबद्ध देश के बाजार हिस्से में वृद्धि हुई है।

## iii. मालसूची

72. क्षति अवधि और पीओआई में घरेलू उद्योग की मालसूची की स्थिति नीचे सारणी में दी गई है:-

विवरण	इकाई	2017-18	2018-19	2019-20	पीओआई
प्रारंभिक स्टॉक	मी.टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीवद्ध	100	103	87	70
अंतिम स्टॉक	मी.टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीवद्ध	100	85	148	195
औसत स्टॉक	मी.टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीवद्ध	100	94	118	133

73. यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग के पास औसत मालसूची में जांच की अवधि के दौरान उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

## iv. लाभप्रदता, नकद लाभ और नियोजित पूंजी पर आय

74. क्षति अवधि में घरेलू उद्योग की लाभप्रदता, नकद लाभ और निवेश पर आय नीचे सारणी में दिए गए हैं:-

विवरण	इकाई	2017-18	2018-19	2019-20	पीओआई
कर पूर्व लाभ/(हानि)	रु./किग्रा.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीवद्ध	100	33	19	5
कर पूर्व लाभ/हानि	लाख रु.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीवद्ध	100	38	21	4
नकद लाभ	लाख रु.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीवद्ध	100	56	42	31
कर पूर्व लाभ, ब्याज और मूल्य ह्रास	लाख रु.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीवद्ध	100	66	52	41
नियोजित पूंजी पर आय	%	***	***	***	***

प्रवृत्ति	सूचीवद्ध	100	56	33	18
-----------	----------	-----	----	----	----

75. यह देखा गया है कि:

- क. क्षति अवधि और जांच की अवधि में घरेलू उद्योग के लाभों में उल्लेखनीय गिरावट आई है।  
 ख. क्षति अवधि सहित जांच की अवधि में नियोजित पूंजी पर नकद लाभों और नियोजित पूंजी पर आय में भी गिरावट आई है।

**v. रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता**

76. क्षति अवधि में रोजगार, मजदूरी और घरेलू उद्योग की उत्पादकता नीचे तालिका में दिए गए हैं:-

विवरण	इकाई	2017-18	2018-19	2019-20	पीओआई
मजदूरी	लाख रु.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीवद्ध	100	147	187	174
रोजगार	संख्या	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीवद्ध	100	149	141	130
प्रति इकाई मजदूरी	रु./एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीवद्ध	100	135	167	176
प्रति कर्मचारी उत्पादकता	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीवद्ध	100	74	80	76
दैनिक उत्पादकता	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीवद्ध	100	109	113	99

77. यह देखा गया है कि आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की मजदूरियों और रोजगार में वृद्धि हुई है। तथापि, उत्पादकता में कर्मचारी और कार्य दिवसों, दोनों के संदर्भ में पिछले वर्ष, साथ ही आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में गिरावट आई है।

**vi. वृद्धि**

78. उत्पादन, मालसूचियों और लाभों के संदर्भ में घरेलू उद्योग की वृद्धि नीचे दी गई तालिका के अनुसार है:-

विवरण	इकाई	2017-18	2018-19	2019-20	पीओआई
उत्पादन	वर्ष/वर्ष%	-	9	3	(12)
घरेलू बिक्री मात्रा	वर्ष/वर्ष%	-	15	(2)	(17)
घरेलू बिक्रियों की लागत	वर्ष/वर्ष%	-	23	8	3
घरेलू बिक्री कीमत	वर्ष/वर्ष%	-	3	5	(0)
घरेलू लाभ/हानि	वर्ष/वर्ष%	-	(67)	(44)	(74)
औसत स्टॉक	वर्ष/वर्ष%	-	(6)	26	13

79. यह देखा गया है कि प्रमुख मात्रा संबंधी मापदंडों जैसे उत्पादन, घरेलू बिक्रियों और लाभों के संबंध में घरेलू उद्योग की वृद्धि नकारात्मक है।

**vii. पाटन मार्जिन की मात्रा**

80. पाटन की मात्रा एक संकेतक है कि भारत में किस सीमा तक आयात पाटित किए जा रहे हैं। जांच यह दर्शाती है कि जांच की अवधि में पाटन मार्जिन सकारात्मक रहा है।

**viii. पूंजी निवेश को जुटाने की क्षमता**



81. घरेलू उद्योग ने इस कारण क्षति का दावा नहीं किया है। यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग एक बहु-उत्पाद कंपनी है। क्षति अवधि के दौरान सिर्फ किसी विशेष उत्पाद के निष्पादन के आधार पर ही निवेश संबंधी निर्णय नहीं लिए जा सकते और उत्पाद के दीर्घावधिक संभावनाओं द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है।

**ix. घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारण**

82. यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग उत्पाद का एकमात्र स्वदेशी आपूर्तिकर्ता है। इसके अलावा, संपूर्ण क्षति अवधि के दौरान, घरेलू उद्योग की लागतें आयातों की पहुंच कीमतों से कम रही हैं। परिणाम स्वरूप, घरेलू उद्योग लागतों में वृद्धि के समानुपात में अपनी कीमतों में वृद्धि करने में असमर्थ है। अतः यह देखा गया है कि आयातों की कीमतें बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित कर रही हैं। घरेलू उद्योग द्वारा सामना किया जा रहा कीमत ह्रास का कारण प्रभाव आयातों की निम्न कीमत है।

83. पाटित आयात घरेलू उद्योग की कीमतों को प्रभावित कर रहे हैं। इसलिए, यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारण संबद्ध वस्तुओं के पाटित आयात हैं।

**x. कम कीमत पर बिक्री/मार्जिन की मात्रा**

84. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग के लिए एनआईपी को यथा संशोधित अनुबंध-II के साथ पठित, पाटनरोधी नियमावली में निर्धारित किए गए सिद्धांतों के आधार पर निर्धारित किया है। पीयूमी के एनआईपी को घरेलू उद्योग द्वारा उपलब्ध कराए गए उत्पादन की लागत और जांच की अवधि के लिए प्रैक्टिसिंग कॉस्ट एकाउंटेंट द्वारा विधिवत् सत्यापित सूचना/आंकड़ों को अपना कर निर्धारित किया गया है। क्षति मार्जिन को परिकलित करने के लिए संबद्ध देश से पहुंच कीमत की तुलना करने के लिए एन आई पी पर विचार किया गया है। क्षति रहित कीमत का निर्धारण करने के लिए, क्षति अवधि में घरेलू उद्योग के कच्चे माल के सर्वोत्तम उपयोग पर विचार किया गया है। यूटिलिटीज के साथ भी यही उपचार किया गया है। क्षति अवधि में उत्पादन क्षमता के सर्वोत्तम उपयोग पर विचार किया गया है। यह सुनिश्चित किया गया है कि उत्पादन की लागत पर किसी असाधारण या गैर-आवर्ती व्ययों को प्रभावित नहीं किया गया था। क्षति रहित कीमत पर पहुंचने के लिए पीयूमी के लिए औसत नियोजित पूंजी (अर्थात् औसत कार्यशील पूंजी सहित औसत निवल निर्धारित परिसंपत्तियां) पर एक उचित आयात (कर पूर्व @22%) को कर पूर्व लाभ के रूप में अनुमति दी गई थी, जैसाकि नियमावली के अनुबंध-III में निर्धारित किया गया है और जिस का अनुसरण किया जा रहा है। उत्पाद के पैक और बिना पैक किए गए रूपों के लिए पृथक् एनआईपी का निर्धारण किया गया है। क्षति मार्जिन परिकलित करने के लिए इस प्रकार निर्धारित किए गए एनआईपी पर विचार किया गया है।
85. सहयोगी निर्यातकों के लिए पहुंच कीमत को पाटन मार्जिन के निर्धारण के प्रयोजनार्थ अपनाई गई सीआईएफ निर्यात कीमत से निर्धारित किया गया है। आयातों की पहुंच कीमत को निर्धारित करने के लिए प्रयोज्य सीमा शुल्कों को जोड़ा गया है। संबद्ध देश से सभी गैर-सहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए, प्राधिकारी ने उपलब्ध तथ्यों के आधार पर पहुंच कीमत को निर्धारित किया है।
86. उपरोक्त के अनुसार निर्धारित की गई पहुंच कीमत और एनआईपी के आधार पर, चीन जन.गण. से उत्पादकों/निर्यातकों के लिए क्षति मार्जिन को नीचे तालिका में उपलब्ध कराया गया है:-

क्र.सं.	उत्पादक	गैर-क्षति कीमत (यूएसडॉ./ एमटी)	पहुंच मूल्य (यूएसडॉ./एमटी)	क्षति मार्जिन (यूएसडॉ./एमटी)	क्षति मार्जिन (%)	क्षति मार्जिन (रेंज %)
1.	सिनोकेम एन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन केमिकल्स) टाइकैंग (कंपनी लि. और शांक्सी सिनोकेम लानतियान न्यू केमिकल मैटिरियल कं. लि.	***	***	***	***	70-80
2.	शानडोंग डोंगयुई केमिकल कं. लि.	***	***	***	***	70-80
3.	झेजियांग सनमेई केमिकल इन्ड .कं., लि.	***	***	***	***	80-90
4.	झेजियांग क्यूहुआ फ्लूओर-केमिस्ट्री कं. लि. और झेजियांग शूझोऊ लियांगझोऊ रेफिजरेट्स कं., लि.	***	***	***	***	60-70
5.	अन्य सभी	***	***	***	***	120-130

**ज.3.4 क्षति संबंधी निष्कर्ष**

87. संबद्ध वस्तुओं के आयातों और घरेलू उद्योग के निष्पादन की जांच स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि 2018-19 और 2019-20 की तुलना में जांच की अवधि में संबद्ध देश से पाटित आयातों की मात्रा में निरपेक्ष रूप में और सापेक्ष रूप में वृद्धि हुई है। संबद्ध देश से आयात घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती कर रहे हैं और कम कीमत पर बिक्री सकारात्मक है। संबद्ध देश से आयात घरेलू उद्योग की कीमतों को दबा रहे हैं। पिछले वर्ष की तुलना में जांच की अवधि के दौरान उत्पादन, बिक्रियों, बाजार हिस्से और क्षमता उपयोग में गिरावट आई है और जांच की अवधि में घरेलू उद्योग के लिए माल सूचियों में वृद्धि हुई है। लाभप्रदता, लाभों, नकद लाभों और नियोजित पूंजी पर आय के संबंध में घरेलू उद्योग के निष्पादन में गिरावट आई है। पूर्वोक्त को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी का निष्कर्ष है कि पाटनरोधी शुल्क के विद्यमान होने के बावजूद घरेलू उद्योग क्षति का सामना कर रहा है।

**झ. कारणात्मक संबंध और गैर-आरोपण विश्लेषण**

88. प्राधिकारी ने पाटित आयातों के अलावा किन्हीं ऐसे अन्य ज्ञात कारकों की भी जांच की है जो उसी समय घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचा सकते हैं ताकि इन अन्य कारकों के कारण हुई क्षति, यदि कोई हो, पाटित आयातों के कारण हुई नहीं मानी जाएगी। इस संबंध में प्रासंगिक कारकों में, अन्य के साथ-साथ, पाटित कीमतों पर नहीं बेचे गए आयातों की मात्रा और कीमत, मांग में संकुचन या खपत के पैटर्न में परिवर्तन, व्यापार प्रतिबंधित पद्धतियां और घरेलू एवं विदेशी उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा, प्रौद्योगिकी में परिवर्तन, निर्यात निष्पादन और घरेलू उद्योग की उत्पादकता शामिल हैं। प्राधिकारी ने जांच की है कि क्या पाटित आयातों के अलावा अन्य कारक भी घरेलू उद्योग को क्षति में योगदान कर सकते हैं।

**क) तीसरे देशों से आयातों की मात्रा और कीमतें**

89. यह देखा गया है कि अन्य देशों से आयात (पाटित आयातों के अलावा) या तो न्यूनतम सीमा से कम हैं या उच्च कीमतों पर हैं। इसलिए, तीसरे देश से आयात घरेलू उद्योग को क्षति का कारण नहीं हो सकते।

**ख) मांग में संकुचन**

90. यह देखा गया है कि क्षति अवधि और जांच की अवधि में विचाराधीन उत्पाद की मांग में गिरावट आई है। तथापि, घरेलू मांग में गिरावट और पाटनरोधी शुल्क के विद्यमान होने के बावजूद जांच की अवधि में संबद्ध आयातों में वृद्धि हुई है। इसलिए, मांग में संकुचन को घरेलू उद्योग के क्षति का कारण नहीं समझा जा सकता।

**ग) खपत के पैटर्न में परिवर्तन**

91. विचाराधीन उत्पाद के खपत के पैटर्न में किसी महत्वपूर्ण परिवर्तन (परिवर्तनों) के बारे में किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। इसलिए, खपत के पैटर्न में संभावित परिवर्तन प्राधिकारी द्वारा विचारित क्षति के कारण नहीं है।

**घ) प्रतिस्पर्धा और व्यापार प्रतिबंधित पद्धतियों की स्थिति**

92. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच यह नहीं दर्शाती कि प्रतिस्पर्धा की स्थितियां या व्यापार प्रतिबंधित पद्धतियां प्राधिकारी द्वारा विचार की गई क्षति के लिए उत्तरदायी है।

**ड.) प्रौद्योगिकी में परिवर्तन**

93. प्रौद्योगिकी में महत्वपूर्ण परिवर्तनों की मौजूदगी के बारे में किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जो घरेलू उद्योग को क्षति का कारण हो सकता है।

**च) घरेलू उद्योग का निर्यात निष्पादन**

94. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग के लिए आंकड़ों पर केवल क्षति विश्लेषण के लिए विचार किया है। इसलिए निर्यात निष्पादन घरेलू उद्योग को क्षति का कारण नहीं है।

**छ) अन्य उत्पादों का निष्पादन**

95. घरेलू उद्योग ने पीयूमी के लिए क्षति संबंधी डाटा उपलब्ध कराया है और क्षति विश्लेषण के प्रयोजन हेतु प्राधिकारी ने इसे ही अपनाया है। आवेदक द्वारा उत्पादित और बेचे गए अन्य उत्पादों का निष्पादन घरेलू उत्पादन को क्षति का संभावित कारण नहीं है।
96. अतः, प्राधिकारी निष्कर्ष देते हैं कि घरेलू उद्योग को अन्य कारकों के कारण जांच की अवधि में कोई क्षति नहीं हुई है।

### झ.1 कारणात्मक संबंध पर निष्कर्ष

97. प्राधिकारी का निष्कर्ष है कि घरेलू उद्योग ने अन्य कारकों के कारण पीओआई में क्षति का सामना नहीं किया है। इस के अलावा, निम्नलिखित कारक दर्शाते हैं कि घरेलू उद्योग को क्षति संबद्ध पाटित आयातों के कारण है:-
- क. निर्यात कीमत लगातार घरेलू उद्योग की विक्रियों की लागत से भी कम रही है। परिणाम स्वरूप, घरेलू उद्योग विक्रियों की लागत में वृद्धि सहित अपनी विक्री कीमत में वृद्धि करने में असफल रहा है।
  - ख. आयात घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती कर रहे हैं। आयातों की पहुंच कीमतें न केवल घरेलू उद्योग की विक्री कीमतों से बल्कि पीओआई में उत्पादन की लागत से भी नीचे रहे हैं।
  - ग. पाटित आयात बाजार में उत्पाद की कीमतों पर महत्वपूर्ण दबावकारी प्रभाव उत्पन्न कर रहे हैं।
  - घ. घरेलू उद्योग की विक्री कीमत पर आयातों के विपरीत प्रभाव ने लाभों, नकद लाभों और नियोजित पूंजी पर आय में महत्वपूर्ण ह्रास किया है।
  - ड. कम कीमत वाले आयातों के परिणाम स्वरूप, घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में गिरावट आई है जबकि संबद्ध आयातों के बाजार हिस्से में वृद्धि हुई है। परिणाम स्वरूप, घरेलू उद्योग के उत्पादन, विक्रियों और क्षमता उपयोग में गिरावट आई है जबकि घरेलू उद्योग की मालसूची में वृद्धि हुई है।
  - च. विभिन्न आर्थिक मापदंडों के संबंध में घरेलू उद्योग की वृद्धि नकारात्मक है।
98. अतः, प्राधिकारी निष्कर्ष देते हैं कि संबद्ध वस्तुओं के पाटन और घरेलू उद्योग को क्षति के बीच कारणात्मक संबंध मौजूद है।

### ब. पाटन और क्षति के जारी रहने/पुनरावृत्ति की संभावना

99. किसी समीक्षा जांच में, प्राधिकारी द्वारा यह निर्धारित किया जाना जरूरी है कि क्या संबद्ध वस्तुएं पाटित कीमतों पर भारतीय बाजार में प्रवेश कर रही हैं या प्रवेश करने की संभावना है और यदि शुल्क को समाय करने की अनुमति दी जाती है तो क्या इन पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को क्षति के जारी रहने या पुनरावृत्ति की संभावना है।

### ब.1 अन्य हितवद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

100. संभावना के संबंध में अन्य हितवद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:-

- क. अतिरिक्त उत्पादन क्षमता, अनुप्रयुक्त क्षमताओं, बाजार हिस्से, निर्यात प्रचालन और चीन जन.गण. से निर्यातकों के लिए भारत के आकर्षक बाजार होने आदि के संबंध में याचिकाकर्ता के दावे केवल काल्पनिक, मनगढ़ंत और तथ्यों पर आधारित नहीं हैं। निर्यातकों की पाटन निस्तारणीय क्षमताओं का अर्थ यह नहीं है कि अप्रयुक्त क्षमताओं का प्रयोग केवल भारत को निर्यात करने के लिए किया जा रहा है। पाटन और परिणामी क्षति के जारी रहने अथवा पुनरावृत्ति की कोई संभावना नहीं है।
- ख. चीन जन.गण. में अतिरिक्त क्षमता 5-10K मी.टन से अधिक नहीं हो सकती। ऐसी क्षमता सामान्य है और उत्पादन व्यवधान को पूरा करने के लिए आवश्यक सुरक्षित भंडार है। कोई प्रमुख निष्क्रिय क्षमता नहीं है।
- ग. अत्यधिक, मुक्त रूप से निस्तारणीय और निष्क्रिय क्षमताओं के लिए आंकड़े अलंघनीय नहीं हैं क्योंकि उनमें विभिन्न एचएफसी सम्मिलित हैं जो विचाराधीन उत्पाद नहीं हैं। ऐसे आंकड़ों पर भरोसा करने का परिणाम पूरी तरह से विकृत निष्कर्षों में हो सकता है।
- घ. इसके बजाय, आर-134ए से संबंधित एडी जांच में यूएसआईटीसी द्वारा एक 2017 के जांच परिणाम से प्राप्त वैकल्पिक आंकड़ों पर भरोसा किया जाना चाहिए। यूएसआईटीसी ने 169000 मी.टन की क्षमता और 94 प्रतिशत क्षमता उपयोग को अवलोकित किया और निष्कर्ष दिया कि चीनी उत्पादकों के पास अप्रयुक्त सीमित क्षमता है। सनमेई हाल में चीन जन.गण. में किसी महत्वपूर्ण क्षमता परिवर्धनों से अवगत नहीं है और यूएसआईटीसी द्वारा अवलोकित समग्र क्षमता अभी भी प्रासंगिक है।

- ड. याचिकाकर्ता ने चीन जन.गण. की अप्रयुक्त क्षमता लगभग 79,160 मी.टन होने का दावा किया है। तथापि, क्षमता उपयोग के 94 प्रतिशत से 95 प्रतिशत की सीमा में होने की कल्पना करते हुए भी अतिरिक्त क्षमता 5000 से 10000 की सीमा में भी नहीं हो सकती।
- च. याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि प्रवृत्त शुल्कों को पूरी तरह से अधिशोषित किया गया था जो सांख्यिकी से स्पष्ट रूप से गलत है क्योंकि आयात पूरी तरह से सीमाबद्ध थे। अतः, चीन जन.गण. से आयातों को स्पष्ट रूप से घरेलू उद्योग के लिए खतरा नहीं समझा जा सकता। संभावना का कोई संगत आधार नहीं है क्योंकि आयातों की ऐतिहासिक मात्रा ऐसे दावों को नकारती है जिनकी कोई योग्यता नहीं है।
- छ. पीयूसी का सीमित प्रभाव इस तथ्य का परावर्तक है कि चीन जन.गण. में कोई महत्वपूर्ण निष्क्रिय क्षमता विद्यमान नहीं है।
- ज. अन्य देशों द्वारा पाटनरोधी शुल्क लागू किए गए थे। 2017-18 के आरंभ में और 2017 के पश्चात्, भारत को निर्यातों में वृद्धि नहीं हुई है। इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता कि निर्यातक वर्षों तक ऐसी निष्क्रिय क्षमता को रोक कर रखेंगे और शुल्क के समाम होने की प्रतीक्षा करते रहेंगे ताकि वे भारत में बहुत मामूली मांग को भी पूरा कर सकें।
- झ. उक्त उत्पाद के प्रयोग पर प्रतिबंध के कारण ईयू और यूएसए जैसे प्रमुख बाजार में मांग में गिरावट ऐसे देशों को संबद्ध वस्तुओं के निर्यातों में गिरावट का कारण बन सकती है। किन्तु उस स्थिति में भी, किसी प्रयुक्त क्षमता को किसी भी क्लोजर या परिशोधनों से गुजरना होगा और पी यू सी के लिए सीमित भारतीय बाजार के लिए जीवित नहीं रखा जाएगा।
- ञ. विचाराधीन उत्पाद को इसके पर्यावरणीय प्रभाव के कारण उत्पादन और आपूर्ति से चरणबद्ध रूप से हटाए जाने की संभावना है। इसलिए, यह कल्पना करना उचित नहीं होगा कि संबद्ध देश में उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा कुल एचएफसी क्षमता के महत्वपूर्ण भाग को पीयूसी के प्रति समर्पित किया जाएगा।
- ट. अतिरिक्त क्षमता के दावे को प्रतिभागी निर्यातकों के प्रश्नावली उत्तरों में उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के आधार पर सत्यापित किया जाना चाहिए।
- ठ. जैसाकि चीन जन.गण. से ग्रेफाइट इलैक्ट्रोड्स के मामले में निर्णय दिया गया है, अतिरिक्त क्षमताओं को पाटित कीमतों पर भारत में उतारने का कोई अभिप्राय नहीं है और स्पष्ट रूप से इसे क्षति के पहले से पूर्वाभासित और आने वाले खतरे के रूप में विचारित नहीं किया जा सकता जैसाकि भारतीय स्पिनर्स एसोसिएशन बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी के मामले में निर्णय किया गया है।
- ड. चूंकि भारत की क्योटो प्रोटोकॉल का एक हस्ताक्षरी है और परिणामस्वरूप पीयूसी के भारत में भी चरणबद्ध रूप से हटाए जाने की संभावना है, यूएसए और ईयू की भांति ही भारत में भी मांग में गिरावट आने की संभावना है।
- ढ. घरेलू उद्योग द्वारा निर्यातकों के निष्पादन पैरामीटरों के विश्लेषण सूचीबद्ध आंकड़ों पर आधारित हैं न कि वास्तविक सूचना पर। झेजियांग क्यूशाओ लियानशाओ द्वारा कोई क्षमता वर्धन नहीं किया गया है। अतिरिक्त क्षमताओं का निपटान करने के लिए इसकी घरेलू रूप से और तीसरे देशों में पर्याप्त मांग है। भेदभाव पूर्ण कीमत निर्धारण का आरोप गलत है। पीओआई में भारत को निर्यातों में गिरावट आई है।
- ण. क्यूहुआ फ्लो-केमिस्ट्री का क्षमतावर्धन क्रम रहित है क्योंकि निर्यात अनपैकड रूप में किया गया था जबकि महत्वपूर्ण चीनी निर्यात पैकड रूप में किए जाते हैं। भारत को विक्रियां नगण्य हैं। जब उत्पाद को चरणबद्ध रूप में समाप्त किया जा रहा है तब हानि को वहन करने और बाजार पर पकड़ बनाए रखने के लिए प्रतिवादी का कोई प्रोत्साहन नहीं दिया गया है।
- त. तीसरे देशों को चीनी उत्पादकों की निर्यात कीमत भारत की तुलना में अधिक है, इसलिए भारत एक कीमत आकर्षक बाजार नहीं है।

## ब.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

101. संभावना के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:-

- क. मूल जांच और तदवर्ती जांचों में पाटन मार्जिन महत्वपूर्ण है। एडीडी के प्रवृत्त होने के बावजूद संबद्ध माल पाटित किया जा रहा है। इसलिए, एडीडी को समाप्त किए जाने की स्थिति में, पाटन और परिणामी क्षति जारी रहेंगे।
- ख. संबद्ध वस्तुओं के चीनी उत्पादकों के पास चीनी मांग से उल्लेखनीय रूप से अधिक क्षमता है। एडीडी को समाप्त किए जाने की स्थिति में, भारत उनके लिए एक आकर्षक बाजार बन जाएगा।

विवरण	मात्रा (टन प्रति वर्ष)
चीनी उत्पादकों की कुल क्षमता	237,160*
चीन में संबद्ध वस्तुओं का उत्पादन (2019)	158,000
चीन में संबद्ध वस्तुओं की खपत (2019)	57,000
चीन से संबद्ध वस्तुओं का निर्यात (2019)	101,000

\*पूर्ण रूप से संबद्ध वस्तुओं को समर्पित नहीं

ग. संबद्ध वस्तुओं के चीनी उत्पादकों के पास 79,160 मी.टन की अप्रयुक्त क्षमता और 180,000 मी.टन की मुक्त रूप से निस्तारणीय क्षमता है, जो भारतीय मांग से उल्लेखनीय रूप से अधिक है। एडीडी को समाप्त किए जाने की स्थिति में, इन क्षमताओं को पाटित कीमतों पर भारत को स्थानांतरित किया जा सकता है।

विवरण	मात्रा (टन प्रति वर्ष)
चीनी उत्पादकों की कुल क्षमता	2,37,160
चीन में संबद्ध वस्तुओं का उत्पादन (2019)	1,58,000
चीन में संबद्ध वस्तुओं की खपत (2019)	57,000
चीन से संबद्ध वस्तुओं का निर्यात (2019)	1,01,000
अप्रयुक्त क्षमताएं	79,160
मुक्त रूप से निस्तारणीय क्षमताएं	1,80,160

- घ. क्योटो प्रोटोकॉल के अनुसमर्थन के अनुसरण में, यूएसए और ईयू ने संबद्ध वस्तुओं को चरणबद्ध रूप से बाहर करने के लिए उपाय किए हैं। इन देशों में मांग में उल्लेखनीय गिरावट के बाद, भारतीय बाजार अधिक आकर्षक हो जाएगा। इसलिए, एडीडी को समाप्त किए जाने की स्थिति में, संबद्ध देश से भारत में पाटित आयातों में महत्वपूर्ण वृद्धि होगी।
- ड. 2017 में, यूएसए ने यूएसए में चीन जन.गण. से संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर एडीडी लागू किया था। इसने उनके सबसे बड़े निर्यात बाजार तक चीनी पहुंच को प्रभावित किया था। इसलिए, एडीडी को समाप्त किए जाने की स्थिति में भारत को संबद्ध आयातों में उछाल आ जाएगा।
- च. भारत संबद्ध देश के लिए सर्वाधिक आकर्षक बाजार है क्योंकि संबद्ध देश का भारत में पाटन का लंबा इतिहास रहा है। भारत उनके सबसे बड़े निर्यात गंतव्यों में से एक है। संबद्ध वस्तुओं के महत्वपूर्ण चीनी उत्पाद निर्यात किए जा रहे हैं और यूएसए और ईयू में मांग में गिरावट आ रही है।
- छ. निर्यातक प्रभावली के उत्तरो के विश्लेषण दर्शाता है कि पाटन की संभावना और परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को क्षति की संभावना मौजूद है। भारत को निर्यातों में वृद्धि हुई है जबकि तीसरे देशों को निर्यातों में गिरावट आई है। पीवीआईटी में महत्वपूर्ण कमी आई है और मालसूची, निर्यातकों द्वारा उत्पादन और क्षमताओं के साथ ही घरेलू और निर्यात विक्रियों के बीच भेदभाव पूर्ण कीमत निर्धारण में वृद्धि हुई है।
- ज. उत्पादन सुविधाओं की परस्पर विनिमय क्षमता स्वयं में स्थापित करती है कि उत्पादक बाजार स्थितियों के अनुसार अपने उत्पादन बदल सकते हैं। पाटनरोधी शुल्क को समाप्त किए जाने की स्थिति में, उत्पादक आसानी से विचाराधीन उत्पाद के अपने उत्पादन को बढ़ा सकते हैं और भारत को निर्यात में वृद्धि कर सकते हैं।
- झ. जेजियांग क्यूहुआ फ्लोर-कमेस्ट्री कंपनी ने वर्ष 2018 में अपनी क्षमता को 17 प्रतिशत बढ़ाया है।
- ञ. विचाराधीन उत्पाद अगले पांच वर्षों में चरणबद्ध रूप में बाहर नहीं हो रहा है और घरेलू उद्योग ने केवल अगले 5 वर्षों के लिए शुल्कों के विस्तार के लिए अनुरोध किया है। इसके अलावा, यदि विचाराधीन उत्पाद 5 वर्षों के भीतर बाहर हो जाता है तो संबद्ध निर्यातक पर पाटनरोधी शुल्क के विस्तार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
- ट. चूंकि, केवल कुछ ही निर्यातकों ने उत्तर प्रस्तुत किया है, उन की क्षमताओं पर चीन जन.गण. में पूर्ण क्षमता के रूप में विचार नहीं किया जाना चाहिए।

**व.3 प्राधिकारी द्वारा जांच**

102. प्राधिकारी के नोटिस में लाए गए सभी कारकों की यह निर्धारित करने के लिए जांच की गई है कि क्या शुल्क को समाप्त किए जाने की स्थिति में पाटन और क्षति के जारी रहने या पुनरावृत्ति की संभावना है। प्राधिकारी ने पाटन और क्षति के जारी रहने या पुनरावृत्ति की संभावना का मूल्यांकन करने की दृष्टि से घरेलू उद्योग और अन्य हितवद्ध पक्षकारों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना पर विचार किया है।
103. प्राधिकारी ने नियम 23 खंड 9(5) के तहत निर्धारित की गई अनिवार्यताओं और नियमावली के अनुबंध- II (vii) के संदर्भ में महत्वपूर्ण क्षति के खतरे से संबंधित मानदंडों और हितवद्ध पक्षकारों के द्वारा रिकॉर्ड पर प्रस्तुत किए गए अन्य संबंधित कारकों पर विचार करते हुए क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति की संभावना की जांच की है। वर्तमान जांच चीन जन.गण. से संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर पहले लागू किए गए एडीडी की निर्णायक समीक्षा है। नियमावली के तहत, प्राधिकारी द्वारा यह निर्धारित किया जाना जरूरी है कि क्या एडीडी को लगातार लागू किए जाने की जरूरत है। यह विचार किए जाने की भी जरूरत है कि क्या लागू किया गया शुल्क क्षति कारक पाटन को समाप्त करने के अभिप्रेरित प्रयोजन को पूरा कर रहा है। ऐसी संभावना विश्लेषण को आयोजित करने के लिए कोई विशिष्ट कार्य प्रणाली उपलब्ध नहीं है। तथापि, नियमावली के अनुबंध – II की धारा (vii) में अन्य बातों के साथ-साथ, ऐसे कारकों के लिए व्यवस्था की गई है जिन्हें ध्यान में रखे जाने की जरूरत है अर्थात:-
- भारत में पाटित आयातों की वृद्धि की महत्वपूर्ण दर, जो उल्लेखनीय रूप से बड़े हुए आयातों की संभावना की ओर संकेत करती है।
  - निर्यातक की क्षमता में पर्याप्त रूप से मुक्त रूप से निस्तारणीय या आसन्न महत्वपूर्ण वृद्धि जो किसी अतिरिक्त आयातों को अवशोषित करने के लिए अन्य निर्यात बाजारों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए, भारतीय बाजारों को महत्वपूर्ण रूप से बड़े हुए पाटित आयातों की संभावना की ओर इंगित करती है।
  - क्या आयात ऐसी कीमतों पर प्रवेश कर रहे हैं जिनका घरेलू कीमतों पर ह्रासकारी या न्यूनीकरण प्रभाव होगा और जो संभवतः और अधिक आयातों के लिए मांग में वृद्धि करेंगे।
  - वस्तु की मालसूचियों की जांच की जा रही है।

**i. जारी और विद्यमान पाटन और क्षति**

104. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच की वर्तमान अवधि में विचाराधीन उत्पाद के आयात, पाटनरोधी शुल्क की विद्यमानता के बावजूद पाटित कीमतों पर हैं। यह भी नोटिस किया गया कि लाभों, नकद लाभों, और नियोजित पूंजी पर आय के संबंध में घरेलू उद्योग के निष्पादन में उल्लेखनीय रूप से ह्रास हुआ है। यह भी देखा गया है कि संबद्ध आयात घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती कर रहे हैं।

**ii. संबद्ध देश में अतिरिक्त क्षमताएं**

105. उत्तर देने वाले निर्यातकों द्वारा दायर प्रश्नावली उत्तरों का विश्लेषण निम्नानुसार दर्शाता है:-

विवरण - पीओआई	सिनोकेम एन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन केमिकल्स (ताइकैंग) कं. लि.	शांक्सी सिनोकेम लानतियान न्यू केमिकल मैटिरियल कं. लि.	शानडोंग डोंगयुई केमिकल कं. लि.	झेजियांग सनमेई केमिकल इन्ड. कं. लि.	झेजियांग क्यूहुआ फ्लुओर केमिस्ट्री कं. लि.	झेजियांग क्यूझोऊ लियानझोऊ रेफ्रिजरेटर्स कं. लि.	सिनोकेम एन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन केमिकल्स (क्सियान कं. लि.)	कुल
क्षमता - (एमटी)	***	***	***	***	***	***	***	1,71,000
उत्पादन- (एमटी)	***	***	***	***	***	***	***	1,49,871
क्षमता उपयोग -	***	***	***	***	***	***	***	88

(%)								
घरेलू विक्रियां- (एमटी)	***	***	***	***	***	***	***	1,07,817
भारत को निर्यात- (एमटी)	***	***	***	***	***	***	-	1,084
अन्य देशों को निर्यात - (एमटी)	***	***	***	***	***	***	-	63,019

106. रिकॉर्ड पर उपलब्ध सूचना के अनुसार, संबद्ध देश में संबद्ध वस्तुओं के उत्पादकों के पास हैं:-

- क. भारतीय मांग की तुलना में बहुत अधिक क्षमताएं; प्रतिवादी चीनी उत्पादकों की अप्रयुक्त क्षमता भारत में संबद्ध वस्तुओं की मांग का 8 गुना है।
- ख. अन्य देशों को महत्वपूर्ण निर्यात जो कि एडीडी की समाप्ति की स्थिति में भारत की ओर मोड़ा जा सकता है। अमेरिका और यूरोपीय संघ जैसे प्रमुख बाजारों में मांग में गिरावट को ध्यान में रखते हुए, जैसा कि नीचे चर्चा की गई है, भारत व्यापार मोड़ के लिए एक संभावित गंतव्य बन गया है।

### iii. अन्य प्रमुख बाजारों में मांग में गिरावट

107. आवेदक ने यह दर्शाने के लिए साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं कि क्योटो प्रोटोकॉल के अनुसमर्थन के पश्चात् यूएसए और ईयू द्वारा अपने क्षेत्राधिकार के भीतर संबद्ध वस्तु के प्रयोग को समाप्त करने के लिए उपाय किए गए हैं। उत्तर देने वाले उत्पादकों/निर्यातकों ने भी स्वीकार किया है कि उत्पाद के प्रयोग पर प्रतिबंध के कारण ईयू और यूएसए जैसे प्रमुख बाजारों में मांग में गिरावट के कारण ऐसे देशों को संबद्ध वस्तुओं के निर्यातों में गिरावट आ सकती है। आवेदक का कहना है कि विद्यमान शुल्कों की समाप्ति की स्थिति में, भारत चीन जन.गण. में संबद्ध वस्तुओं के उत्पादकों द्वारा व्यापार विपथन का लक्ष्य बन जाएगा।

### iv. यूएसए द्वारा एडीडी को लागू करना

108. आवेदक ने अनुरोध किया है कि रिकॉर्ड पर उपलब्ध सूचना के अनुसार, 2017 के बाद से यूएसए में चीन जन.गण. से संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर व्यापार उपचारात्मक उपाय स्थापित किए गए हैं। चीन जन.गण. में उत्पादक और निर्यातक यूएस में विचाराधीन उत्पाद का पाटन कर रहे हैं। चीन जन.गण. से विचाराधीन उत्पाद के निर्यातक और उत्पादक पाटनरोधी शुल्क के प्रवृत्ति होने के बावजूद भारत में विचाराधीन उत्पाद का पाटन कर रहे हैं। आवेदक का कहना है कि यह स्पष्ट रूप से स्थापित करता है कि पाटनरोधी शुल्क को समाप्त किए जाने की स्थिति में, संबद्ध देश से उत्पादक/निर्यातक भारत में उत्पादन का पाटन करना जारी रखेंगे।

### v. भारतीय बाजार की आकर्षकता

109. यह भी देखा गया है कि संबद्ध देश से आयात पीओआई के दौरान घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती कर रहे हैं और कीमत कटौती महत्वपूर्ण है, जो यह सुझाव देता है कि इस समय स्थापित एडीडी की समाप्ति के कारण घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाने वाले पाटन के और गहन होने की संभावना है।
110. निम्नलिखित निर्यातकों ने निर्णायक समीक्षा जांच के लिए संगत, प्रश्नावली उत्तर सहित, निर्धारित प्रपत्र और तरीके में प्रश्नावली उत्तर दायर किए हैं। इसलिए, प्राधिकारी ने प्रश्नावली उत्तर की जांच की है और सामान्य मूल्य (अर्थात् पाटित) और क्षति कारक कीमतों (अर्थात् घरेलू उद्योग के एनआईपी से कम पर) से कम कीमतों पर तीसरे देशों को इन निर्यातकों द्वारा निर्यातों की मात्रा को सुनिश्चित किया है।
111. नीचे दी गई सारणी पाटित और क्षतिकारक कीमतों पर तीसरे देशों को इन निर्यातकों द्वारा निर्यातों की मात्रा को दर्शाती है:-

पैरामीटर	सिनोकेम एन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन केमिकल्स (ताइकैंग) कं. लि.	शांक्सी सिनोकेम लानतियान न्यू केमिकल मैटिरियल कं. लि.	शानडोंग डोंगयुई केमिकल कं. लि.	झेजियांग सनमेई केमिकल इन्ड. कं. लि.	झेजियांग क्यूहुआ फ्लुओर केमिस्ट्री कं. लि.	झेजियांग क्यूझोऊ लियानझोऊ रेफ्रिजरेटर्स कं. लि.	सिनोकेम एन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन केमिकल्स (क्सियान कं. लि.)	कुल
एनआईपी से कम मात्रा	***	***	***	***	***	***	***	63,422
एनआईपी से अधिक मात्रा	***	***	***	***	***	***	***	161
सामान्य मूल्य से कम मात्रा	***	***	***	***	***	***	***	63,072
सामान्य मूल्य से अधिक मात्रा	***	***	***	***	***	***	***	512
भारत में मांग	***	***	***	***	***	***	***	
भारत में मांग के प्रतिशत के रूप में सामान्य मूल्य/एनआईपी से निम्न निर्यात मात्रा								
सामान्य मूल्य	***	***	***	***	***	***	***	>700%
एनआईपी	***	***	***	***	***	***	***	>700%

112. यह देखा गया है कि

क. इन निर्यातकों द्वारा तीसरे देशों को निर्यातों की महत्वपूर्ण मात्रा पाटित और क्षतिकारक कीमतों पर हैं (लगभग 99%)।

ख. तीसरे देशों को पाटित/हानिकारक कीमतों पर निर्यात की मात्रा भारत में संबद्ध वस्तुओं की मांग का 8 गुना है।

#### vi. संबद्ध देशों में उत्पादकों का निर्यात उन्मुखीकरण

113. उत्तरों से प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध देशों में उत्पादक निर्यातोन्मुखी हैं।

#### पाटन और क्षति की संभावना के संबंध में निष्कर्ष

114. रिकॉर्ड पर उपलब्ध साक्ष्य यह दर्शाता है कि वर्तमान जांच की अवधि में विचाराधीन उत्पाद के आयात, पाटनरोधी शुल्क मौजूद होने के बावजूद पाटित कीमतों पर हैं। चीन के प्रतिवादी निर्यातकों के पास क्षमताएं, भारतीय मांग से काफी अधिक हैं। चीन के प्रतिवादी उत्पादकों की अप्रयुक्त क्षमताएं भारत में संबद्ध वस्तुओं के लिए मांग की 8 गुणा हैं। अन्य देशों को महत्वपूर्ण निर्यात किए गए हैं, जो पाटनरोधी शुल्क समाप्त होने की स्थिति में भारत को अन्तरित किए जा सकते हैं। बड़े बाजारों जैसे यूएस और यूरोपीय संघ में मांग में गिरावट के संबंध में विचार करते हुए, भारत व्यापार को अन्तरित करने के लिए एक संभावित स्थान बन सकता है। चीन जन. गण. से यूएसए में संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर व्यापार उपचारी उपाय लागू हैं। चीन जन. गण. से विचाराधीन उत्पाद के निर्यातक और उत्पादक, पाटनरोधी शुल्क लागू रहने के बावजूद भारत में विचाराधीन का पाटन कर रहे हैं। संबद्ध देश से आयातों के कारण जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती हो रही है और कटौती का मार्जिन महत्वपूर्ण है, जो यह सुझाव देता है कि वर्तमान में लागू पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति होने से घरेलू उद्योग को क्षति के लिए जिम्मेदार पाटन में तेजी आने की संभावना है। संबद्ध निर्यातकों द्वारा अन्य देशों को निर्यातों की महत्वपूर्ण मात्रा (करीब 90 प्रतिशत), पाटित और क्षतिकारी कीमतों पर हैं। संबद्ध देश में उत्पादक निर्यातोन्मुखी हैं। संबद्ध देश से अन्य देशों को निर्यात कीमत ऐसी कीमत से कम हैं, जिस पर भारत में उत्पाद का निर्यात किया



जा रहा है। भारत प्रतिवादी निर्यातकों के लिए कीमतों का आकर्षक बाजार है और पाटनरोधी शुल्क समाप्त होने की स्थिति में, चीन जन. गण. के आयातों में पाटन कीमत पर वृद्धि होने की संभावना है, जिनके कारण घरेलू उद्योग को क्षति हो रही है। उपरोक्त को देखते हुए, प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि मौजूदा पाटनरोधी शुल्क समाप्त होने की स्थिति में पाटन और क्षति की संभावना है।

## ट. प्रकटन पश्चात अनुरोध

### ट.1 अन्य हितवद्ध पक्षकारों के विचार

115. अन्य हितवद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित प्रकटीकरण के उपरांत की टिप्पणियां की गई हैं:-

- क. पर्याप्त क्षति की आशंका के संबंध में मापदंडों पर विचार करने के लिए संगत सही तथ्यों पर विचार किया गया है और इसलिए यह अनुरोध किया जाता है कि अनुबंध-II (vii) की सानमेई के लिए अलग से जांच की जाए।
- ख. क्षति की संभावना के दावे अप्रमाणित हैं और जांच की अवधि में आयातों में मामूली वृद्धि को संभावना के लिए आधार नहीं माना जा सकता। इसके अलावा, सानमेई ने अन्य देशों को उच्चतर कीमत पर अधिक मात्रा में निर्यात किया है और कंपनी की वस्तुसूची के स्तर में भी जांच की अवधि के दौरान काफी कमी आई है।
- ग. अन्य देशों में बाजार की हानि क्षति के कारण से नहीं है, क्योंकि सानमेई से भारत को विगत वर्षों के दौरान संबद्ध आयातों में गिरावट आई है और जांच की अवधि के दौरान यह सबसे कम दर्ज किया गया है।
- घ. अन्य कारकों जैसे अन्य देश के आयात, मांग में गिरावट आदि पर प्राधिकारी द्वारा समुचित ध्यान दिया जाना है।
- ङ. याचिकाकर्ता संदेह से परे यह स्थापित करने में विफल हुआ है कि मौजूदा पाटनरोधी शुल्क समाप्त होने से घरेलू उद्योग को पाटन और क्षति जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है, जैसा कि पाटनरोधी नियमावली के नियम 23(1ख) में उल्लेख किया गया है। इसके विपरीत, कंपनी द्वारा किए गए अनुरोधों में, वर्तमान शुल्कों की समाप्ति होने की स्थिति में घरेलू उद्योग को पाटन और क्षति जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना का अभाव दर्शाया गया है।
- च. वर्तमान मामले के तथ्य स्पष्ट रूप से यह दर्शाते हैं कि याचिकाकर्ता को कोई क्षति नहीं हुई और याचिकाकर्ता को चीन जन.गण. से विचाराधीन उत्पाद के आयातों के कारण कोई क्षति होने की संभावना नहीं है क्योंकि उनके निष्पादन पर चीन जन.गण. से आयातों द्वारा प्रभाव नहीं पड़ा है बल्कि अन्य कारणों से प्रभाव पड़ा है। समग्र स्थिति संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर लागू वर्तमान पाटनरोधी शुल्कों की समाप्ति को न्यायोचित दर्शाती हैं।
- छ. यूएसए से विचाराधीन उत्पाद प्राथमिक तौर पर बिना पैक किए गए रूप में हैं और चीन जन.गण. से विचाराधीन उत्पाद अधिकतर पैक किए गए रूप में होता है। इस प्रकार यूएसए को एक उचित प्रतिनिधि के रूप में नहीं माना जा सकता।
- ज. याचिका में यूएसए की आयात कीमत के आधार पर सामान्य मूल्य अपनाया गया है, जो कि प्रकट किए गए निर्मित सामान्य मूल्य से भिन्न है। यह स्पष्ट नहीं है कि कैसे यूएसए से 291 रुपए/कि.ग्रा. की आयात कीमत का 356 रु./कि.ग्रा. के परिकलित सामान्य मूल्य के लिए उपयोग किया जा सकता है।
- झ. प्रकटीकरण विवरण यह नहीं कहता है कि क्या समुद्री मालभाड़ा, बीमा, ऋण लागत आदि के समायोजन, यूएसए से आयात कीमत के लिए किए गए थे ताकि इस समीक्षा के प्रयोजन के लिए सामान्य मूल्य के रूप में विचार किए जाने से पूर्व कारखाना बाह्य कीमत के समान लाया जा सके।
- ञ. उत्पादन और खपत के संबंध में आयातों की मात्रा में क्षति जांच की अवधि के दौरान कमी आई है। उत्पादन और खपत के संबंध में आयातों की मात्रा में, आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में क्रमशः 35 और 22 इंडेक्स प्वाइंट के बीच आयात की मात्रा में वृद्धि सामान्य है।
- ट. घरेलू उद्योग की मांग में बाजार अंश में आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में 16 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है, जबकि संबद्ध आयातों में गिरावट आई है।
- ठ. वर्ष 2018-19 में कीमत कटौती क्षति अवधि में सबसे कम अर्थात् 0-10 प्रतिशत पर थी, जबकि उसी वर्ष में पहुंच कीमत सबसे अधिक अर्थात् 332 रु./कि.ग्रा. थी। तथापि, घरेलू उद्योग ने वर्ष 2018 में प्रति यूनिट लाभ में सबसे तेज

- कटौती का सामना किया। जांच की अवधि में घरेलू उद्योग के निष्पादन में वह अवधि शामिल है, जब कोविड-19 महामारी अपने पीक पर थी।
- ड. यूएस में शुल्क मौजूद रहने के कारण चीन जन.गण. से भारत को इस तथ्य के कारण विचाराधीन उत्पाद के निर्यातों के लिए प्रत्यक्ष रूप से निर्यात स्थान का विकल्प नहीं मिलेगा क्योंकि भारतीय बाजार में मांग में आधार वर्ष से जांच की अवधि तक तीव्र गिरावट आई है। यूएस द्वारा शुल्क लगाए जाने के बावजूद, भारत निर्यातकों के लिए आकर्षक नहीं होगा क्योंकि मांग में गिरावट आ रही थी।
- ढ. प्राधिकारी ने यह कहा है कि संबद्ध देशों में उत्पादक निर्यात अभिमुखी है। तथापि, प्रतिवादियों की घरेलू बिक्रियां, भारत में उनके निर्यातों से काफी अधिक हैं, अतः वे निर्यातोन्मुखी नहीं हैं और उनका प्राथमिक बाजार घरेलू है।
- ण. निवल निर्यात कीमत और डीजीटीआर द्वारा निर्धारित पहुंच कीमत और वास्तविक अनुरोध के बीच काफी अन्तर है। प्रतिभागी उत्पादकों/निर्यातकों, दोनों के लिए कारखाना बाह्य निर्यात कीमत और पहुंच मूल्य की गणना अलग-अलग की जानी है और उसके बाद प्रतिभागी उत्पादकों/निर्यातकों, दोनों के लिए समूह के रूप में भारत औसत कारखाना बाह्य कीमत और पहुंच मूल्य की गणना की जानी है।
- त. विचाराधीन उत्पाद के पैक किए गए और पैक न किए गए रूपों के लिए अलग विश्लेषण करके पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन का निर्धारण करने के लिए भारी से भारी और पैक से पैक तुलना की जानी चाहिए।
- थ. प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किया गया निर्मित सामान्य मूल्य और क्षति रहित कीमत काफी अधिक है और अनुचित/बढ़ा चढ़ा कर पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन को दर्शाने से बाजार में एकाधिकार होगा, जिसके कारण प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण को काफी हानि होगी और भारतीय उद्योगों के बेहतर विकास के लिए नुकसानदेह होगा।
- द. चीन जन.गण. से विचाराधीन उत्पाद के आयातों के संदर्भ में 36 प्रतिशत तक की पर्याप्त कटौती हुई है। जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की निवल बिक्री कीमत में पर्याप्त वृद्धि हुई है, जो यह साबित करता है कि याचिकाकर्ता को हुई हानि चीन जन.गण. से आयातों के कारण नहीं है।
- ध. नियोजित पूंजी पर 22 प्रतिशत का एक तर्कसंगत प्रतिफल काफी बढ़ा कर दिखाया गया है और घरेलू उद्योग को अनुचित फायदा और संरक्षण प्रदान करता है। महानिदेशक को विगत में, जब पाटन का कोई आरोप नहीं था, याचिकाकर्ता द्वारा अर्जित प्रतिफल पर तर्कसंगत प्रतिफल के रूप में विचार करना चाहिए और उसे, क्षतिरहित कीमत निकालने के लिए तर्कसंगत प्रतिफल के रूप में अपनाना चाहिए।
- न. चीन जन.गण. से उत्पादकों/निर्यातकों के पास कोई सरप्लस क्षमताएं नहीं हैं, क्योंकि सिनोकेम एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन कैमिकल्स (टाइकांग) कं. लि. पहले से ही 100 प्रतिशत से अधिक क्षमता उपयोग पर प्रचालन कर रहा है। इस प्रकार, चीन जन.गण. में निष्क्रिय क्षमताएं और आसानी से निपटाई जाने योग्य क्षमताएं पूरी तरह से अस्वीकार की जानी चाहिए क्योंकि इस मामले में संभावना का निर्धारण करने के लिए कोई भी संगत आधार, आयातों की ऐतिहासिक मात्रा के रूप में, ऐसे दावों को किसी मेरिट से वंचित होने के रूप में निष्प्रभावी करती है। इंडियन स्पिनर्स एसोसिएशन बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी (2004(170) ईएलटी 144) मामले का हवाला दिया गया है।
- प. आवेदक ने वित्तीय वर्ष 2019-20 में हानि उठाई, जब क्षमता में आगे वृद्धि की गई थी। क्षमता में वृद्धि की गई, जबकि मौजूदा क्षमता का उपयोग भी नहीं हो पाया और ऐसे स्वयं के दर्शाए गए कारकों को संबद्ध आयातों के लिए जिम्मेदार नहीं माना जाना चाहिए।
- फ. जैसा कि एसआरएफ लिमिटेड की वार्षिक रिपोर्ट 2019-20 में उल्लेख किया गया है, याचिकाकर्ता के खिलाफ फ्लूरोकैमिकल्स बिजनेस में 13 प्रतिशत ग्राहक शिकायतें दर्ज हैं, जो यह तथ्य दर्शाती हैं कि एसआरएफ लिमिटेड में उत्पादित विचाराधीन उत्पाद घटिया क्वालिटी का है, जो उन्हें विचाराधीन उत्पाद के क्वालिटी ग्रेड और विशिष्ट ग्रेड का उत्पादन करने से रोकता है।
- ब. न केवल याचिकाकर्ता के पास उत्तम कीमत क्षमता है, बल्कि चीन जन.गण. से पहुंच कीमत और याचिकाकर्ता की लाभप्रदता के बीच एक विपरीत संबंध है।

- भ. जब पहुंच कीमत आधार वर्ष के दौरान 270 रु./कि.ग्रा. से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान 304 रु./कि.ग्रा. होती है, लाभप्रदता 100 से (12) प्वाइंट बढ़ती है, जो यह दर्शाता है कि यह आयात नहीं है, जो याचिकाकर्ता के लाभों को रोकता है। इसके अलावा, जब जांच की अवधि और विगत वर्ष के बीच पहुंच कीमत में गिरावट आई है, घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में (12) प्वाइंट से 11 प्वाइंट तक वृद्धि हुई है और यदि याचिकाकर्ता पर पहुंच कीमत में गिरावट का प्रभाव पड़ता तो विक्री कीमत में वृद्धि संभव नहीं होती।
- म. पाटनरोधी शुल्क 12 वर्षों से लागू रहा है। घरेलू उद्योग द्वारा प्रदान की गई सूचना किसी विशेष परिस्थिति की मौजूदगी को नहीं दर्शाती, जिसके कारण कि पाटनरोधी शुल्क को 12 वर्षों की अवधि से आगे जारी रखने की जरूरत है। ड्राई सेल बैट्रियों में जांच परिणामों पर निर्भरता की गई है, जहां पर कि प्राधिकारी विशेष मामले को छोड़कर 10 वर्षों की अवधि से आगे शुल्क को जारी नहीं रखते।

## ट.2 घरेलू उद्योग के विचार

116. घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित प्रकटीकरण के उपरांत की टिप्पणियां की गई हैं:-

- क. सिनोकैम टाइकांग के लिए यह सुनिश्चित करने की वाध्यता है कि भारत को संबद्ध आयातों की समस्त निर्यात विक्रियों को शामिल किया जाए। उन्होंने अपने प्रश्नावली उत्तर में भारत को संबद्ध विक्रियों के लिए वस्तुओं के विपणन के माध्यम के संबंध में भ्रामक और गलत सूचना प्रदान की है।
- ख. सिनोकैम टाइकांग ने इस तथ्य को छिपाया है कि उनका एक निर्यातक असहयोगी रहा है। यह घरेलू उद्योग के अधिकारों का हनन है और ऐसी सूचना की मिथ्या घोषणा के कारण उत्तर को अस्वीकार किया जाना चाहिए। निर्यातक प्रश्नावली का अनुदेश 4 और उत्पादक द्वारा दाखिल प्रमाण-पत्र तथा कानूनी प्रतिनिधि द्वारा की गई घोषणा पर भरोसा किया गया है।
- ग. प्राधिकारी असहयोगी व्यापारी के माध्यम से सिनोकैम टाइकांग के निर्यातों के हिस्से को नोट करने में विफल रहे हैं।
- घ. असहयोगी असंबद्ध निर्यातक के पास विक्री चैनल के लिए निर्यात कीमत की गणना, सिनोकैम टाइकांग से संबद्ध वस्तुओं की कारखाना बाह्य व्ययों के लिए समायोजित पहले निर्यातक की विक्री कीमत के आधार पर की जानी चाहिए।
- ड. असहयोगी असंबद्ध निर्यातक, हनीवेल ट्रेडिंग (शंघाई) कं. लि. की असहयोग करने की प्रथा रही है, जबकि वह भारत को काफी मात्रा में निर्यात करता रहा है। चीन जन.गण. से एक प्रतिवादी उत्पादक का, उसी निर्यातक द्वारा असहयोग किए जाने के कारण “एचएफसी घटक आर-32” के संबंध में पाटनरोधी जांच में हाल के अन्तिम जांच परिणाम में असहयोगी पाया गया था।
- च. वर्तमान जांच में शेष पाटन मार्जिन, विगत की जांचों की तुलना में तीन गुणा हो गया है। वर्तमान शेष क्षति मार्जिन विगत की जांचों के क्षति मार्जिन की तुलना में काफी अधिक भी है। चीन के आयातों के क्षतिकारी प्रभाव में हर जांच में वृद्धि हुई है। पाटनरोधी नियमावली के नियम 23(1) के तहत पाटनरोधी शुल्क की मात्रा में वृद्धि की जाए, यदि ऐसे पाटन पर प्रतिक्रिया करनी है तो, जो कि क्षति का कारण है। अतः पाटनरोधी शुल्क में वृद्धि आवश्यक है।
- छ. प्राधिकारी यूके से भारत को संबद्ध वस्तुओं के आयातों के आधार पर सामान्य मूल्य का निर्धारण कर सकते हैं, क्योंकि चीन जन.गण. के लिए यूके एक उपयुक्त प्रतिनिधि देश है। इस पर सूचना, पैक और बिना पैक रूप में अलग-अलग की गई है, जो घरेलू उद्योग द्वारा पहले ही प्रदान की जा चुकी है। यूके भारत को, समान निर्माण प्रक्रिया का उपयोग करके एक प्रमुख उत्पाद और निर्यातक भी है। यूके से भारत को आयातित संबद्ध वस्तुएं चीन जन.गण. से आयातित संबद्ध वस्तुओं और भारत में उत्पादित संबद्ध वस्तुओं के समान वस्तु हैं।
- ज. घरेलू उद्योग अपनी विक्री लागत पर उनके कीमत संबंधी निर्णयों के लिए आधार बनाने में असमर्थ रहा है। चूंकि संबद्ध आयातों से केवल कटौती ही नहीं हो रही बल्कि घरेलू उद्योग की विक्री की लागत से भी काफी कम है, जो भारतीय बाजार में विचाराधीन उत्पाद के लिए कीमत संबंधी मापदंड के रूप में कार्य करता है। जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग विक्री कीमत में कमी करने पर मजबूर था जबकि लागतों में वृद्धि होने से लाभों में काफी कटौती हो रही थी। इसके अलावा, प्राधिकारी एक कारणात्मक संबंध का निष्कर्ष दे सकते हैं।

- झ. निम्नलिखित को देखते हुए पाटनरोधी शुल्क की समामि की स्थिति में पाटन और क्षति के जारी रहने/पुनरावृत्ति होने की संभावना है:-
- i. चीन के उत्पादकों की मात्रा 38 प्रतिशत अप्रयुक्त क्षमता ही समग्र भारतीय मांग की पूर्ति के लिए पर्याप्त है। प्रतिवादी निर्यातकों के क्षमता उपयोग में जांच की अवधि में गिरावट आई है, जो यह दर्शाता है कि वे अधिक क्षमता उपयोग कर पाने में समर्थ हैं। चीन के उत्पादक काफी वस्तुसूचियां रखते हैं, जिसके लिए प्राधिकारी से अनुरोध है कि वे जांच करें। चूंकि यूरोपीय संघ और यूएसए संबद्ध वस्तुओं को हटा रहे हैं, अतः चीन के उत्पादकों के अन्य देशों के निर्यातों को, जो कि भारतीय मांग का 8 गुना है, काफी हद तक भारत को भेजे जाएंगे। चूंकि मोन्ट्रियल प्रोटोकॉल के लिए किगाली संशोधन के अनुसार वर्ष 2023 के बाद भारत को संबद्ध वस्तुओं के लिए क्षमता बढ़ाने की अनुमति नहीं है और चीन जनगण. ने काफी अधिक सरप्लस क्षमताएं स्थापित की हैं, अतः चीन के उत्पादकों को उत्पाद का पाटन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। पाटनरोधी शुल्क समाम होने की स्थिति में, भारत को संबद्ध आयातों में वृद्धि होगी। घरेलू उद्योग का संरक्षण करने में विफल होने से एचएफसी इंडस्ट्री की ऑटोमोबाइल निर्माण आपूर्ति चेन कमजोर होगी।
  - ii. चूंकि सामान्य मूल्य घरेलू उद्योग के विक्री मूल्य से कम है, अतः अन्य देश के निर्यात भी जो कि सामान्य मूल्य से कम हैं, घरेलू उद्योग की विक्री कीमत से कम हैं, जिससे भारतीय बाजार आकर्षक बनता है। प्राधिकारी से अनुरोध किया जाता है कि अन्य देशों को निर्यातों के लिए और भारत को निर्यातों के लिए कीमतों की तुलना की जाए, क्योंकि इससे पता चलेगा कि काफी मात्रा में निर्यात, भारत को पाटनरोधी शुल्क के साथ निर्यात कीमत से कम कीमत पर हैं, जिससे भारतीय बाजार आकर्षक बनता है।
  - iii. यूएसए और यूरोपीय संघ में मांग में गिरावट पर विचार करते हुए, भारत को निर्यात, प्राधिकारी इस जांच परिणाम के आलोक में वृद्धि के लिए बाध्य हैं कि प्रतिवादी उत्पादक निर्यात उन्मुखी हैं।
- ञ. किसी भी प्रयोक्ता/आयातक ने पाटनरोधी शुल्क को न लगाने के लिए कोई संगत सूचना प्रदान नहीं की है। केवल आयातक ही हितवद्ध पक्षकार हैं, जो उनकी अनुचित व्यापार प्रक्रिया से संरक्षण की मांग कर रहे हैं। प्रयोक्ताओं/आयातों की कम भागीदारी यह दर्शाती है कि उन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं है।
- ट. निम्नलिखित यह दर्शाता है कि पाटनरोधी शुल्क का उपभोक्ताओं पर और जनता पर व्यापक रूप से कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं है:-
- i. पाटनरोधी शुल्क का विस्तार ऐसे घरेलू निर्यातकों के निष्पादन में गिरावट को रोकेगा, जो पाटन के कारण क्षति का सामना कर रहे हैं। यद्यपि कोई मांग-आपूर्ति अन्तर नहीं है, लेकिन घरेलू उद्योग के पास केवल 56 प्रतिशत बाजार अंश और 57 प्रतिशत क्षमता उपयोग है।
  - ii. यदि घरेलू उद्योग को क्षति का सामना करने दिया जाता है तो वे समाम हो जाएंगे और चीन के आयातों का समग्र एकाधिकार होगा। भारतीय उपभोक्ता उनकी दया पर रहेंगे और उन्हें अधिक वस्तु सूचियां रखनी होगी और इसके लिए अधिक व्यय करना होगा। घरेलू उद्योग से खरीद करने से, उचित कीमत स्थिरता, अबाध आपूर्ति, डाउनस्ट्रीम उद्योग का विकास और एक स्थिर व विश्वसनीय कारोबारी भागीदारी सुनिश्चित होगी।
  - iii. यह लोक हित में है कि संबद्ध वस्तुओं का एक सशक्त, प्रतिस्पर्धी घरेलू उत्पादन हो, पाटनरोधी शुल्क का उद्देश्य कीमत को ठीक करना और यूएसए तथा यूके से आयातों को प्रोत्साहित करके उचित प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करना है।
  - iv. अन्तिम उत्पाद में विचाराधीन उत्पाद की लागत बहुत ही कम है और उनका अन्तिम प्रयोक्ताओं पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा।
  - v. घरेलू उद्योग ने वर्ष 2011 में पाटनरोधी शुल्क लगाकर भारत को आत्म-निर्भर बनाने के लिए भारी निवेश करके अपनी क्षमता को चार गुणा किया है। घरेलू उद्योग भारत में वर्तमान और भावी मांग को पूरा कर सकता है। यदि क्षति जारी रहती है तो इन निवेशों पर दीर्घावधि प्रतिफल प्राप्त नहीं होगा।
  - vi. पाटित आयातों के अभाव में, घरेलू उद्योग का क्षमता उपयोग वर्तमान में 57 प्रतिशत की तुलना में 87 प्रतिशत होता।

- vii. चूंकि भारत को वर्ष 2023 के बाद संबद्ध वस्तुओं के संबंध में क्षमता बढ़ाने की अनुमति नहीं होगी, घरेलू उद्योग निवेश किए हैं और क्षमताएं बढ़ाई हैं। घरेलू एचएफसी उद्योग को सुरक्षा प्रदान करना आवश्यक है, ताकि मौजूदा निवेश को संरक्षित किया जा सके और नए निवेश को प्रोत्साहित किया जा सके।
- viii. घरेलू उद्योग द्वारा एचएफसी के लिए नवोन्मेषी और व्यवहार्य विकल्पों को अपनाकर भारत को उद्योग में एक वैश्विक प्रतिस्पर्धा प्रदान की जाएगी और विकास को बढ़ावा दिया जाएगा। यदि क्षति जारी रहती है तो घरेलू उद्योग विकल्पों को विकसित करने के लिए आर एंड डी में निवेश नहीं कर पाएगा।
- ix. अन्य स्रोत भी मौजूद हैं, जो भारत को संबद्ध वस्तुओं का निर्यात करते हैं और उनका काफी बाजार अंश है। चूंकि संबद्ध वस्तुएं यूरोपीय संघ और यूएसए में बाहर की जा चुकी हैं, कोई भी उत्पादन भारत सहित निर्यात बाजारों के लिए ही होगा। पाटनरोधी शुल्क का विस्तार होने से न तो घरेलू उद्योग को एकाधिकार मिलेगा और न ही संबद्ध वस्तुओं की उपलब्धता पर प्रभाव पड़ेगा।
- x. घरेलू उद्योग, पाटन के बावजूद सकारात्मक व्यापार संतुलन बनाए रखने में समर्थ है। यदि क्षति को जारी रहने दिया जाता है, तो इसे बनाए नहीं रखा जा सकता।

### ट.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

117. प्राधिकारी ने सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए प्रकटीकरण के उपरांत के अनुरोधों की जांच की है और यह नोट करते हैं कि कुछ तर्क पुनः दिए गए हैं, जिनमें पहले ही समुचित रूप से जांच की जा चुकी है और जांच परिणामों के संगत पैरा में पर्याप्त रूप से शामिल किए जा चुके हैं। प्रकटीकरण के उपरांत की टिप्पणियों/ अनुरोधों में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा पहली बार उठाए गए मामले और जो प्राधिकारी द्वारा संगत पाए गए हैं, वे इस प्रकार हैं :-

- i. जहां तक सामान्य मूल्य, संभावना, क्षति और लोक हित का संबंध है, प्राधिकारी द्वारा उन्हें इन जांच परिणामों के संगत पैरा में शामिल किया गया है।
- ii. जहां तक सिनोकेम टाइकांग द्वारा दाखिल किए गए उत्तर को अस्वीकार करने का संबंध है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि असहयोगी व्यापारी हनीवेल ट्रेडिंग (शंघाई) कं. लि. के पास सिनोकेम टाइकांग द्वारा किए गए कुल निर्यातों की बहुत ही कम प्रतिशतता है और इसीलिए प्राधिकारी ने उत्पादक के लिए निर्यात कीमत के अन्तिम निर्धारण के लिए इस व्यापारी द्वारा किए गए निर्यातों के लिए उपलब्ध सर्वोत्तम तथ्य लागू किए गए हैं।
- iii. जहां तक सिनोकेम ग्रुप के लिए भारित औसत कारखाना बाह्य निर्यात कीमत की गणना और गणना किए गए पहुंच मूल्य का संबंध है, प्राधिकारी ने यह नोट किया है कि इसकी गणना, विनिर्दिष्ट नियमों और प्राधिकारी की मौजूदा प्रक्रिया के अनुसार की गई है।
- iv. जहां तक विचाराधीन उत्पाद के पैक किए गए रूपों और पैक न किए गए रूपों के संबंध में तुलना करने का संबंध है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन की तुलना, पैक किए गए और पैक न किए गए रूपों के लिए की गई है। और फिर भारित औसत लिया गया है।
- v. जहां तक एनआईपी की गणना का संबंध है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि विनिर्दिष्ट नियमावली और प्राधिकारी की मौजूदा प्रक्रिया के अनुसार निर्धारण किया गया है।
- vi. जहां तक आयातित विचाराधीन उत्पाद की तुलना में घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद की खराब गुणवत्ता का संबंध है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने इसे प्रमाणित करने के लिए पर्याप्त सूचना प्रदान नहीं की है। इसके साथ ही, डीएसएम इंडेमिड्स बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी [(2000 (119) ई.एल.टी.308] मामले में, माननीय अधिकरण (ट्रिब्यूनल) ने यह नोट किया है कि गुणवत्ता में अंतर को, आयातित उत्पाद पर विचार करने के लिए घरेलू समान उत्पाद से भिन्न संगत मापदंड नहीं माना जा सकता।
- vii. जहां तक वार्षिक रिपोर्ट में विवरणों के संबंध में तर्क का संबंध है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि एसआरएफ करीब 71 उत्पादों का निर्माण करता है। वार्षिक रिपोर्ट में समेकित विवरण विचाराधीन उत्पाद के निष्पादन को नहीं दर्शाता। इसके अलावा, इन जांच परिणामों के संगत पैरा में किए गए क्षति विश्लेषण यह स्थापित करने के लिए स्वतः

स्पष्ट हैं कि पाटन के कारण घरेलू उद्योग को निरंतर क्षति हो रही है। इसके अलावा, कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट जैसे सार्वजनिक विवरण इस निष्कर्ष को नहीं बदलते कि उत्पाद के पाटन के कारण घरेलू उद्योग को क्षति हुई है।

- viii. जहां तक चीन जन. गण. से पहुंच कीमत और याचिकाकर्ता की लाभप्रदता के बीच विपरीत संबंध होने के तर्क का संबंध है, यह नोट किया जाता है कि आयातों की पहुंच कीमत, क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की लागतों से कम है। अतः यहां तक कि आयातों की पहुंच कीमत में वृद्धि होने के बाद भी, यह घरेलू उद्योग की विक्रियों की लागत से अभी भी कम थी। इसके परिणामस्वरूप, जबकि क्षति अवधि के दौरान लागतों में वृद्धि हुई है, घरेलू उद्योग लागत में वृद्धि के अनुपात में अपनी विक्री कीमत में वृद्धि करने में असमर्थ है, जिसके परिणामस्वरूप कीमत में ह्रास हुआ है और लाभप्रदता में गिरावट आई है।
- ix. जहां तक पाटनरोधी शुल्क के विस्तार की जरूरत का संबंध है, नियमावली के तहत प्राधिकारी से यह अपेक्षित है कि वे यह निर्धारित करें कि क्या पाटनरोधी शुल्क की समामि होने से घरेलू उद्योग को पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है। यह भी नोट किया जाता है कि पाटनरोधी शुल्क के विस्तार के लिए सिफारिश केवल तब की गई है, जब अपेक्षित कानूनी अपेक्षाएं पूरी की गई हैं।
- x. जहां तक सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए यूएसए से भारत में आयातों की कीमत के उपयुक्त होने के लिए तर्क का संबंध है, प्राधिकारी द्वारा इसे इन जांच परिणामों के संगत पैरा में शामिल किया गया है। अनुबंध-1 के पैरा 7 में सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए क्रमबद्धता निर्धारित की गई है और यह प्रावधान किया गया है कि सामान्य मूल्य का निर्धारण, एक बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में कीमत अथवा निर्मित मूल्य अथवा ऐसी कीमत पर, जहां से ऐसे तीसरे देश से भारत सहित अन्य देशों की कीमत के आधार पर किया गया है अथवा जहां यह संभव नहीं है, वहां किसी अन्य तर्कसंगत आधार पर किया गया है, जिसमें समान उत्पाद के लिए एक तर्कसंगत लाभ मार्जिन को शामिल करने के लिए यदि आवश्यक हो तो विधिवत समायोजन करके, भारत में वास्तव में भुगतान की गई अथवा भुगतान किए जाने योग्य कीमत सहित किसी अन्य तर्कसंगत आधार पर किया गया है। इस प्रकार, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि सामान्य मूल्य का निर्धारण, अनुबंध-1 के पैरा 7 के तहत प्रदत्त विभिन्न क्रमगत विकल्पों को ध्यान में रखते हुए किया गया है। किसी भी हितवद्ध पक्षकार द्वारा, पैरा 7 के प्रथम परन्तुक के उपयोग पर विचार करने के लिए कोई सूचना प्रदान नहीं की गई है और न ही इसके लिए प्राधिकारी के पास कोई सामग्री उपलब्ध है। यूएसए से आयातों में भारत में विचाराधीन उत्पाद के दूसरे सबसे अधिक आयात शामिल हैं। अतः प्राधिकारी ने यूएसए को एक उपयुक्त प्रतिनिधि देश के रूप में विचार किया है और यूएसए से भारत को आयात कीमत के आधार पर सामान्य मूल्य का निर्धारण किया गया है। जहां तक चीन जन. गण. और यूएसए के विकास के स्तर में अन्तर के संबंध में तर्क का संबंध है, प्राधिकारी ने कुईतुन जिनजियांग कैमिकल इंडस्ट्री कं. लि. बनाम भारत संघ का हवाला दिया है, जिसमें कि माननीय सेस्टेट ने यह पाया है कि विकास का स्तर तभी संगत होगा, जब घरेलू विक्री कीमत अथवा एक बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश की उत्पादन की लागत अपनाई गई है, क्योंकि विकास का स्तर कीमत और लागत को प्रभावित करता है। अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में कीमत अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में मांग और आपूर्ति का कार्य है और यह आपूर्तिकर्ता देश के विकास के स्तर से प्रभावित नहीं होता है। अतः भारत के लिए कीमत से तात्पर्य भारतीय बाजार में खपत के लिए कीमत से है। जब सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए पैरा 7 के तहत दूसरे विकल्प का प्रयोग किया जाता है, तो जो संगत है, वह निर्यातों की मात्रा है और संबंधित देश द्वारा जांच की अवधि के दौरान पाटन नहीं किया जा रहा है, चूंकि ये मापदंड भारतीय बाजार में कीमत की तुलनात्मकता को प्रभावित करेंगे। इसके अलावा, यह नोट किया जाता है कि भारत में उत्पादन की लागत पर सामान्य मूल्य के रूप में विचार करने के लिए सभी प्रतिवादी निर्यातकों के लिए अधिक पाटन मार्जिन होगा।
- xi. जहां तक इस तर्क का संबंध है कि यूएस से आयात केवल बिना पैक किए रूप में हैं, प्राधिकारी ने पैक किए गए रूप में सामान्य मूल्य की गणना करते समय सत्यापित पैकिंग लागत शामिल की है। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि चूंकि यूएसए के पास भारत में कुल आयातों में दूसरा सबसे बड़ा हिस्सा है, अतः यूएसए पर एक उपयुक्त प्रतिनिधि देश के रूप में विचार किया जा रहा है।
- xii. जहां तक पाटन और क्षति की संभावना के तर्क का संबंध है, इन जांच परिणामों के संगत पैरा में इस पर विचार किया गया है। जहां तक कीमत के आकर्षक होने का संबंध है, प्राधिकारी ने तीसरे देश के प्रतिवादी निर्यातकों द्वारा किए गए निर्यातों की जांच की है। सारबद्ध तालिका इस प्रकार है :-

मात्रा मी .टन में	सिनोकेम इन्वायरमेन्टल प्रोटेक्शन केमिकल्स (ताइकैंग) कं. लि.	शांक्सी सिनोकेम लानतियान न्यू केमिकल मैटिरियल कं. लि.	शानडोंग डोंगयुई केमिकल कं. लि.	झेजियांग सानमेई केमिकल इन्ड. कं. लि.	झेजियांग क्यूहुआ फ्लुओर केमिस्ट्री कं. लि.	झेजियांग क्यूझोऊ लायनझोऊ रेफ्रिजरेंट्स कं. लि.	सिनोकेम लानतियान फ्लूरो मैटिरियल्स कं. लि.)	कुल
घरेलू उद्योग के एनएसआर से कम मात्रा	***	***	***	***	***	***	***	63,422
घरेलू उद्योग के एनएसआर से अधिक मात्रा	***	***	***	***	***	***	***	161
भारत में सीआईएफ कीमत से कम मात्रा	***	***	***	***	***	***	***	54,465
भारत में सीआईएफ कीमत से अधिक मात्रा	***	***	***	***	***	***	***	9,118
पाटनरोधी शुल्क (बीसीडी के बिना) के साथ भारत में सीआईएफ कीमत से कम मात्रा	***	***	***	***	***	***	***	62,321
पाटनरोधी शुल्क (बीसीडी के बिना) के साथ भारत में सीआईएफ कीमत से अधिक मात्रा	***	***	***	***	***	***	***	1,262

xiii. यह देखा जाएगा कि :

- क. प्रतिवादी निर्यातकों से 99.75 प्रतिशत निर्यात, भारत को निर्यात कीमत से कम कीमत पर हैं।
- ख. प्रतिवादी निर्यातकों से 85.66 प्रतिशत निर्यात, भारत की बिक्री कीमत से कम कीमत पर हैं।
- ग. प्रतिवादी निर्यातकों से 98.02 प्रतिशत निर्यात, भारत को पाटनरोधी शुल्क के साथ सीआईएफ निर्यात कीमत से कम कीमत पर हैं।
- घ. भारत प्रतिवादी निर्यातकों के लिए कीमतों का आकर्षक बाजार है और पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति होने की स्थिति में, चीन जन. गण. से आयातों के कारण पाटन कीमत में वृद्धि होने की संभावना है, जिससे घरेलू उद्योग को क्षति हो रही है।

#### ठ. भारतीय उद्योग का हित एवं अन्य मुद्दे

118. प्राधिकारी ने यह माना है कि पाटनरोधी शुल्कों को लगाने से भारत में उत्पाद के कीमत स्तर पर प्रभाव पड़ सकता है। तथापि, भारतीय बाजार में उचित प्रतिस्पर्धा में पाटनरोधी उपायों को लागू करने से कमी नहीं आएगी। इसके प्रतिकूल, पाटनरोधी उपाय लागू किए जाने से पाटन की प्रक्रियाओं द्वारा प्राप्त अनुचित लाभ को दूर किया जा सकेगा, घरेलू उद्योग की गिरावट को रोका जा सकेगा और संबद्ध वस्तुओं के उपभोक्ताओं को व्यापक विकल्प बनाए रखने में मदद मिलेगी। पाटनरोधी उपायों का पाटन के प्रयोजन, सामान्य तौर पर घरेलू उद्योग को पाटन की अनुचित व्यापार प्रक्रिया के द्वारा हुई हानि को दूर करना है ताकि भारतीय बाजार में खुली और उचित प्रतिस्पर्धा की स्थिति की पुनर्स्थापना हो सके, जो कि देश के सामान्य हित में है। अतः पाटनरोधी शुल्कों को लगाने से उपभोक्ताओं के लिए उत्पाद की उपलब्धता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्राधिकारी

यह नोट करते हैं कि पाटनरोधी उपाय लागू करने से किसी भी तरह से संबद्ध देश से आयातों पर प्रतिबंध नहीं लगेगा और इसीलिए उपभोक्ताओं के लिए उत्पाद की उपलब्धता पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके विपरीत पाटनरोधी शुल्क का विस्तार होने से यूएसए और यूके सहित अन्य स्रोतों से आयातों को प्रोत्साहन मिलेगा।

119. प्राधिकारी ने यह विचार किया कि क्या पाटनरोधी शुल्क को विस्तार करना प्रतिकूल लोक हित होगा। इसके लिए प्राधिकारी ने यह जांच की है कि क्या विचाराधीन उत्पाद के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क को विस्तार करने से यह व्यापक लोक हित के खिलाफ होगा। यह निर्धारण, घरेलू उद्योग सहित विभिन्न पक्षकारों, आयातकों और उत्पाद के उपभोक्ताओं के हितों और रिकॉर्ड पर दर्ज सूचना पर विचार किए जाने के आधार पर है।
120. प्राधिकारी ने राजपत्र अधिसूचना जारी की है, जिसमें आयातकों, उपभोक्ताओं और अन्य हितवद्ध पक्षकारों सहित सभी हितवद्ध पक्षकारों से विचार आमंत्रित किए गए हैं। प्राधिकारी ने पाटनरोधी शुल्क के उनके प्रचालनों पर संभव प्रभाव सहित वर्तमान जांच के संबंध में संगत सूचना प्रदान करने के लिए उपभोक्ताओं के लिए एक प्रश्नावली भी निर्धारित की है। प्राधिकारी ने अन्य के साथ-साथ विभिन्न देशों से विभिन्न सप्लायरों द्वारा सप्लाइ किए गए उत्पाद की अन्तर परिवर्तनीय क्षमता के संबंध में सूचना की मांग की है ताकि स्रोतों को बदला जा सके, उपभोक्ताओं पर पाटनरोधी शुल्कों के प्रभाव, ऐसे कारक, जिनसे पाटनरोधी शुल्क लगाने से उत्पन्न नई स्थिति के समायोजन में विलंब अथवा कार्य में तेजी आने की संभावना है।
121. किसी उपभोक्ता, आयातक अथवा उपभोक्ता एसोसिएशन ने वर्तमान जांच के संबंध में विरोध नहीं किया है, जैसा कि इन जांच परिणामों में पहले ही नोट किया गया है, इससे इस धारणा को बल मिलता है कि भारत में उपभोक्ता उद्योग पर संबद्ध वस्तुओं के संबंध में पाटनरोधी शुल्क के विस्तार से प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है। इसके अलावा, इस संबंध में प्राधिकारी इस बात की पुनरावृत्ति करते हैं कि पाटनरोधी उपायों को लागू करने से संबद्ध देश के आयातों पर प्रतिबंध नहीं लगेगा और इसलिए उपभोक्ताओं के लिए उत्पाद की उपलब्धता पर प्रभाव नहीं पड़ेगा।
122. यहां तक कि प्राधिकारी ने पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव की मात्रा के लिए और यह स्पष्ट करने के लिए कि कैसे उन पर पाटनरोधी शुल्क लगाने का प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, उपभोक्ताओं के लिए फॉर्मेट निर्धारित किया है। यह नोट किया जाता है कि किसी भी हितवद्ध पक्षकार ने संगत सूचना प्रदान नहीं की है। इस प्रकार यह नोट किया जाता है कि हितवद्ध पक्षकारों ने सत्यापन योग्य सूचना के साथ प्रयोक्ता उद्योग पर पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव की स्थापना नहीं की है। इसके अलावा, घरेलू उद्योग ने उपभोक्ता उद्योग पर पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश के प्रभाव की मात्रा निर्धारित की और यह अनुरोध किया है कि प्रभाव मामूली है।
123. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने यह अनुरोध किया है कि विचाराधीन उत्पाद का वैश्विक उत्पादन हो रहा है। चीन के पास 240 केटीपीए की क्षमता है, नार्थ अमेरिका के पास 102 केटीपीए की सम्मिलित क्षमता है और यूरोपीय संघ तथा जापान के पास प्रत्येक की 20 केटीपीए क्षमता है। यह नोट किया जाता है कि उत्पाद निःशुल्क की श्रेणी में आता है और इसीलिए उसे विभिन्न देशों से आयात किया जा सकता है। पाटनरोधी शुल्क को विस्तार करने से आयातों पर किसी भी तरह से प्रतिबंध नहीं लगेगा और इसलिए इसके उपभोक्ताओं के उत्पाद की उपलब्धता पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। पाटनरोधी शुल्क लगाने से न तो उपभोक्ताओं के लिए उत्पाद की उपलब्धता पर प्रभाव पड़ेगा और न ही उपभोक्ताओं के लिए एकाधिकार की स्थिति उत्पन्न होगी।
124. संयुक्त राज्य अमेरिका ने भी चीन जन. गण. से यूएसए में विचाराधीन उत्पाद के आयातों की भी जांच की है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने इस निष्कर्ष पर इन आयातों पर महत्वपूर्ण मात्रा में शुल्क लगाए हैं, कि इनसे उनके घरेलू उद्योग को पर्याप्त क्षति हो रही थी।
125. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि इस उत्पाद का उपयोग मुख्यतः ऑटोमोबाइल एयर कंडीशनिंग में किया जाता है और घरेलू उद्योग ने यह कहा है कि भारत में अगले दशक में एचएफसी में एक मजबूत वृद्धि होने की संभावना है। घरेलू उद्योग ने यह भी अनुरोध किया है कि उन्होंने वर्ष 2011 में 530 करोड़ रु. के निवेश के साथ संबद्ध आयातों पर प्रारंभिक पाटनरोधी शुल्क लगाने से अपनी क्षमता में चार गुणा क्षमता बढ़ाई है। अतः घरेलू उद्योग भारत में विचाराधीन उत्पाद की वर्तमान और भावी मांग को पूरा करने में सक्षम है।
126. इसके अलावा, घरेलू उद्योग का क्षमता उपयोग जांच की अवधि में कम है और इसमें विगत वर्ष की तुलना में गिरावट आई है। घरेलू उद्योग के पास भारत में काफी अधिक मांग को पूरा करने की क्षमता थी। तथापि, विचाराधीन उत्पाद के पाटन के कारण, घरेलू उद्योग के पास अप्रयुक्त क्षमता थी और उसका चीन के आयातों की तुलना में घरेलू बाजार में काफी कम हिस्सा था।



127. यह नोट किया जाता है कि हितबद्ध पक्षकारों ने यह प्रदर्शित नहीं किया है कि कैसे संबद्ध वस्तुओं की कीमतों से उपभोक्ताओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। दूसरी ओर, घरेलू उद्योग ने यह दर्शाते हुए योग्य सूचना प्रस्तुत की है कि प्रस्तावित पाटनरोधी शुल्क का प्रभाव प्रयोक्ता उद्योग पर मामूली होगा। घरेलू उद्योग ने यह अनुरोध किया है कि विचाराधीन उत्पाद की लागत अन्तिम उत्पाद में न्यूनतम है और इसका अन्तिम प्रयोक्ताओं पर लगभग शून्य प्रभाव पड़ा है। उदाहरण के लिए, यह मानकर कि भारत में एक कम्पैक्ट कार की लागत 2,50,000 रु. है, एयर कंडीशनर में प्रयुक्त आर-134 ए की मात्रा 500 ग्राम से कम होगी। यह मानकर कि 500 ग्राम आर-134 ए की लागत करीब 150 रु. है, अन्तिम रूप से तैयार उत्पाद के वास्तविक उपभोक्ता पर विचाराधीन उत्पाद की लागत काफी कम है।
128. इस प्रकार यह नोट किया जाता है कि हितबद्ध पक्षकारों ने सत्यापन योग्य सूचना के साथ प्रयोक्ता उद्योग पर प्रस्तावित पाटनरोधी शुल्क के संभावित प्रतिकूल प्रभाव की स्थापना नहीं की है। यद्यपि 10 वर्षों के लिए पाटनरोधी शुल्क लागू हैं, लेकिन ऐसा कोई भी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध साक्ष्य नहीं है जो यह दर्शाता हो कि प्रयोक्ता उद्योग पर भी प्रतिकूल प्रभाव है। इस प्रकार यदि यह माना जाता है कि पाटनरोधी शुल्क को विस्तार करने से संबद्ध वस्तुओं का उपयोग करके निर्मित उत्पाद के कीमत स्तर पर प्रभाव पड़ सकता है, लेकिन उसके परिणामस्वरूप उत्पाद पर पाटनरोधी शुल्क का प्रभाव काफी अपर्याप्त होगा। इसके अलावा, भारतीय बाजार में उचित प्रतिस्पर्धा से पाटनरोधी उत्पादों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, विशेषकर यदि पाटनरोधी शुल्क लगाना आवश्यक राशि तक सीमित किया जाए ताकि घरेलू उद्योग की क्षति को दूर किया जा सके। पाटनरोधी उपाय लागू करने का उद्देश्य पाटन प्रक्रियाओं द्वारा प्राप्त अनुचित लाभ को दूर करना, घरेलू उद्योग की क्षति को रोकना और संबद्ध वस्तुओं के उपभोक्ताओं को व्यापार के विकल्प उपलब्ध कराने में मदद प्रदान करना है।
129. प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि शुल्क को विस्तार करने की सिफारिश केवल तभी की गई है जब अपेक्षित कानूनी जरूरतें पूरी हों। हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि घरेलू उद्योग प्रायः व्यापार संरक्षा का प्रयोग करता रहा है। तथापि, यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग ने यह सूचित किया है कि वह 71 उत्पादों के उत्पादन में शामिल है और वर्तमान में 4 उत्पादों में पाटनरोधी शुल्क से संरक्षण है। घरेलू उद्योग ने यह भी अनुरोध किया है कि उन्होंने विगत में विक्री कीमत में असमान वृद्धि करने के लिए संबद्ध वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क का लाभ नहीं लिया है, इस तथ्य पर विचार करते हुए कि घरेलू उद्योग संबद्ध वस्तुओं में सकारात्मक व्यापार संतुलन बनाए रखने के लिए समर्थ रहा है, घरेलू उद्योग की स्थिति भी देश की अर्थव्यवस्था के हित में है।
130. रिकॉर्ड पर उपलब्ध सूचना से यह भी नोट किया जाता है कि पाटनरोधी शुल्क विचाराधीन उत्पाद के उपभोक्ताओं पर न्यून है और प्राधिकारी का यह विचार है कि पाटनरोधी शुल्क लगाना सार्वजनिक हित में होगा।

#### ड. निष्कर्ष एवं सिफारिशें

131. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों और उनमें उठाए गए मामलों की जांच के बाद और रिकॉर्ड पर उपलब्ध तथ्यों पर विचार करने के बाद प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि :
- क. आवेदक नियमावली के नियम 2 (ख) के तहत घरेलू उद्योग है और आवेदन में नियमावली के नियम 5 (3) के संदर्भ में आधार के मापदंड को पूरा किया गया है।
  - ख. घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद संबद्ध देश से आयातित विचाराधीन उत्पाद के समान वस्तु है।
  - ग. आवेदन में जांच शुरू करने के प्रयोजन से संगत समस्त सूचना शामिल है और जांच शुरू करने को न्यायोचित ठहराने के लिए प्रयास साक्ष्य शामिल हैं।
  - घ. संबद्ध वस्तुओं के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत पर विचार करते हुए, संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के लिए पाटन मार्जिन का निर्धारण किया गया है और मार्जिन महत्वपूर्ण है।
  - ड. घरेलू उद्योग ने पर्याप्त क्षति का सामना किया है। संबद्ध वस्तुओं के आयातों की जांच और घरेलू उद्योग का निष्पादन स्पष्ट रूप से यह दर्शाते हैं कि संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के पाटित आयातों की मात्रा में गिरावट आई है लेकिन उसके बाद क्षति अवधि के दौरान यह सापेक्ष संदर्भ में महत्वपूर्ण रही है। संबद्ध देश से आयातों के कारण, घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती हो रही है। संबद्ध देश से आयात घरेलू उद्योग की कीमतों का ह्रास कर रहे हैं। घरेलू उद्योग के क्षमता उपयोग, उत्पादन और घरेलू विक्रियों में जांच की अवधि में काफी गिरावट आई है। घरेलू उद्योग वित्तीय हानि, नकदी हानि तथा नियोजित पूंजी पर नकारात्मक प्रतिफल का सामना कर रहा है।
  - च. घरेलू उद्योग को हुई महत्वपूर्ण क्षति पाटित आयातों के कारण से रही है।

- छ. चीन के उत्पादकों द्वारा रखी गई सरप्लस क्षमताओं, यूएस और यूरोपीय संघ जैसे बड़े बाजारों में संबद्ध वस्तुओं के लिए गिरती मांग, यूएस द्वारा चीन के आयातों पर लगाए गए टैरिफ के अवरोधों, भारतीय बाजार की आकर्षकता और चीन के उत्पादकों के निर्यातोन्मुखी होने को देखते हुए, लागू पाटनरोधी शुल्क की समामि की स्थिति में पाटन और क्षति के जारी रहने की संभावना मौजूद है।
- ज. पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव की मात्रा के लिए प्रयोक्ताओं/ आयातकों के लिए सभी फार्मेट प्रदान किए जाने के बावजूद और यह स्पष्ट किए जाने के बावजूद कि कैसे पाटनरोधी शुल्क का विस्तार होने से उन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, किसी भी प्रयोक्ता/ आयातक ने संगत सूचना प्रदान नहीं की है। हितवद्ध पक्षकारों ने सत्यापन किए जाने योग्य सूचना के साथ प्रयोक्ता उद्योग पर, पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव की स्थापना नहीं की है। लागू पाटनरोधी शुल्क की समामि होने पर संबद्ध उत्पाद के स्वदेशी उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और यह तथ्य कि पाटनरोधी शुल्क का प्रभाव विचाराधीन उत्पाद के उपभोक्ताओं के लिए न्यूनतम है, प्राधिकारी का यह विचार है कि पाटनरोधी शुल्क का विस्तार लोक हित में होगा।
132. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि जांच की शुरुआत की गई थी और सभी हितवद्ध पक्षकारों को अधिसूचित की गई थी तथा घरेलू उद्योग, निर्यातकों, आयातकों और अन्य हितवद्ध पक्षकारों को पाटन, क्षति एवं कारणात्मक संबंध के पहलुओं पर सकारात्मक सूचना प्रदान करने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया था। पाटनरोधी नियमावली में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार, पाटन, क्षति एवं कारणात्मक संबंध के बारे में जांच शुरू करने और जांच किए जाने पर प्राधिकारी का यह दृष्टिकोण है कि पाटन और क्षति को दूर करने के लिए पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की जरूरत है। अतः प्राधिकारी संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के आयात पर पाटनरोधी शुल्क लगाना आवश्यक समझते हैं और इसे लगाने की सिफारिश करते हैं।
133. प्राधिकारी द्वारा अपनाए गए कमतर शुल्क नियम को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी कमतर पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन के बराबर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की सिफारिश करते हैं ताकि घरेलू उद्योग की क्षति को दूर किया जा सके। तदनुसार प्राधिकारी केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में जारी की जाने वाली अधिसूचना की तारीख से संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के आयातों के संबंध में नीचे दी गई शुल्क तालिका के कॉलम 7 में उल्लिखित राशि के बराबर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की सिफारिश करते हैं। इस प्रयोजन के लिए पहुंच मूल्य सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 3, 3क, 8ख, 9, 9क के तहत लगाए गए शुल्कों को छोड़कर, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के तहत सीमा शुल्क द्वारा यथा-निर्धारित और सीमा शुल्क के लागू स्तर पर आकलन योग्य मूल्य होगा।

#### शुल्क तालिका

क्र.सं.	शीर्ष	विवरण	मूलता का देश	निर्यात का देश	उत्पादक	राशि	यूनिट	मुद्रा
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	29033919	1,1,1,2-टेट्राफ्लूरोइथा अथवा आर-134ए*	चीन जन. गण.	चीन जन. गण. सहित कोई अन्य देश	सिनोकेम इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन केमिकल्स (ताइकंग) कं. लि.	2.1	किलोग्राम	यूएस डॉलर
2	-वही-	-वही-	चीन जन. गण.	चीन जन. गण. सहित कोई अन्य देश	शांक्सी सिनोकेम लानतियान न्यू केमिकल मैटिरियल कं. लि.	2.1	किलोग्राम	यूएस डॉलर
3	-वही-	-वही-	चीन जन.गण.	चीन जन. गण. सहित कोई अन्य देश	शानडॉंग डोंगयुई केमिकल कं. लि.	2.13	किलोग्राम	यूएस डॉलर

4	-वही-	-वही-	चीन जन. गण.	चीन जन. गण . सहित कोई अन्य देश	झेजियांग सनमेई केमिकल इन्ड. कं . लि.	1.29	किलोग्राम	यूएस डॉलर
5	-वही-	-वही-	चीन जन. गण.	चीन जन. गण . सहित कोई अन्य देश	झेजियांग क्यूहूआ फ्लूरो-केमिस्ट्री कं . लि.	1.59	किलोग्राम	यूएस डॉलर
6	-वही-	-वही-	चीन जन. गण.	चीन जन. गण . सहित कोई अन्य देश	झेजियांग क्यूझोऊ लियानझोऊ रेफ्रिजरेटर्स कं . लि .	1.59	किलोग्राम	यूएस डॉलर
7	-वही-	-वही-	चीन जन. गण.	चीन जन. गण . सहित कोई अन्य देश	क्र. सं 1 .से 6 के अलावा कोई अन्य	3.24	किलोग्राम	यूएस डॉलर
8	-वही-	-वही-	चीन जन. गण .के अलावा कोई अन्य देश	चीन जन. गण.	कोई अन्य	3.24	किलोग्राम	यूएस डॉलर

\* नोट : सीजीएमपी प्रमाणित आर 134ए को विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर किया गया है।

#### ढ. आगे की प्रक्रिया

134. इस सिफारिश के कारण केन्द्र सरकार के आदेश के खिलाफ कोई भी अपील, अधिनियम के संगत प्रावधानों के अनुसार सीमा शुल्क, उत्पाद एवं सेवा कर अपील अधिकरण के समक्ष की जा सकेगी।

अनंत स्वरूप, निर्दिष्ट प्राधिकारी

## MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 8th October, 2021

### FINAL FINDINGS

(Case No. ADD-SSR-01/2021)

**Subject: Sunset Review of the anti-dumping investigation concerning imports of '1,1,1,2-Tetrafluoroethane or R-134a' originating in or exported from China PR-reg.**

**F. No. 7/1/2021-DGTR:** Having regard to the Customs Tariff Act, 1975, as amended from time to time (hereinafter also referred to as "the Act") and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules 1995, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the "Anti-Dumping Rules" or "the Rules") thereof, the Designated Authority (hereinafter referred to as "Authority") received an application from M/s SRF Limited (hereinafter also referred to as the "applicant" or the "petitioner") requesting the initiation of the sunset review of the anti-dumping duty imposed on the imports of '1,1,1,2-Tetrafluoroethane or R-134a' (hereinafter referred to as the "subject goods" or the "product under consideration" or the "PUC") originating in or exported from China PR (hereinafter referred to as the "subject country").

#### **A. BACKGROUND OF THE CASE**

2. The Authority had initiated the original anti dumping investigation concerning the imports of '1,1,1,2-Tetrafluoroethane or R-134a' originating in or exported from China PR and Japan vide notification no. 14/24/2009-DGAD dated 19<sup>th</sup> August, 2009. The final findings notification was issued by the Authority vide notification no. 14/24/2009-DGAD dated 10<sup>th</sup> May, 2011, recommending the imposition of the definitive anti-dumping duty on the imports of the subject goods, originating in or exported from China PR and Japan. The definitive anti-dumping duties (ADD) were imposed by the Department of Revenue vide notification no. 61/2011 – Customs (ADD) dated 15<sup>th</sup> July, 2011.

3. The Authority had initiated the first sunset review investigation concerning the imports of '1,1,1,2-Tetrafluoroethane or R-134a' originating in or exported from China PR vide notification no. 15/23/2014-DGAD dated 10<sup>th</sup> April, 2015. The final findings notification was issued by the Authority vide notification no. 15/23/2014-DGAD dated 30<sup>th</sup> May, 2016 recommending extension of the anti-dumping duty in force on the imports of the subject goods, originating in or exported from China PR. The anti-dumping duties were extended by the Department of Revenue vide notification no. 30/2016 – Customs (ADD) dated 11<sup>th</sup> July, 2016.
4. The Authority had initiated a new shipper review investigation concerning the imports of '1,1,1,2-Tetrafluoroethane or R-134a' originating in or exported from China PR vide notification no. 15/22/2016-DGAD dated 27<sup>th</sup> February, 2017. The final findings notification was issued by the Authority vide notification no. 15/22/2016-DGAD dated 26<sup>th</sup> July, 2018 vide which the shipper review investigation was terminated.
5. In terms of Section 9A (5) of the Act, ADD imposed shall, unless revoked earlier, cease to have effect on the expiry of five years from the date of such imposition and the Authority is required to review, whether the expiry of ADD is likely to lead to continuation or recurrence of the dumping and the injury. Further, Rule 23 (1B) of the Rules provides as follows:  
*"any definitive antidumping duty levied under the Act, shall be effective for a period not exceeding five years from the date of its imposition, unless the designated authority comes to a conclusion, on a review initiated before that period on its own initiative or upon a duly substantiated request made by or on behalf of the domestic industry, within a reasonable period of time prior to the expiry of that period, that the expiry of the said anti-dumping duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry."*
6. In accordance with the above, the Authority is required to review, on the basis of a duly substantiated request made by or on behalf of the domestic industry, as to whether the expiry of anti-dumping duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury.
7. The Authority, on the basis of prima facie evidence submitted by the applicant, issued a public notice vide Notification No. 7/1/2021-DGTR dated 19<sup>th</sup> February, 2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, initiating the subject investigation in accordance with Section 9A(5) of the Act read with Rule 23 of the Rules to review the need for continued imposition of the anti-dumping duty in respect of the subject goods, originating in or exported from the subject country and to examine whether the expiry of the said ADD is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry.
8. Pending the conclusion of the investigation, the anti-dumping duties were extended up to and inclusive of 10<sup>th</sup> January, 2022 vide Notification No. 30/2021-Customs (ADD) dated 24<sup>th</sup> May, 2021.
9. The scope of the present review covers all the aspects of the final findings notification no. 15/23/2014-DGAD dated 30<sup>th</sup> May, 2016 which had recommended the extension of the anti-dumping duty on the imports of the subject goods originating in or exported from the subject country.

## **B. PROCEDURE**

10. The procedure described below has been followed with regard to the subject investigation:
  - a. The Authority notified the Embassy of the subject country in India about receipt of the application for the sunset review investigation before proceeding to initiate the present investigation in accordance with Sub-Rule (5) of Rule 5 of the Anti-Dumping Rules.
  - b. The Authority issued a public notice dated 19<sup>th</sup> February, 2021 published in the Gazette of India Extraordinary, initiating the sunset review investigation concerning the anti-dumping duty imposed on the imports of the subject goods originating in or exported from the subject country.
  - c. The Authority sent a copy of the initiation notification dated 19<sup>th</sup> February, 2021 to the Embassy of the subject country in India, the known producers and exporters from the subject country, known importers, importer/user Associations and other interested parties, as per the addresses made available by the applicant. The interested parties were advised to provide the relevant information in the form and manner prescribed and to make their submissions known in writing within the prescribed time-limit.
  - d. The Authority provided a copy of the non-confidential version of the application to the known producers/exporters and to the Embassy of the subject country in India in accordance with Rule 6(3) of the Rules.
  - e. The Embassy of the subject country in India was also requested to advise the exporters/producers from its country to respond to the questionnaire within the prescribed time limit. A copy of the letter and questionnaire sent to the producers/exporters was also sent to it along with the names and addresses of the known producers/exporters from the subject country.

- f. The Authority, upon request made by the interested parties, granted extension of time to file the Questionnaire Responses vide communication dated 25<sup>th</sup> March, 2021, up to 15<sup>th</sup> April, 2021.
- g. The Authority sent questionnaires to the following known producers/exporters in the subject country in accordance with Rule 6(4) of the Rules:
  - i. M/s Zhejiang Juhua Group I/E Co. Ltd.
  - ii. M/s Shandong Dongyue Chemical Ltd.
  - iii. M/s Sinochem Environmental Protection Chemicals (Taicang) Co. Ltd.
  - iv. M/s Jiangsu Kangtai Fluorine Chemical Co. Ltd.
  - v. M/s Changshu 3F Zhonghao New Chemical Materials Co. Ltd.
  - vi. M/s Zhejiang Fotech International Co. Ltd.
  - vii. M/s Du Pont China Holding Co. Ltd.
  - viii. M/s Zhejiang Pujiang Bailian Chemical Co. Ltd.
  - ix. M/s Mitsui DuPont Fluorochemicals Co. Ltd.
  - x. M/s Jiangsu Bluestar Environmental Protection Technology Co. Ltd.
  - xi. M/s Sinochem Modern Environmental Protection Chemicals (Xián) Co. Ltd.
  - xii. M/s Jiangsu JIN XUE Group Co. Ltd.
  - xiii. M/s Jiangsu Yonghe Fluorochemical Co. Ltd.
  - xiv. M/s Zhejiang Sanmei Chemical Ind. Co. Ltd.
- h. In response to the above notification, the following producers/exporters and their related exporters/traders have responded and submitted/filed exporters' questionnaire responses and/or legal submissions:
  - i. M/s Sinochem Environmental Protection Chemicals (Taicang) Co. Ltd. (Producer/ Exporter)
  - ii. M/s Shaanxi Sinochem Lantian New Chemical Material Co. Ltd. (Producer/ Exporter)
  - iii. M/s Shandong Dongyue Chemical Co. Ltd. (Producer/ Exporter)
  - iv. M/s Zhejiang Sanmei Chemical Ind. Co. Ltd. (Producer/ Exporter)
  - v. M/s Zhejiang Quhua Fluor-chemistry Co. Ltd. (Producer/ Exporter)
  - vi. M/s Zhejiang Quzhou Lianzhou Refrigerants Co. Ltd. (Producer/ Exporter)
  - vii. M/s Sinochem Lantian Trading Co. Ltd. (Domestic seller)
  - viii. M/s Sinochem Xián Jincool New Chemical Materials Co. Ltd. (Trader)
  - ix. M/s Sinochem Lantian Fluoro Materials Co. Ltd. (Domestic seller)
  - x. M/s Sinochem Modern Environmental Protection Chemical (Xián) Co. Ltd. (Formerly producer)
- i. The Authority sent questionnaires to the following known importers and users of the subject goods in India calling for necessary information in accordance with Rule 6(4) of the Rules.
  - i. M/s E.I. DuPont India Pvt. Ltd.
  - ii. M/s Navine Fluorine International Ltd.
  - iii. M/s Stallion Enterprises
  - iv. M/s Value Refrigerants Pvt. Ltd.
  - v. M/s Mangali Petrochem Ltd.
  - vi. M/s KPL International Ltd.
  - vii. M/s KIRO Refrigerants Pvt. Ltd.
  - viii. M/s Honeywell International (I) Pvt. Ltd.
  - ix. M/s O.B. Fluoro Chems Pvt. Ltd.
  - x. M/s Brenntag India Pvt. Ltd.

- xi. M/s Cipla Ltd.
- j. In response to the above notification, none of the importers or users responded or submitted importer/user questionnaire responses/legal submissions and/or registered as the interested parties.
- k. A list of all interested parties was uploaded on DGTR's website along with the request therein to all of them to email the non-confidential version of their submissions to all other interested parties since the public file was not accessible physically due to ongoing Covid-19 global pandemic.
- l. The period of investigation (POI) for the purpose of the present investigation is 1<sup>st</sup> October, 2019 to 30<sup>th</sup> September, 2020 (12 months). The injury examination period has been considered as the period from 2017-18, 2018-19, 2019-20 and the POI.
- m. The Authority obtained transaction-wise import data from the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S) for the subject goods for the injury period, including the POI, and analysed the data after due examination of the transactions.
- n. The verification of the data provided by the domestic industry and the responding exporters was conducted to the extent considered necessary for the purpose of the present investigation.
- o. The non-injurious price (hereinafter referred to as the "NIP") based on the cost of production and reasonable profits of the subject goods in India, having regard to the information furnished by the domestic industry in accordance with Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) and Annexure III to the Rules, has been worked out so as to ascertain whether the anti-dumping duty lower than the dumping margin would be sufficient to remove injury to the domestic industry.
- p. In accordance with Rule 6(6) of the Rules, the Authority provided an opportunity to the interested parties to present their views orally in a public hearing held through video conferencing on 24<sup>th</sup> May, 2021. The parties which presented their views in the oral hearing were requested to file written submissions of the views expressed orally, followed by rejoinder submissions, if any. The parties shared their non-confidential submissions with the other interested parties and were advised to offer their rebuttals.
- q. The submissions made by the interested parties, arguments raised and the information provided by the various interested parties during the course of the investigation, to the extent the same are supported with evidence and considered relevant to the present investigation, have been considered in the final findings.
- r. The Authority, during the course of investigation, satisfied itself as to the accuracy of the information supplied by the interested parties, which forms the basis of this final finding, to the extent possible, and verified the data/documents submitted by the domestic industry to the extent considered relevant and possible.
- s. The information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claims. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims, wherever warranted, and such information has been considered as confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, the parties providing the information on confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis.
- t. In accordance with the Rules, the Authority disclosed the essential facts of the case that would form the basis of its findings in the form of a disclosure statement on 30.09.2021 and the interested parties were allowed time up to 6.10.2021 to comment on the same. The comments of the interested parties, to the extent relevant, have been considered by the Authority and have been addressed in this finding.
- u. Wherever an interested party has refused access to, or has otherwise not provided necessary information during the course of investigation, or has significantly impeded the investigation, the Authority has considered such interested parties as non-cooperative and recorded this final finding on the basis of the facts available.
- v. '\*\*\*' in this final findings notification represents the information furnished by an interested party on confidential basis and so considered by the Authority under the Rules.
- w. The exchange rate adopted by the Authority for the subject investigation is US \$1= 74.38.

### **C. PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND LIKE ARTICLE**

#### **C.1. Submissions of the other interested parties**

- 11. The other interested parties have made the following submissions with regard to the product under consideration and the like article:
  - a. The PUC is defined without making any differentiation for the packed and the unpacked material and even the entire import data is presented in such manner except for a few parameters for the subject country as cherry picked by the petitioner.

- b. The proposed separate examination of the packed and the unpacked forms is not substantiated by the domestic industry.

### C.2. Submissions of the domestic industry

12. The submissions made by the domestic industry with regard to the product under consideration and the like article are as follows:
  - a. The product under consideration is '1,1,1,2-Tetrafluoroethane or R-134a'. Since the present investigation is a sunset review, the product under consideration remains the same as defined in the previous investigation. There are no developments in the product that took place over the period.
  - b. The product manufactured by the domestic industry is like article to the product imported from the subject country. The issue of like article has already been examined by the Authority in the previous investigations as well.
  - c. The packed and the unpacked forms of the product have a difference in the cost and price of the product under consideration, and it does not constitute a different product to be separately mentioned in the product description. The domestic industry has provided the import statement, the statement of the price undercutting, the dumping margin and the injury margin as packed and unpacked. Separate dumping and injury margins should be calculated for the packed and the unpacked forms and thereafter for the product under consideration, as done in the previous investigation.

### C.3. Examination by the Authority

13. The Product Under Consideration in the present investigation is "1,1,1,2-Tetrafluoroethane or R-134a". The product under consideration is the same as defined in the previously conducted investigation, which was defined as follows in the final findings:

*The product under consideration in the present investigation is 1,1,1,2-Tetrafluoroethane or R-134a of all types. R-134a, is also called as Tetrafluoroethane, Genetron 134a, Suva 134a or HFC-134a, HFA- 134a, and Norflurane. It is a haloalkane refrigerant with thermodynamic properties similar to R-12 (dichlorodifluoromethane), but without its ozone depletion potential. It has the chemical formula CH<sub>2</sub>FCF<sub>3</sub>, and a boiling point of 26.3 °C ( 15.34 °F). It is an inert gas used primarily as a high temperature refrigerant for domestic refrigeration and automobile air-conditioners. Other uses of the subject goods include plastic foam blowing, as a cleaning solvent and as a propellant for the delivery of pharmaceuticals (e.g., bronchodilators), gas dusters, and in air driers, for removing the moisture from compressed air.*

*The subject goods are being imported under Chapter 29 of the Customs Tariff Act under subheading 2903 under "Halogenated Derivatives of Hydrocarbons", under subheading 29033919 as "Other Fluorinated Derivatives", under the Indian Trade Classification (based on Harmonized Commodity Description and Coding System). The petitioner has, however claimed that the product under consideration does not have any dedicated customs classification code and are being imported under various other Customs sub-headings. However, the customs classification is indicative only and in no way binding on the scope of this investigation.*

*However, the cGMP approved pharma grade is excluded from the purview of the PUC, since the same is neither produced by the domestic industry nor imported from the subject country."*

*The product is classified under Chapter 29 in heading 2903, "Halogenated Derivatives of hydrocarbons", under subheading 29033919 as "Other Fluorinated Derivates". The customs classification is only indicative and is not binding on the scope of the present application and the proposed review investigation."*

14. Since the present investigation is a sunset review investigation, the product under consideration remains the same as defined in the previously conducted investigation. The subject goods are classified under Chapter 29 of the Customs Tariff Act under subheading 2903 39 19. However, the customs classification is only indicative and not binding on the scope of the product under consideration.
15. The Authority notes from the information available on record that the product produced by the domestic industry is like article to the product under consideration imported from the subject country. The product is being sold both in packed and unpacked (bulk) form and the only difference in both the forms is in the cost and price of the product under consideration, but the two do not constitute a different product to be separately mentioned in the product description. The domestic industry has provided the import statement, the statement of the price undercutting, the dumping margin and the injury margin as packed and unpacked. The product produced by the domestic industry is comparable to the goods imported from the subject country in terms of physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions and uses, product specifications, pricing, distribution & marketing, and tariff classification of the goods. The two are technically and commercially

substitutable. The consumers have used and are using the two interchangeably. The Authority, therefore, holds that the subject goods produced by the domestic industry are the like article to the product imported from the subject country in terms of Rule 2(d) of the Rules.

#### **D. SCOPE OF THE DOMESTIC INDUSTRY AND STANDING**

##### **D.1. Submissions by the other interested parties**

16. No submissions have been made by the other interested parties with regard to the scope of domestic industry and its standing.

##### **D.2. Submissions by the domestic industry**

17. The domestic industry has made the following submissions with regard to the scope of domestic industry and its standing:

- a. The applicant, namely, M/s SRF Limited, is not related to any exporters of the subject goods in the subject country or any importer of the subject goods in India.
- b. The applicant also constitutes 100% of the Indian production of the like article.

##### **D.3. Examination by the Authority**

18. Rule 2(b) of the Anti-Dumping Rules defines the domestic industry as under:

*“(b) “domestic industry” means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof in such case the term ‘domestic industry’ may be construed as referring to the rest of the producers”.*

19. The application has been filed by M/s SRF Limited. The applicant accounts for 100% of the total Indian production. The applicant accounts for a major proportion in the Indian production of the subject goods. The applicant has certified that it is neither related to any exporters or producers of the product under consideration in the subject country nor any importer of the product under consideration in India.

20. The Authority holds that the applicant constitutes the domestic industry under rule 2(b) of the Rules and considers that the application satisfied the criteria of standing in terms of Rule 5(3) of the Rules.

#### **E. CONFIDENTIALITY**

##### **E.1. Submissions by the other interested parties**

21. The other interested parties have made the following submissions with regard to the confidentiality:

- a. The petitioner has filed an incomplete petition and has not provided adequate non confidential summaries of the information claimed confidential under Annexure 6 (Costing Information), without any reasonable justification, thereby violating the Rules and Trade Notices.
- b. The confidentiality claimed is as per the Rules after providing reasoning. The claims of deficiency are all incorrect.

##### **E.2. Submissions by the domestic industry**

22. The domestic industry has made the following submissions with regard to the confidentiality:

- a. The responses filed by the other interested parties are deficient and in violation of Trade Notice 10/2018, thereby preventing the domestic industry from defending their rights. The exporters have claimed the information in the public domain as confidential, excessive confidentiality on mala fide grounds of business propriety, and failed to even provide responses.
- b. The costing information is a business proprietary information and is not amenable to summarization. The domestic industry has referred and relied upon CESTAT orders in Anwar Jute Spinning Mills Ltd. v. Union of India/DA and Nitro Chemical Industry Ltd. v. DA. The exporters are arguing for its disclosure when they themselves have not disclosed.

##### **E.3. Examination by the Authority**

23. With regard to confidentiality of information, Rule 7 of the Rules provides as follows:

*“Confidential information: (1) Notwithstanding anything contained in sub-Rules (2), (3) and (7) of rule 6, sub-rule(2) of rule12, sub-rule(4) of rule 15 and sub-rule (4) of rule 17, the copies of applications received under sub-rule (1) of rule 5, or any other information provided to the designated authority on a confidential basis by any party in the course of investigation, shall, upon the designated authority being*



*satisfied as to its confidentiality, be treated as such by it and no such information shall be disclosed to any other party without specific authorization of the party providing such information.*

*(2) The designated authority may require the parties providing information on confidential basis to furnish non-confidential summary thereof and if, in the opinion of a party providing such information, such information is not susceptible of summary, such party may submit to the designated authority a statement of reasons why summarization is not possible.*

*(3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (2), if the designated authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorise its disclosure in a generalized or summary form, it may disregard such information."*

24. The Authority examined the confidentiality claims of the interested parties and on being satisfied allowed the claim on confidentiality. The Authority considers that any information which is by nature confidential (for example, because its disclosure would be of significant competitive advantage to a competitor or because its disclosure would have a significantly adverse effect upon a person supplying the information or upon a person from whom that person acquired the information), or which is provided on a confidential basis by the parties to an investigation shall, upon good cause shown, should be treated as such by the Authority. Such information cannot be disclosed without specific permission of the party submitting it.

25. The Authority has considered the claims of confidentiality made by the applicant and the opposing interested parties and on being satisfied about the same, the Authority has allowed the claim on confidentiality. The Authority made available to all interested parties the non-confidential version of evidences submitted by various interested parties for inspection, upon request as per Rule 6(7).

## **F. MISCELLANEOUS SUBMISSIONS**

### **F.1. Submissions by the other interested parties**

26. The following miscellaneous submissions have been made by the other interested parties:

- a. The domestic industry is seeking undue protection since 2009 and should not be allowed to misuse trade remedial measures to attack foreign producers and the exporters with the sole purpose of retaining monopoly. Further extension of the anti-dumping duties will provide unfair advantages to the petitioner.
- b. The period of investigation should be from October, 2019 to March, 2020 (six months) instead of October, 2019 to September, 2020 (12 months) as the COVID-19 crisis disrupted all the business activities post-March, 2020. All the sectors have been adversely affected as the domestic demand and the exports sharply plummeted.
- c. There are no special or exceptional circumstances which call for continuation of the antidumping duty. The reference has been made to Dry Cell Batteries and Nylon Filament Yarn wherein continuation of the duty was not recommended as it had served its intended purpose.
- d. Further extension of the duty can severely affect the end-users and downstream industry who are dependent on internationally competitive raw material to manufacture the value-added products that can compete with other South Asian countries, causing significant loss of livelihood, wide gap between demand and supply, reduction in export of finished goods by MSMEs and market asymmetry between the manufacturers of the product.
- e. The improper implementation of the anti-dumping measures as means of trade protection cannot play the role of protecting the industry and will cause an unfair competitive environment and damage the fundamental interests of their respective industries in the long term.
- f. Since the period of investigation should end as close to the date of initiation as possible, a longer period may be selected, as has been recognized in the recent investigations concerning cold-rolled steel, hot-rolled steel, tyre curing presses, seamless tubes pipes and hollow profiles of iron or non-alloy steel, polyurethane leather and solar cells. The initiation notice of solar cells notes that the 18-month POI was due to the pandemic.
- g. The Post-POI data should be circulated to the interested parties, after which a second oral hearing should be conducted. Since the duty has been extended until 10<sup>th</sup> January, 2022, revised imports should be called for and post-POI should be analysed.
- h. The allegation that the Chinese producers are absorbing the duty is baseless. The decline in the subject imports evidence the same. Moreover, the margins in the previous investigation were based on the facts available unlike the present case. The absorption cannot be determined by mere comparison of margins. There should be sufficient evidence of the same. The landed price from non-subject country has remained lower.

- i. The claim for enhancement of the duty must be rejected since the domestic industry has not suffered any continued injury. The margins in the previous investigation were based on facts available unlike the present case. Hence, it is not a ground for enhancement of the duty.

## **F.2. Submissions by the domestic industry**

27. The following miscellaneous submissions have been made by the domestic industry:
  - a. The Chinese producers are absorbing the anti-dumping duty imposed earlier, as is established by the significantly higher injury margins and dumping margins compared to previous sunset review.
  - b. The enhancement of the quantum of the duties may be considered since the exporters have intensified the dumping of the product under consideration in India and a cessation of the anti-dumping duty will result in aggravated injury to the domestic industry.
  - c. The anti-dumping duty is not a protection and is only a remedy to address the unfair pricing. There is no excessive protection to the domestic industry.
  - d. The extension of the anti-dumping duty has been sought due to continued dumping and the consequent injury to the domestic industry as well as the likelihood of injury in the event of cessation of the duties. The investigation was initiated by the Authority only after being prima facie satisfied with the petitioner's claims. The exporters are habitually exporting the product under consideration at dumped prices.
  - e. There is no requirement of causal link in a sunset review. The dumping need not be the primary cause of the injury. The volume and the market share of the subject imports increased during the covid period, while the market share of the domestic industry has declined in the period of investigation as compared to the previous year.
  - f. As regards the period of investigation, the period of investigation could not have been October, 2019 to March, 2020 in view of Rule 3(A), since the period of investigation would have been six months older.
  - g. As dumping from the subject country has increased compared to the previous investigations, the anti-dumping duties must be enhanced. The Authority has recommended duties in the various sunset review investigation irrespective of the duration of the duties along with the authorities in US, Canada, EU and Brazil. The facts of dry cell batteries case were totally different, and its rationale was not applied in the subsequent cases.
  - h. None of the users or the importers have taken part in the investigation since the anti-dumping duty does not adversely impact them. The domestic industry has sufficient capacities to meet the Indian demand, and thus the downstream industry will never face shortage of supply. None of the interested parties have submitted the relevant evidence of the alleged impact, though the duties have been in force for 10 years.
  - i. As regards the post-POI data, the post POI information is not a mandated requirement in a sunset review investigation. The Authority has established the likelihood of dumping and the consequent injury to the domestic industry without considering the post POI information in several previous cases.

## **F.3. Examination by the Authority**

28. The Authority has considered the submissions of the parties and determines as follows:

- a. As regards the excessive protection, the Authority notes that there is no bar on the number of times a sunset review can be conducted, and the antidumping duty extended. The Rules require the Authority to determine whether cessation of ADD is likely to lead to continuation or recurrence of the dumping and the injury to the domestic industry. It is further noted that the recommendation for extension of anti-dumping duty is made only when the requisite legal requirements are met. It is further noted that the domestic industry is engaged in the production of 71 products and at present the anti-dumping duty is levied only on four products.

As regards the argument of the impact of the ADD on the user industry, it is noted that no users/user associations has cooperated in the present investigation. This leads to the presumption that the user industries in India are not adversely impacted by the extension of ADD on the subject goods. Though the ADD on the subject goods has been in force for more than 10 years, there is no evidence to show that the same has led to curtailment of the subject imports leading to any adverse impact on either the user industry or the consumers in India. Further, even if it is considered that the extension of the ADD might affect the price levels of the products manufactured using the subject goods, it is noted that fair competition in the Indian market will not be reduced by the ADD. The objective of imposition of the anti-dumping measure is to remove the unfair advantages gained by the dumping practices, to prevent the decline of the domestic industry and help maintain availability of wider choice to the consumers of the subject goods.

- b. As regards period of investigation, the Rules state as follows:

*The period of investigation shall, -*

(i) *not be more than six months old as on the date of initiation of investigation;*

(ii) *be for a period of twelve months normally and for reasons to be recorded in writing, the designated authority may consider a minimum of six months or maximum of eighteen months.*

- c. The Authority has considered the period of investigation (POI) for the purpose of the present investigation as 1<sup>st</sup> October, 2019 to 30<sup>th</sup> September, 2020 (12 months). The injury examination period has been considered as the period from 2017-18, 2018-19, 2019-20, and the POI. The period of investigation is found appropriate and in accordance with the AD Rules.
- d. As regards the post-POI data, it is noted that the examination of the post-POI data is not mandatory in a sunset review investigation. The likelihood analysis conducted by the Authority, herein below, is sufficient to analyse whether there is a need for extension of the ADD on the subject goods.

## **G. ASSESSMENT OF DUMPING – METHODOLOGY AND PARAMETERS**

### **Normal Value, Export Price and Determination of Dumping Margin**

#### **G.1. Submissions of the other interested parties**

29. The following submissions have been made by the other interested parties with regard to the normal value, the export price and the dumping margin:

- a. The surrogate country methodology should not be used in calculating the normal value for this case, regardless of whether China PR is treated as a market economy country. India has no basis for calculating the normal value using the non-market economy methodology.
- b. India is bound by 'pacta sunt servanda' and must fulfil its obligations under the relevant agreements and recognize China PR's full market economy status by amending the relevant domestic regulations.
- c. The Authority cannot use the import price from USA to determine the normal value as it would go against the previous findings of the Authority. An examination as to whether such methodology which was rejected previously can be adopted in subsequent reviews should be provided.
- d. The domestic industry has failed to clarify what adjustments were made to the import price (CIF) to arrive at the ex-factory normal value.
- e. The claim of the dumping margin is exaggerated and incorrect even if the claim of the domestic industry regarding the basis for determination of the normal value is accepted.

#### **G.2. Submissions of the domestic industry**

30. The following submissions have been made by the domestic industry with regard to the normal value, the export price and the dumping margin:

- a. The Authority shall follow Para 1-6 of Annexure I for determination of the normal value only if the responding companies from China PR establish that their costs and price information is such that an individual normal value and the dumping margin can be determined. If the responding companies from China PR are not able to demonstrate that their costs and the price information can be adopted, the Authority shall reject the claim of an individual dumping margin.
- b. Unless the producers / exporters in China PR establish that their costs and the prices are reliable, their domestic costs and the prices cannot be accepted for determination of the normal value. In view of the failure of the producers and exporters to demonstrate that they are operating under market economy conditions, the normal value should be determined in accordance with the provisions of para 7 of Annexure – I to the Anti-Dumping Rules.
- c. China PR is not being treated as a non-market economy merely based on domestic regulations, but also on the basis of Article 15(a)(i) of China's Accession Protocol which continues to operate even after 11th December, 2016.
- d. China PR has failed to fulfil its obligations under the Accession Protocol and failed to remove distortions to allow the prices to be set by the market, as a result of which even other WTO members, including USA and the European Union have continued to treat China PR as a non-market economy.
- e. The applicant claims that since the normal value cannot be determined on the basis of the price or the constructed value in a market economy third country for the reason that the relevant information is not publicly available, the determination of the normal value for China PR should be on the basis of the price from a market economy third country to the other country including India. The applicant has used the import price of the subject goods from the USA into India.

- f. The USA is an appropriate market economy third country since it is a major producer and exporter of the subject goods into India with significant volumes and China PR is comparable to USA in the level of economy and development. The subject goods produced in the USA are also like article to those produced in China PR and India, using the similar manufacturing process. The exports from USA to India are also in the ordinary course of trade.
- g. The applicant has taken the CIF price and adjusted the same for ocean freight, inland freight, marine insurance, port expenses, commission, bank charges and VAT to determine the export price.
- h. The dumping margin is not only above de-minimis but also significant for the subject country.
- i. The CESTAT in Kuitun Jinjiang Chemical Industry Co. Ltd vs Union of India held that the level of development is not a relevant consideration while considering the import price of a surrogate country as the normal value. The previous findings of the Designated Authority in rejecting import price of USA as the normal value are against the CESTAT order and, therefore, not binding on the Authority.

### **G.3. Examination by the Authority**

31. Under section 9A (1) (c), normal value in relation to an article means:

- i) *The comparable price, in the ordinary course of trade, for the like article, where meant for consumption in the exporting country or territory as determined in accordance with the Rules made under sub-section (6), or*
- ii) *When there are no sales of the like article in the ordinary course of trade in the domestic market of the exporting country or territory, or when because of the particular market situation or low volume of the sales in the domestic market of the exporting country or territory, such sales do not permit a proper comparison, the normal value shall be either:*
  - (a) *comparable representative price of the like article when exported from the exporting country or territory or an appropriate third country as determined in accordance with the Rules made under sub-section (6); or*  
*the cost of production of the said article in the country of origin along with reasonable addition for administrative, selling and general costs, and for profits, as determined in accordance with the Rules made under sub-section (6);*
  - (b) *Provided that in the case of import of the article from a country other than the country of origin and where the article has been merely trans shipped through the country of export or such article is not produced in the country of export or there is no comparable price in the country of export, the normal value shall be determined with reference to its price in the country of origin.*

32. The Authority sent questionnaires to the known producers/exporters from the subject country, advising them to provide information in the form and manner prescribed by the Authority. The following producers/exporters have co-operated in this investigation by filing the prescribed questionnaire responses:

- i. M/s Sinochem Environmental Protection Chemicals (Taicang) Co. Ltd. (Producer/ Exporter)
- ii. M/s Shaanxi Sinochem Lantian New Chemical Material Co. Ltd. (Producer/ Exporter)
- iii. M/s Shandong Dongyue Chemical Co. Ltd. (Producer/ Exporter)
- iv. M/s Zhejiang Sanmei Chemical Ind. Co. Ltd. (Producer/ Exporter)
- v. M/s Zhejiang Quhua Fluor-chemistry Co. Ltd. (Producer/ Exporter)
- vi. M/s Zhejiang Quzhou Lianzhou Refrigerants Co. Ltd. (Producer/ Exporter)
- vii. M/s Sinochem Lantian Trading Co. Ltd. (Domestic seller)
- viii. M/s Sinochem Xián Jincool New Chemical Materials Co. Ltd. (Trader)
- ix. M/s Sinochem Lantian Fluoro Materials Co. Ltd. (Domestic seller)
- x. M/s Sinochem Modern Environmental Protection Chemical (Xián) Co. Ltd. (Formerly producer)

### **Market Economy Status for Chinese Producers**

33. Article 15 of China's Accession Protocol in WTO provides as follows:

*"Article VI of the GATT 1994, the Agreement on Implementation of Article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994 ("Anti-Dumping Agreement") and the SCM Agreement shall apply in proceedings involving imports of Chinese origin into a WTO Member consistent with the following:*

*"(a) In determining price comparability under Article VI of the GATT 1994 and the Anti-Dumping Agreement, the importing WTO Member shall use either Chinese prices or costs for the industry under investigation or a*

*methodology that is not based on a strict comparison with domestic prices or costs in China based on the following rules:*

*(i) If the producers under investigation can clearly show that market economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard to the manufacture, production and sale of that product, the importing WTO Member shall use Chinese prices or costs for the industry under investigation in determining price comparability;*

*(ii) The importing WTO Member may use a methodology that is not based on a strict comparison with domestic prices or costs in China if the producers under investigation cannot clearly show that market economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard to manufacture, production and sale of that product.*

*(b) In proceedings under Parts II, III and V of the SCM Agreement, when addressing subsidies described in Articles 14(a), 14(b), 14(c) and 14(d), relevant provisions of the SCM Agreement shall apply; however, if there are special difficulties in that application, the importing WTO Member may then use methodologies for identifying and measuring the subsidy benefit which take into account the possibility that prevailing terms and conditions in China may not always be available as appropriate benchmarks. In applying such methodologies, where practicable, the importing WTO Member should adjust such prevailing terms and conditions before considering the use of terms and conditions prevailing outside China.*

*(c) The importing WTO Member shall notify methodologies used in accordance with subparagraph (a) to the Committee on Anti-Dumping Practices and shall notify methodologies used in accordance with subparagraph (b) to the Committee on Subsidies and Countervailing Measures.*

*(d) Once China has established, under the national law of the importing WTO Member, that it is a market economy, the provisions of subparagraph (a) shall be terminated provided that the importing Member's national law contains market economy criteria as of the date of accession. In any event, the provisions of subparagraph (a)(ii) shall expire 15 years after the date of accession. In addition, should China establish, pursuant to the national law of the importing WTO Member, that market economy conditions prevail in a particular industry or sector, the non-market economy provisions of subparagraph (a) shall no longer apply to that industry or sector."*

34. It is noted that while the provision contained in Article 15 (a) (ii) have expired on 11.12.2016, the provision under Article 2.2.1.1 of WTO read with obligation under 15 (a) (i) of the Accession Protocol require criterion stipulated in Para 8 of the Annexure I of the Rules to be satisfied through the information/data to be provided in the supplementary questionnaire on claiming the market economy status. It is noted that since the responding producers/exporters from China PR have not submitted response to this questionnaire in the form and manner prescribed, the normal value computation is required to be done as per the provisions of Para 7 of Annexure I of the Rules.

35. The normal value and the export price for all the producers/exporters from the subject country have been determined as below.

#### **G.4. Determination of the Normal Value**

36. Para 7 of Annexure I of the Rules reads as under:

*In case of imports from non-market economy countries, normal value shall be determined on the basis of the price or constructed value in the market economy third country, or the price from such a third country to other countries, including India or where it is not possible, or on any other reasonable basis, including the price actually paid or payable in India for the like product, duly adjusted if necessary, to include a reasonable profit margin. An appropriate market economy third country shall be selected by the designated authority in a reasonable manner, keeping in view the level of development of the country concerned and the product in question, and due account shall be taken of any reliable information made available at the time of selection. Accounts shall be taken within time limits, where appropriate, of the investigation made in any similar matter in respect of any other market economy third country. The parties to the investigation shall be informed without any unreasonable delay the aforesaid selection of the market economy third country and shall be given a reasonable period of time to offer their comments.*

37. The Authority notes that the prices or the constructed value of the product in an appropriate market economy third country have neither been made available by the applicant or any other interested party nor it is available with the Authority from any public source. It is also noted that the interested parties have not provided any verifiable information which could have been adopted by the Authority. However, the Authority notes that the verifiable evidence and the published information is available on the import price of the subject goods from USA to India. USA is also a major producer and exporter of the subject goods into India and employs similar manufacturing process. Further, the imports from USA constitute the second largest imports of the subject goods after the subject country. Therefore, the Authority finds USA to be an appropriate surrogate country for China PR. Also, the

determination of the normal value on the basis of the import price from the market economy third country to India was upheld by the CESTAT in the matter of Kuitun Jinjiang Chemical Industry Co. Ltd. The subject goods imported into India from the USA are the like article to those produced in the subject country and in India. The normal value so determined is given below in dumping margin table.

#### **G.5. Determination of the Export Price**

##### **Sinochem Environmental Protection Chemicals (Taicang) Co., Ltd. (Producer) and Shaanxi Sinochem Lantian New Chemical Material Co., Ltd. (Producer)**

38. During the POI, Sinochem Environmental Protection Chemicals (Taicang) Co., Ltd., has exported \*\*\* MT of PUC to India both in packed and unpacked forms for invoice value of \*\*\* US\$, out of which \*\*\* MT of the PUC has been exported to India by Sinochem Environmental Protection Chemicals (Taicang) Co., Ltd., through another trader, namely, Honeywell Trading (Shanghai) Co., Ltd., China PR. However, this trader has not filed its response with the Authority and, therefore, the Authority has applied the best facts available for the exports made by this trader for the final determination export price for the producer.

39. It is further noted that during the POI, Shaanxi Sinochem Lantian New Chemical Material Co., Ltd., a producer/exporter of subject goods, has directly exported \*\*\* MT of PUC to India in unpacked forms for invoice value \*\*\* US\$. Shaanxi Sinochem Lantian New Chemical Material Co., Ltd. is a related company of Sinochem Environmental Protection Chemicals (Taicang) Co., Ltd.

40. Sinochem Environmental Protection Chemicals (Taicang) Co., Ltd., and Shaanxi Sinochem Lantian New Chemical Material Co., Ltd., China PR have claimed adjustments on account of ocean freight, insurance, inland transportation, port and other related expenses, credit cost and packing expenses, which have been allowed. Accordingly, the weightage average export price at ex-factory level for Sinochem Environmental Protection Chemicals (Taicang) Co., Ltd., and Shaanxi Sinochem Lantian New Chemical Material Co., Ltd., China PR has been determined and same is shown in Dumping Margin table below.

##### **Shandong Dongyue Chemical Co. Ltd. (Producer)**

41. During POI, Shandong Dongyue Chemical Co., Ltd. has directly exported \*\*\* MT of PUC to India in packed form for invoice value of \*\*\* US\$. Shandong Dongyue Chemical Co., Ltd., has claimed adjustments on account of ocean freight, inland transportation, port and other related expense, packing expenses and bank charges, which have been allowed. Accordingly, the net export price at ex-factory level for Shandong Dongyue Chemical Co., Ltd., has been determined and same is shown in Dumping Margin table below.

##### **Zhejiang Sanmei Chemical Ind. Co., Ltd. (Producer)**

42. Zhejiang Sanmei Chemical Ind. Co., Ltd. is a producer cum exporter of the subject goods who has exported \*\*\* MT of the subject goods to India directly in the POI in unpacked form. The adjustments have been claimed on account of ocean freight, marine insurance, inland transportation & port expenses, which have been allowed by the Authority. Accordingly, the net export price at ex-factory level has been determined and the same is shown in Dumping Margin table below.

##### **Zhejiang Quhua Fluor-Chemistry Co., Ltd and Zhejiang Quzhou Lianzhou Refrigerants Co., Ltd**

43. Zhejiang Quhua Fluor-Chemistry Co. Ltd. ("Quhua") and its related company, namely, Zhejiang Quzhou Lianzhou Refrigerants Co., Ltd. ("Lianzhou") are the producers of the subject goods in China PR and have exported the subject goods to India directly to unrelated customers.

44. During the POI, Quhua and Lianzhou have exported \*\*\* MT and \*\*\* MT of subject goods respectively directly to the unrelated customers in India both in packed and unpacked forms. The responding producers/exporters have claimed adjustments on accounts of ocean freight, insurance, inland transportation, handling charges, bank charges and credit cost which have been allowed by the Authority. The ex-factory export price of Quhua and Lianzhou so determined is given in the dumping margin table below.

##### **Non-cooperative exporters from China PR**

45. The export price in respect of other exporters from China PR has been determined as per the facts available in terms of Rule 6(8) of the Rules. For the purpose, the Authority has considered the imports as reported in the DGCIS and the questionnaire response of the cooperating producer and exporters.

#### **G.6. Determination of the Dumping Margin**

46. It is noted that in the subject investigation many cooperating producers and exporters are related to each other and form a group of related companies. It has been the consistent practice of the Authority to consider related exporting producers and exporters as one single entity for the determination of a dumping margin and, thus, to establish one single dumping margin for them. This is, in particular, because calculating the individual dumping margins might encourage circumvention of the anti-dumping measures, thus, rendering them ineffective by

enabling the related exporting producers to channelise their exports to India through the company with the lowest individual dumping margin.

47. Considering the normal value and the export price for the subject goods, the dumping margins for the subject goods from subject country have been determined as follows:

SN	Producers	CNV (US\$/MT)	NEP (US\$/MT)	Dumping Margin (US\$/MT)	Dumping Margin (%)	Dumping Margin (Range %)
1.	Sinochem Environmental Protection Chemicals (Taicang) Co., Ltd. and Shaanxi Sinochem Lantian New Chemical Material Co., Ltd.	***	***	***	***	60-70
2.	Shandong Dongyue Chemical Co., Ltd.	***	***	***	***	110-120
3.	Zhejiang Sanmei Chemical Ind. Co. Ltd.	***	***	***	***	50-60
4.	Zhejiang Quhua Fluor-chemistry Co. Ltd. and Zhejiang Quzhou Lianzhou Refrigerants Co. Ltd.	***	***	***	***	45-55
5.	Non-cooperative/ residual exporters	***	***	***	***	125-135

## **H. ASSESSMENT OF INJURY AND THE CAUSAL LINK**

### **H.1. Submissions of the other interested parties**

48. The following submissions have been made by other interested parties with regard to the injury and the causal link:

- The petitioner has withheld information regarding the temporary shutdown of Dahej site, as mentioned in Annual Report 2019-20. Therefore, the injury is attributable to the shutdown and not to the imports from China PR.
- The claims of the petitioner contradict the information in their 49<sup>th</sup> Annual Report.
- The petitioner has claimed artificial injury to obtain undue protection. The claim of the increase in the imports of the PUC is baseless. The decline in the import volume from the subject country is more than the decline in the import volume from the other countries. The domestic industry is targeting China PR when injury could have possibly been caused due to the imports from the other countries.
- The decline in the sales of the domestic industry in the period of investigation along with the total demand is due to COVID-19 as already admitted by the domestic industry in the oral hearing. The imports are not the cause of the material injury to the domestic industry. Further, the market share of the domestic industry increased while that of the subject imports and the imports from the other countries declined.
- The claim of losses during the period of investigation does not match with the Annual Report of the company and, therefore, should be critically examined.
- The losses, if any, are due to underutilization of the petitioner's capacities and increase in the captive consumption. The expansion of the capacity and the production of the PUC despite decline in demand is also a reason for the injury suffered. If the petitioner had the capacity much more than the demand, it should have increased its price in order to recover any loss. The available information indicates that the capacity utilisation of the domestic industry has been historically low and is low in the POI.
- The increase in the wages of the employees is possible only when the company is making profits. The petitioner has manipulated the data to show artificial injury to get protection.
- The cash profits increased from 16 to 36 in the period of investigation and, therefore, the decline is due to COVID-19 and not attributable to the subject imports. The overall performance of the domestic industry has remained healthy during the entire injury period and the period of investigation.

- i. The 49th Annual Report for the year ended March 31, 2020 shows excessive growth in the PBT, the Profit Before Interest, the Depreciation & Tax (PBIDT), the total income in the POI compared to the financial year 2018-19.
- j. The demand for the subject product in India is in Range of 8000 MT to 9000 MT while India has the capacity in the range of 13000 MT to 15000 MT. Major share of the Indian demand is catered by the petitioner itself and the imports from China PR are very low.
- k. There is no causal link between the imports from the subject country and the alleged injury. The absence of the causal link is evident from the lack of correlation between the landed price, the price undercutting and the profitability.
- l. The material injury also occurred due to the higher fixed cost on account of the increased capacity which is much in excess to the present demand and should not be attributed to China PR.
- m. It cannot be claimed that the current injury and the causal link are immaterial in a sunset review application as the petitioner itself claimed that there is a causal link between the injury and the imports from China PR.
- n. The petitioner did not reduce the price despite fall in cost of sales, thereby, showing superior pricing power.
- o. There is an inverse relation between the landed price from China PR and the profitability of the petitioner, showing that there was something else hindering the profits of the petitioner. The ROCE also showed similar movement. The decrease in the profits is due to the increase in the interest costs and the depreciation due to the increase in the capital expenditure and the capacity enhancement.
- p. The imports from the US are in significant volumes and higher than the import volumes from the subject country. It is not clear how the injury caused due to the imports from the US will be segregated and will not be imputed on the subject imports from China PR.

## **H.2. Submissions of the domestic industry**

49. The following submissions have been made by the domestic industry with regard to the injury and the causal link:
- a. The imports have continued to enter in the Indian market at dumped prices.
  - b. The subject imports have increased in the POI in absolute terms as well as in relation to the production and consumption in India.
  - c. The imports are undercutting and underselling the prices of the domestic industry.
  - d. The imports have been suppressing the domestic prices.
  - e. The profitability of the domestic industry has significantly declined over the injury period.
  - f. The performance of the domestic industry in respect of cash profits, PBIT and the return on the capital employed has declined significantly over the injury period. In the event of cessation of the duties, the profitability of the domestic industry would be further impacted.
  - g. The inventories with the domestic industry have increased significantly over the injury period.
  - h. The production, sales and the capacity utilization of the domestic industry have declined significantly in the POI.
  - i. There exists a causal link between the dumped subject imports and the injury suffered by the domestic industry.
  - j. As regards the temporary shutdown of Dahej plant, the shutdown was in the first quarter of the period and was related to speciality chemical business segment. The product under consideration is part of the refrigerant business segment & not part of the speciality chemical business segment and hence the injury claimed by the domestic industry is not attributed to the shutdown.
  - k. As regards the imports from the other countries causing injury, China PR constitutes the highest share in the total imports into India and the Chinese import prices are the lowest during the injury period except in 2018-19.
  - l. As regards matching the claim of losses with Annual Reports, the domestic industry has claimed injury only for the domestic performance while the Annual report covers overall performance including the non-PUCs, the performance in the export markets, etc.
  - m. The increase in the capacity is required in order to cater to the applicant's own captive requirement and demand in India and ensures continued supply of the product under consideration. Even if the capacity is



considered at the same level, it will still show decline in the capacity utilization due to continuous presence of the dumped imports into India.

- n. As regards the captive consumption, the captive consumption of the domestic industry has declined during the period of investigation whereas the imports have increased. The losses to the domestic industry are not because of increase in the captive consumption.
- o. The domestic industry has not claimed injury on the basis of employment, wages or the productivity. The exporters are trying to mislead the Authority away from the facts by raising irrelevant arguments.
- p. The decline in the profits of the domestic industry clearly shows that the domestic industry is unable to move its prices in proportion to the cost.
- q. The interest and the depreciation cost of the domestic industry have declined during the period of investigation as compared to 2018-19.
- r. The domestic industry has not filed any petition for the USA in the current period. Further, the imports price from USA are significantly higher than the import prices from China PR. The injury to the domestic industry is due to the dumped imports from China PR.
- s. As regards the COVID-19 situation, the position of the domestic industry must be considered, not in the context of ideal conditions but in the specific circumstances of the domestic industry. The companies are affected by Covid-19 globally.

### **H.3. Examination by the Authority**

50. The submissions made by the domestic industry with regard to the injury and the causal link related issues have been examined. The injury analysis made by the Authority hereunder ipso facto addresses the various submissions made by the interested parties.

51. The Authority has taken note of the arguments and counter-arguments of all the interested parties with regard to the injury to the domestic industry. The injury analysis so made by the Authority hereunder addresses the various submissions made by the interested parties.

52. As regards the submission that alleged injury to the domestic industry is due to other reasons and there is no injury as per statements in the Annual Reports of the domestic industry, the Authority notes that the injury analysis carried out hereunder is self-explanatory.

53. As regards the submission that the alleged injury to the domestic industry is due to temporary shutdown of Dahej site, it has been clarified by the domestic industry that the shutdown was in the first quarter of the period and was related to speciality chemical business segment which is not the business segment of the product under consideration. The product under consideration is part of the refrigerant business segment.

54. Rule 11 of the Rules read with its Annexure-II thereto provides that an injury determination shall involve examination of factors that may indicate injury to the domestic industry, "... taking into account all relevant facts, including the volume of the dumped imports, their effect on the prices in the domestic market for like articles and the consequent effect of such imports on the domestic producers of such articles."

55. Rule 23 of the Rules provides that the provisions of Rule 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19, and 20 shall apply mutatis mutandis in the case of a review. In case the performance of the domestic industry shows that it has not suffered injury during the current injury period, the Authority shall determine whether cessation of the present duty is likely to lead to recurrence of the injury to the domestic industry.

56. The Authority has examined the current injury, if any, to the domestic industry before proceeding to examine the likelihood aspects of the dumping and the injury on account of the imports from the subject country. It has been examined as to whether there is an increase in the imports, in absolute terms or in relation to the production or the consumption. In considering the effect of the dumped imports on the prices, it is considered necessary to examine whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like article in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress the prices to a significant degree or prevent the price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree. For the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry in India, indices having a bearing on the state of the industry such as production, capacity utilization, sales volume, stock, profitability, net sales realization, the magnitude and margin of dumping, etc. have been considered in accordance with Annexure-II of the Rules. The Authority has taken note of the various submissions of the domestic industry and the other interested parties, and has analysed the same considering the facts available on record and applicable laws. The injury analysis made by the Authority hereunder ipso facto addresses the various submissions made by the parties.

#### **H.3.1. Volume effect of dumped imports on domestic industry**

##### **a. Assessment of demand/apparent consumption**

57. The Authority has taken into consideration, for the purpose of the present investigation, the demand or the apparent consumption of the product in India as the sum of the domestic sales of Indian producers and the imports from all sources.

Particular	Unit	2017-18	2018-19	2019-20	POI
Sales of Domestic Industry	MT	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Index</i>	<i>100</i>	<i>115</i>	<i>114</i>	<i>94</i>
Sales of Other Indian producer including supporter	MT	-	-	-	-
Subject Country- China	MT	2,053	1,214	1,074	1,309
Imports from Other Countries	MT	2,975	2,864	2,964	2,171
Total Indian Demand	MT	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Index</i>	<i>100</i>	<i>98</i>	<i>97</i>	<i>82</i>

58. It is seen that the demand for the subject goods declined over the injury period and the period of investigation. However, the subject imports increased in the period of investigation as compared to 2018-18 and 2019-20 despite a decline in demand.

**b. Import volumes from the subject country.**

59. With regard to the volume of the dumped imports, the Authority is required to consider whether there has been a significant increase in the dumped imports, either in absolute terms or relative to the production or the consumption in India. For the purpose of the injury analysis, the Authority has relied on the transaction wise import data procured from DGCI&S. The factual position is as follows:

Particular	Unit	2017-18	2018-19	2019-20	POI
Subject Country- China	MT	2,053	1,214	1,074	1,309
<i>Trend</i>	<i>Index</i>	<i>100</i>	<i>59</i>	<i>52</i>	<i>64</i>
Subject Country Imports in relation to					
Total Imports	%	41	30	27	38
<i>Trend</i>	<i>Index</i>	<i>100</i>	<i>73</i>	<i>65</i>	<i>92</i>
Production	%	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Index</i>	<i>100</i>	<i>54</i>	<i>46</i>	<i>65</i>
Consumption	%	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Index</i>	<i>100</i>	<i>60</i>	<i>54</i>	<i>78</i>

60. It is seen that:

- The imports from the subject country have declined in 2018-19 and further in 2019-20 but have increased thereafter in the period of investigation.
- The import from the subject country has shown the same trend in relation to the production and the consumption in India. The imports from the subject country have increased in relation to the production and consumption during the period of investigation as compared to 2018-19 and 2019-20.
- The imports have increased during the period of investigation despite anti-dumping duty in existence.

**H.3.2. Price effect of the dumped imports**

61. With regard to the effect of the dumped imports on the prices, it is required to be analysed whether there has been a significant price undercutting by the alleged dumped imports as compared to the price of the like products in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress the prices or prevent the price increases, which otherwise would have occurred in the normal course. The impact on the prices of the domestic industry on

account of the dumped imports from the subject country has been examined with reference to the price undercutting, the price suppression and the price depression, if any. For the purpose of this analysis, the cost of production, the non-injurious price (NIP) and the net sales realization (NSR) of the domestic industry have been compared with the landed price of the imports of the subject goods from the subject country.

**a. Price undercutting**

62. For the purpose of the price undercutting analysis, the selling price of the domestic industry has been compared with the import price from the subject country. Accordingly, the undercutting effects of the dumped imports from the subject country work out as follows:

Particular	Unit	2017-18	2018-19	2019-20	POI
<b>Total</b>					
Net Sales Realisation	₹/KG	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Index</i>	<i>100</i>	<i>102</i>	<i>106</i>	<i>105</i>
Landed price	₹/KG	270	332	307	271
Price undercutting	₹/KG	***	***	***	***
Price undercutting	%	***	***	***	***
<i>Price undercutting</i>	<i>% Range</i>	<i>20-30</i>	<i>0-10</i>	<i>10-20</i>	<i>20-30</i>
<b>Unpacked</b>					
Net Sales Realisation	₹/KG	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Index</i>	<i>100</i>	<i>102</i>	<i>108</i>	<i>107</i>
Landed price	₹/KG	221	300	238	210
Price undercutting	₹/KG	***	***	***	***
Price undercutting	%	***	***	***	***
<i>Price undercutting</i>	<i>% Range</i>	<i>20-30</i>	<i>0-10</i>	<i>20-30</i>	<i>30-40</i>
<b>Packed</b>					
Net Sales Realisation	₹/KG	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Index</i>	<i>100</i>	<i>102</i>	<i>100</i>	<i>97</i>
Landed price - China	₹/KG	309	360	334	309
Price undercutting	₹/KG	***	***	***	***
Price undercutting	%	***	***	***	***
<i>Price undercutting</i>	<i>% Range</i>	<i>30-40</i>	<i>20-30</i>	<i>20-30</i>	<i>20-30</i>

63. It is seen that the imports from the subject country, both in packed as well as unpacked forms, are entering at a price below the domestic selling price of the domestic industry resulting in positive undercutting.

**b. Price suppression and depression**

64. In order to determine whether the dumped imports are depressing or suppressing the domestic prices and whether the effect of such imports is to suppress prices to a significant degree or prevent the price increase which otherwise would have occurred in the normal course, the changes in the costs and the prices over the injury period have been examined. The table below shows the factual position:

Particular	Unit	2017-18	2018-19	2019-20	POI
Cost of sales - Domestic	₹/KG	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Index</i>	<i>100</i>	<i>123</i>	<i>133</i>	<i>137</i>
Net Sales Realisation	₹/KG	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Index</i>	<i>100</i>	<i>102</i>	<i>106</i>	<i>105</i>

Landed Price	₹/KG	270	332	307	271
<i>Trend</i>	<i>Index</i>	<i>100</i>	<i>123</i>	<i>113</i>	<i>100</i>
Decline over previous year					
Cost of sales – Domestic	₹/KG	-	63	28	11
Selling price - Domestic	₹/KG	-	7	14	(3)
Landed price	₹/KG	-	61	(25)	(35)

65. It is seen that the landed price of the imports is below the costs of the domestic industry over the injury period. While the costs have increased over the injury period, the domestic industry is unable to increase their selling price in proportion to the increase in the cost, resulting in price suppression.

### H.3.3. Economic parameters of the Domestic industry

66. Annexure II to the Rules provides that the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry should include an objective and unbiased evaluation of all relevant economic factors and the indices having a bearing on the state of the industry, including the actual and potential decline in the sales, the profits, the output, the market share, the productivity, the return on investments or the utilization of capacity; the factors affecting the domestic prices, the magnitude of the margin of dumping; the actual and potential negative effects on the cash flow, the inventories, the employment, the wages, the growth, the ability to raise capital investments. The various injury parameters relating to the domestic industry are discussed below.

67. The Authority has examined the injury parameters objectively taking into account various facts and the arguments made by the interested parties in their submissions.

#### i. **Production, capacity, capacity utilization and sales**

68. The capacity, production, sales and the capacity utilization of the domestic industry over the injury period is given in the table below:

Particular	Unit	2017-18	2018-19	2019-20	POI
Capacity	MT	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Index</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>115</i>	<i>130</i>
Production Quantity PUC	MT	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Index</i>	<i>100</i>	<i>109</i>	<i>113</i>	<i>99</i>
Capacity Utilization	%	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Index</i>	<i>100</i>	<i>109</i>	<i>98</i>	<i>76</i>
Domestic Sales	MT	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Index</i>	<i>100</i>	<i>115</i>	<i>114</i>	<i>94</i>

69. It is seen that:

- The domestic industry expanded its installed capacity in 2019-20 and further in the period of investigation.
- The production of the domestic industry increased till 2019-20 but declined thereafter in the period of investigation.
- The capacity utilization increased in 2018-19 but declined in 2019-20 and further significantly in the period of investigation.
- The domestic sales of the domestic industry increased in 2018-19 but declined in 2019-20 and further significantly in the period of investigation.

#### ii. **Market Share in the demand**

70. The market share of the domestic industry is shown in the table below:

Particular	Unit	2017-18	2018-19	2019-20	POI
Domestic Industry	%	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Index</i>	<i>100</i>	<i>118</i>	<i>118</i>	<i>116</i>

Subject Country China PR	%	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Index</i>	<i>100</i>	<i>60</i>	<i>54</i>	<i>78</i>
Other Countries	%	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Index</i>	<i>100</i>	<i>98</i>	<i>103</i>	<i>89</i>
Total	%	100	100	100	100

71. It is seen that whereas the market share of the domestic industry increased and of other countries declined in comparison to the base year, the market share of the subject country has increased during the period of investigation over the previous year. The market share of the subject country had increased despite the decline in the demand and the anti-dumping duty in existence.

### iii. Inventories

72. The inventory position with the domestic industry over the injury period and the POI is given in the table below:

Particular	Unit	2017-18	2018-19	2019-20	POI
Opening Stock	MT	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Index</i>	<i>100</i>	<i>103</i>	<i>87</i>	<i>70</i>
Closing Stock	MT	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Index</i>	<i>100</i>	<i>85</i>	<i>148</i>	<i>195</i>
Average Stock	MT	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Index</i>	<i>100</i>	<i>94</i>	<i>118</i>	<i>133</i>

73. It is seen that the average inventories with the domestic industry have increased substantially in the period of investigation.

### iv. Profitability, cash profits and return on capital employed

74. The profitability, cash profits and the return on investment of the domestic industry over the injury period are given in the table below:

Particular	Unit	2017-18	2018-19	2019-20	POI
Profit/(Loss) Before Tax	₹/KG	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Index</i>	<i>100</i>	<i>33</i>	<i>19</i>	<i>5</i>
Profit/Loss Before Tax	₹ Lacs	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Index</i>	<i>100</i>	<i>38</i>	<i>21</i>	<i>4</i>
Cash Profit	₹ Lacs	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Index</i>	<i>100</i>	<i>56</i>	<i>42</i>	<i>31</i>
Profit Before Tax, Interest & depreciation	₹ Lacs	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Index</i>	<i>100</i>	<i>66</i>	<i>52</i>	<i>41</i>
Return on Capital Employed	%	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Index</i>	<i>100</i>	<i>56</i>	<i>33</i>	<i>18</i>

75. It is seen that:

- The profits of the domestic industry have declined significantly over the injury period and the period of investigation.
- The cash profits and the return on capital employed has also declined over the injury period including the period of investigation.

### v. Employment, wages and productivity

76. The employment, the wages and the productivity of the domestic industry over the injury period are given in the table below:

Particular	Unit	2017-18	2018-19	2019-20	POI
Wages	₹ Lacs	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Index</i>	<i>100</i>	<i>147</i>	<i>187</i>	<i>174</i>
Employment	Nos.	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Index</i>	<i>100</i>	<i>149</i>	<i>141</i>	<i>130</i>
Wages Per Unit	Rs/MT	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Index</i>	<i>100</i>	<i>135</i>	<i>167</i>	<i>176</i>
Productivity per Employee	MT	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Index</i>	<i>100</i>	<i>74</i>	<i>80</i>	<i>76</i>
Productivity per day	MT	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Index</i>	<i>100</i>	<i>109</i>	<i>113</i>	<i>99</i>

77. It is seen that the wages and the employment of the domestic industry have increased in the period of investigation compared to the base year. However, the productivity, both in terms of the employee and the days, has declined in the period of investigation compared to the previous year as well as the base year.

#### vi. Growth

78. The growth of the domestic industry in terms of the production, the inventories, and the profits is as per given in the table below:

Particular	Unit	2017-18	2018-19	2019-20	POI
Production	Y/Y%	-	9	3	(12)
Domestic Sales Volume	Y/Y%	-	15	(2)	(17)
Cost of sales domestic	Y/Y%	-	23	8	3
Selling price domestic	Y/Y%	-	3	5	(0)
Profit/Loss domestic	Y/Y%	-	(67)	(44)	(74)
Average stock	Y/Y%	-	(6)	26	13

79. It is seen that the growth of the domestic industry is negative with respect to major volume parameters like the production, the domestic sales and the profits.

#### vii. Magnitude of dumping margin

80. The magnitude of dumping is an indicator of the extent to which the imports are being dumped in India. The investigation has shown that dumping margin is positive in the period of investigation.

#### viii. Ability to raise capital investment

81. The domestic industry has not claimed injury on this account. It is seen that the domestic industry is a multi-product company. The investment decisions may not be based solely on the performance of a particular product during the injury period and may be governed by the long-term prospects of the product.

#### ix. Factors affecting domestic prices

82. It is seen that the domestic industry is the sole domestic supplier of the product. Further, the landed price of the imports is below the cost of the domestic industry throughout the injury period. Resultantly, the domestic industry is unable to increase its prices in proportion to the increase in the cost. It is thus seen that the import prices are directly affecting the prices of the domestic industry in the market. The price suppression suffered by the domestic industry is due to lower price of the imports.

83. The dumped imports are impacting the prices of the domestic industry. Hence, it is concluded that the principal factor affecting the domestic prices is the dumped imports of subject goods.

#### x. Magnitude of price underselling/injury margin

84. The Authority has determined the NIP for the domestic industry on the basis of the principles laid down in the Anti-Dumping Rules, read with Annexure III, as amended. The NIP of the PUC has been determined by adopting the information/data relating to the cost of production provided by the domestic industry and duly certified by the practicing cost accountant for the period of investigation. The NIP has been considered for comparing the landed price from the subject country for calculating the injury margin. For determining the non-injurious price, the best utilisation of the raw materials of the domestic industry over the injury period has been considered. The same treatment has been carried out with the utilities. The best utilisation of the production capacity over the injury period has been considered. It is ensured that no extraordinary or non-recurring expenses were charged to the cost of production. A reasonable return (pre-tax @ 22%) on the average capital employed (i.e., average net fixed assets plus average working capital) for the PUC was allowed as pre-tax profit to arrive at the non-injurious price as prescribed in Annexure III of the Rules and being followed. Separate NIP has been determined for the unpacked and the packed form of the product. The NIP so determined has been considered for calculating injury margin.

85. The landed price for the cooperating exporters has been determined from the CIF export price adopted for the purpose of dumping margin determination. The applicable customs duties have been added to determine the landed price of the imports. For all the non-cooperative producers/ exporters from the subject country, the Authority has determined the landed price based on the facts available.

86. Based on the landed price and the NIP determined as above, the injury margin for the producers/exporters from China PR is provided in the table below.

SN	Producers	Non-Injurious Price (US\$/MT)	Landed Value (US\$/MT)	Injury Margin US\$/MT	Injury Margin (%)	Injury Margin (Range %)
1.	Sinochem Environmental Protection Chemicals (Taicang) Co., Ltd. and Shaanxi Sinochem Lantian New Chemical Material Co., Ltd.	***	***	***	***	70-80
2.	Shandong Dongyue Chemical Co., Ltd.	***	***	***	***	70-80
3.	Zhejiang Sanmei Chemical Ind. Co. Ltd.	***	***	***	***	80-90
4.	Zhejiang Quhua Fluor-chemistry Co. Ltd. and Zhejiang Quzhou Lianzhou Refrigerants Co. Ltd.	***	***	***	***	60-70
5.	Non-cooperative/ residual exporters	***	***	***	***	120-130

#### **H.3.4. Conclusion on injury**

87. The examination of the imports of the subject goods and the performance of the domestic industry clearly shows that the volume of dumped imports from the subject country has increased in absolute terms and in relative terms in the period of investigation as compared to 2018-19 and 2019-20. The imports from the subject country are undercutting the prices of the domestic industry and the price underselling is positive. The imports from the subject country are suppressing the prices of the domestic industry. The production, sales, market share and the capacity utilization has declined during the period of investigation as compared to previous year and inventories have increased for the domestic industry in the period of investigation. The performance of the domestic industry has significantly deteriorated in respect of profitability, profits, cash profits and return on capital employed. In view of the foregoing, the Authority concludes that the domestic industry has suffered injury despite the anti-dumping duty in existence.

#### **I. CAUSAL LINK & NON-ATTRIBUTION ANALYSIS**

88. The Authority also examined any known factors other than the dumped imports which at the same time might have been injuring the domestic industry so that the injury caused by these other factors, if any, is not attributed to the dumped imports. The factors which are relevant in this respect include, inter-alia, the volume and the prices of

the imports not sold at the dumped prices, the contraction in demand or the changes in the patterns of consumption, the trade restrictive practices of and the competition between the foreign and the domestic producers, the developments in technology and the export performance and the productivity of the domestic industry. The Authority examined whether factors other than the dumped imports could have contributed to the injury to the domestic industry.

**a) Volume and prices of imports from third countries**

89. It is seen that the imports from the other countries (other than dumped imports) are either de-minimis or at higher prices. Thus, third country imports could not have been a cause of the injury to the domestic industry.

**b) Contraction in Demand**

90. It is seen that the demand for the product under consideration has declined over the injury period and the period of investigation. However, the subject imports have increased in the period of investigation despite a fall in the domestic demand and the anti-dumping duty in existence. Therefore, the contraction in the demand cannot be considered as a reason for the injury to the domestic industry.

**c) Changes in Pattern of consumption**

91. No evidence has been brought forward by any interested parties about any material change(s) in the pattern of consumption of the product under consideration. Therefore, possible changes in the pattern of consumption are not the cause of the injury considered by the Authority.

**d) Conditions of competition and trade restrictive practices**

92. The Authority notes that the investigation has not shown that conditions of competition or the trade restrictive practices are responsible for the injury considered by the Authority.

**e) Developments in technology**

93. No evidence has been brought forward by any interested parties about the existence of significant changes in the technology that could have caused the injury to the domestic industry.

**f) Export performance of the domestic industry**

94. The Authority has considered the data for the domestic operations only for the injury analysis. Therefore, the export performance is not the cause for the injury to the domestic industry.

**g) Performance of other products**

95. The domestic industry has provided the injury data for the PUC and the same has been adopted by the Authority for the purpose of the injury analysis. The performance of the other products produced and sold by the applicant is not a possible cause of the injury to the domestic industry.

96. Thus, the Authority concludes that the domestic industry has not suffered injury in the POI due to other factors.

**I.1. Conclusion on the Causal Link**

97. The Authority concludes that the domestic industry has not suffered injury in the POI due to other factors. Further, the following factors show that the injury to the domestic industry is due to the subject dumped imports:

- a. The import price is consistently below even the cost of sales of the domestic industry. As a result, the domestic industry is unable to increase its selling price along with the increase in the cost of sales.
- b. The imports are undercutting the prices of the domestic industry. The landed price of the imports is not only below the selling price of the domestic industry but also the cost of production in the POI.
- c. The dumped imports are causing a significant suppressing effect on the prices of the product in the market.
- d. The adverse impact of the imports on the selling price of the domestic industry has led to a significant decline in its profitability. Resultantly, this has caused a significant deterioration in profits, cash profits and the return on capital employed.
- e. As a result of the low-priced imports, the market share of the domestic industry has declined whereas that of subject imports has increased. As a result, the production, sales and the capacity utilization of the domestic industry has declined and the inventory with the domestic industry has increased.
- f. The growth of the domestic industry has become negative in respect of the several economic parameters.



98. The Authority, thus, concludes that there exists a causal link between the dumping of the subject goods and injury to the domestic industry.

## **J. LIKELIHOOD OF CONTINUATION/ RECURRENCE OF DUMPING AND INJURY**

99. In a review investigation, the Authority is required to determine whether the subject goods are continuing to enter or likely to enter the Indian market at dumped prices and whether the injury to the domestic industry is likely to continue or recur due to these dumped imports if the duty is allowed to cease.

### **J.1 Submissions by the other interested parties**

100. The following submissions have been made by the other interested parties with regard to the likelihood:

- a. The claims of the petitioner in respect of the excess production capacities, the unutilized capacities, the market share, the export orientation and India being a lucrative market for the exporters from China PR etc. are just imaginary, concocted and not based on the facts. Disposable capacities with the exporters do not imply that the unutilized capacities are used only to export to India. There is no likelihood of continued or recurrence of the dumping and the consequent injury.
- b. The excess capacity in China PR cannot be more than 5-10K MT. Such capacity is normal and is a buffer required to meet production disruptions. There is no major idle capacity.
- c. The figures for excessive, freely disposable and idle capacities are not sacrosanct as they cover various HFCs which are not the product under consideration. The reliance on such figures can result in completely distorted findings.
- d. The alternative data from a 2017 finding by USITC in AD investigation concerning R-134a should be relied upon instead. USITC observed a capacity of 169000MT, capacity utilization of 94% and observed that the Chinese producers may have limited unused capacity. Sanmei is not aware of any significant capacity additions in China PR in the recent times and the overall capacity observed by USITC may be still relevant.
- e. The petitioner has claimed the unutilised capacity of China PR to be at about 79,160 Metric Tons. However, the excess capacity may not be even in the range of 5000 to 10000 assuming the capacity utilization to be in range of 94% to 95%.
- f. The petitioner alleged that the duties in force were absorbed fully which is patently incorrect from the statistics as the imports were completely range bound. Thus, the imports from China PR clearly cannot be considered to be a threat to the domestic industry. There is no relevant basis for the likelihood as historical volume of the imports negates such claims as bereft of any merit.
- g. The limited impact of the PUC is reflective of the fact that there is no significant idle capacity in China PR.
- h. The anti-dumping duties were imposed by the other countries as early as 2017 and after 2017, the exports to India have not increased. It cannot be believed that the exporters will hold on and continue with any such idle capacity for years waiting for the duty to expire so that they can cater to very minimal demand in India.
- i. The fall in demand in the major market like the EU and the USA due to banning of use of the product can lead to fall in export of subject goods to such countries. But even in that event, any utilized capacity will undergo closure or modifications and will not be kept alive for the limited Indian market for the PUC.
- j. The product under consideration is expected to be phased out of production and the supply due to its environmental impact. Thus, it is not reasonable to presume that the substantial share of total HFC capacity by the producers/exporters in the subject country will be devoted towards the PUC.
- k. The claim of the surplus capacities should be verified based on the data provided in the questionnaire responses of the participating exporters.
- l. The excess capacities do not imply intention to offload in India at the dumped prices as held in Graphite Electrodes from China PR, and this cannot be considered as posing a clearly foreseen and imminent threat of the injury as held in Indian Spinners Association v. Designated Authority.
- m. Since India is also a signatory to the Kyoto Protocol and consequently the PUC is also expected to be phased out in India, the demand is likely to decline in India as well, just like the USA and the EU.
- n. The analysis of the performance parameters of the exporters by the domestic industry is based on indexed data and not the actual information. There is no capacity addition by Zhejiang Quzhou Lianzhou. Sales to India is insignificant compared to the domestic sales. There is sufficient demand

domestically and in third countries to dispose of the excess capacities. The allegation of discriminatory pricing is incorrect. The exports to India declined in the POI.

- o. The capacity addition of Quhua Fluo-chemistry is inconsequential since the export is made in unpacked form while substantial Chinese export is in packed form. The sales to India are insignificant. There is no incentive for the respondent to incur loss and capture market when the product is being phased off.
- p. Export price of the Chinese producers to the third countries is higher than that to India; therefore, India is not a price attractive market.

## **J.2 Submissions by the domestic industry**

101. The following submissions have been made by the domestic industry with regard to the likelihood:

- a. The dumping margins in the original investigation and the subsequent investigations have been significant. The subject goods are being dumped despite the ADD in force. Hence, in the event of cessation of the ADD, the dumping and consequent injury would continue.
- b. The Chinese producers of the subject goods have capacities significantly higher than the Chinese demand. In the event of cessation of the ADD, India will become an attractive market for them.

Particulars	Quantity (tonnes per annum)
Total capacity of Chinese producers	237,160*
Production of subject goods in China (2019)	158,000
Consumption of subject goods in China (2019)	57,000
Export of subject goods from China (2019)	101,000

\*Not entirely dedicated to the subject goods

- c. The Chinese producers of the subject goods have an unutilised capacity of 79,160 MT and freely disposable capacity of 180,000MT which is significantly higher than the Indian demand. In the event of cessation of the ADD, these capacities will likely be diverted to India at dumped prices.

Particulars	Quantity (tonnes per annum)
Total capacity of Chinese producers	2,37,160
Production of subject goods in China (2019)	1,58,000
Consumption of subject goods in China (2019)	57,000
Export of subject goods from China (2019)	1,01,000
Unutilized capacities	79,160
Freely disposable capacities	1,80,160

- d. The USA and the EU have taken measures to phase out the use of the subject goods following the ratification of the Kyoto Protocol. With significant decline in the demand in these countries, the Indian market would become more attractive. Hence, in the event of cessation of the ADD, there would a substantial increase in the dumped imports into India from the subject country.
- e. The US, in 2017, imposed the ADD on the imports of the subject goods from China PR into the USA. This affects Chinese access to their largest export market. Hence, there would a surge in the subject imports to India in the event of cessation of the ADD.
- f. India is the most lucrative market for the subject country since the subject country has a long history of dumping in India. India is one of their largest export destinations. Significant Chinese produce of the subject goods is being exported and the demands in the USA and the EU is declining.
- g. The analysis of the exporter questionnaire responses shows that there exists a likelihood of the dumping and the consequent injury to the domestic industry. The exports to India increased while the exports to the third countries declined. There is significant reduction in the PBIT and the increase in the inventories, the production and the capacities by the exporters as well as discriminatory pricing behaviour between the domestic and the export sales.

- h. The interchangeability of the production facilities itself establishes that the producers can switch their production as per the market conditions. In the event of cessation of the antidumping duty, the producers can easily increase their production of the product under consideration and increase the export to India.
- i. Zhejiang Quhua Fluor-Chemistry Co., Ltd has increased its capacity by 17% in the year 2018.
- j. The product under consideration is not phasing out in India in the next five years and the domestic industry has requested extension of the duties for next 5 years only. Further, if the PUC phases out within 5 years, then the extension of anti-dumping duty will have no effect on the exporter concerned.
- k. Since only few exporters have responded, their capacities should not be considered as the entire capacity in China PR.

### **J.3 Examination by the Authority**

102. All factors brought to the notice of the Authority have been examined to determine as to whether there is a likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury in the event of cessation of the duty. The Authority has considered the information as made available by the domestic industry and the other interested parties in order to evaluate the likelihood of continuation or recurrence of the dumping and the injury.

103. The Authority has examined the likelihood of continuation or recurrence of the injury considering the requirement laid down under Section 9A (5), Rule 23 and parameters relating to the threat of material injury in terms of Annexure – II (vii) of the Rules and other relevant factors brought on record by the interested parties. The present investigation is a sunset review of ADD earlier imposed on the imports of the subject goods from China PR. Under the Rules, the Authority is required to determine whether continued imposition of the ADD is warranted. This also requires a consideration of whether the duty imposed is serving the intended purpose of eliminating injurious dumping. There are no specific methodologies available to conduct such a likelihood analysis. However, clause (vii) of Annexure II of the Rules provides, inter-alia, for factors which are required to be taken into consideration viz.:

- i. A significant rate of increase of the dumped imports into India indicating the likelihood of substantially increased importation;
- ii. Sufficient freely disposable, or an imminent, substantial increase in, the capacity of the exporter indicating the likelihood of substantially increased dumped exports to Indian markets, taking into account the availability of other export markets to absorb any additional exports;
- iii. Whether the imports are entering at the prices that will have a significant depressing or suppressing effect on the domestic prices and would likely increase the demand for further imports; and
- iv. The inventories of the article being investigated.

#### **i. Continued & existing dumping and injury**

104. The Authority notes that the imports of the product under consideration in the current period of investigation are at dumped prices despite anti-dumping duty in existence. It is also noted that the performance of the domestic industry has significantly deteriorated in respect of the profits, cash profits and the return on capital employed. It is also seen that the subject imports are undercutting the prices of the domestic industry.

#### **ii. Surplus capacities in the subject country**

105. The analysis of the questionnaire responses filed by the responding exporters shows as follows:

Particular - POI	Sinochem Environmental Protection Chemicals (Taicang) Co. Ltd.	Shaanxi Sinochem Lantian New Chemical Material Co. Ltd.	Shandong Dongyue Chemical Co. Ltd.	Zhejiang Sanmei Chemical Ind. Co. Ltd.	Zhejiang Quhua Fluor-chemistry Co. Ltd.	Zhejiang Quzhou Lianzhou Refrigerants Co. Ltd.	Sinochem Modern Environmental Protection Chemicals (Xi'an) Co. Ltd	Total
Capacity - (MT)	***	***	***	***	***	***	***	1,71,000
Production - (MT)	***	***	***	***	***	***	***	1,49,871
Capacity utilization - (%)	***	***	***	***	***	***	***	88



below normal value								
Volume above normal value	***	***	***	***	***	***	***	512
Demand in India	***	***	***	***	***	***	***	
Export Volume below normal value/NIP as % of demand in India								
Normal value	***	***	***	***	***	***	***	>700%
NIP	***	***	***	***	***	***	***	>700%

112. It is seen that:

- Significant volume (almost 99%) of the exports by these exporters to the third countries at the dumped and the injurious prices.
- The volume of exports to third countries at dumped/ injurious prices is 8 times the demand for the subject goods in India.

**vi. Export orientation of the producers in the subject countries**

113. The Authority notes from the responses that the producers in the subject countries are export oriented.

**Conclusion on Likelihood of Dumping and Injury**

114. The evidence on record shows that the imports of the product under consideration in the current period of investigation are at dumped prices despite anti-dumping duty in existence. The capacities with the responding Chinese exporters are far higher than the Indian demand. The unutilised capacity of the responding Chinese producers is 8 times the demand for the subject goods in India. Significant exports to the other countries which in the event of cessation of ADD could be diverted to India. Considering the decline in demand in major markets like the US and EU, India becomes a potential destination for trade diversion. The responding producers/exporters have also admitted that the fall in demand in major market like the EU and the USA due to banning of the use of the product can lead to fall in export of subject goods to such countries. There are trade remedial measures in place on the imports of the subject goods from China PR into the USA since 2017. The exporters and producers of the product under consideration from China PR are dumping the product under consideration into India despite anti-dumping duty in force. The imports from the subject country are undercutting the prices of the domestic industry during the POI, and the undercutting margin is significant, which suggests that the cessation of the ADD currently in place is likely to lead to intensified dumping causing injury to the domestic industry. Significant volume (almost 99%) of the exports by these exporters to the third countries at the dumped and the injurious prices. The producers in the subject countries are export oriented. Export price from subject country to other countries are lower than the price at which the product is exported into India. India is the prices attractive market for the responding exporters and in the event of cessation of Anti-dumping duty, the imports from China PR are likely to increase at dumped price causing injury to the domestic industry. In view of the above, it is concluded that there is a likelihood of dumping and injury in the event of cessation of existing anti-dumping duty.

**K. POST-DISCLOSURE COMMENTS**

**K.1. Submissions of the other interested parties**

115. The following post-disclosure comments have been made by the other interested parties:

- Correct facts relevant for the consideration of parameters relating to the threat of material injury has not been considered and hence it is requested that Annexure II (vii) be separately examined for Sanmei.
- The claims of likelihood are unsubstantiated and the slight increase in imports in the POI cannot be considered the basis for likelihood. Further, Sanmei exported a higher volume to other countries for a higher price, and the inventory level of the company has also substantially reduced in the POI.
- The loss of market in third countries have not contributed to the injury as the subject imports from Sanmei have declined over the years to India and recorded the lowest during the POI.
- Other factors such as third country imports, fall in demand etc. has to be addressed properly by the Authority.

- e. The petitioners failed to establish beyond doubt that expiry of the existing anti-dumping duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry as envisaged in Rule 23 (1B) of the Anti-dumping Rules. On the contrary, the submissions by the company show absence of likelihood or recurrence of dumping and injury to the domestic industry in the event of expiry of present duties.
- f. The facts of the present case clearly show that the petitioner did not suffer any injury and the petitioner is not vulnerable to any injury on account of import of the PUC from China PR as their performance is not influenced by imports from China PR but by other factors. The overall situation justifies expiry of present anti-dumping duties applicable on imports of the subject goods from the subject country.
- g. The PUC from USA is primarily in unpacked form and the PUC from China PR are mostly in packed form. Thus, USA cannot be considered an appropriate surrogate.
- h. Normal value adopted on the basis of USA import price in the petition varies from the constructed normal value disclosed. It is unclear how import price of 291 INR/KG from the USA can be used to calculate normal value of 356 INR/KG.
- i. The disclosure statement does not state whether ocean freight, insurance, credit cost, etc adjustments were made to the import price from the USA to bring it to ex-factory price before being considered as normal value for the purposes of this review.
- j. The volume of imports in relation to production and consumption has decreased during the injury investigation period. The volume of imports in relation to production and consumption declined by 35 and 22 index points respectively in the POI as compared to the base year. The increase in import volumes between 2018-19 and the POI is nominal.
- k. The market share in demand of the domestic industry has grown by 16% in the POI as compared to the base year whereas that of the subject imports has declined.
- l. Price undercutting in 2018-19 was at lowest in the injury period at 0-10% whereas the landed price in the same year was highest at 332 Rs/Kg. However, the domestic industry experienced sharpest reduction in profit per unit in 2018. The domestic industry's performance during the POI include periods where the Covid-19 pandemic was at its peak. The Covid-19 pandemic that gripped 2020 must also be considered as a factor for any alleged injury to the domestic industry during the POI.
- m. The existence of duty in the US will not directly lead to export destination substitution for the exports of the PUC from China PR into India due to the fact that the demand in the Indian market has declined steadily from the base year to the POI. Regardless of duty imposition by the US, India will not be attractive to exporters because of declining demand.
- n. The Authority has stated that the producers in the subject countries are export oriented. However, the domestic sales of the respondents are far more significant than their exports to India, hence they are not export oriented and their primary market is domestic.
- o. There is a significant difference between net export price and landed price determined by the DGTR and the actual submission. The ex-factory export price and landed value for both the participating producers/exporters are required to compute separately and then compute the weightage average ex-factory export price and landed value for both participating producers/exporters as group.
- p. A bulk to bulk and pack to pack comparison to determine dumping and injury margins by undertaking separate analysis for packed and unpacked forms of the PUC is required.
- q. Constructed normal value and non-injurious price determined by the Authority is excessively high and undue/inflated dumping margin and injury margin would lead to the monopolistic market which will significantly harm the competitive environment and healthy development of the Indian industries.
- r. The significant reduction by 36% in terms of imports of the PUC from China PR and substantial increment in net selling price of the domestic industry during the POI prove that the injury sustained by the petitioner is not due to imports from China PR.
- s. A reasonable return of 22% on capital employed is highly inflated and gives undue advantage and protection to the domestic industry. The Director General should consider the return earned by the petitioner in the past when there was no allegation of dumping as reasonable return and adopt the same as reasonable return to arrive at the non-injurious price.
- t. No surplus capacities are available with the producers/exporters from China PR as Sinochem Environmental Protection Chemicals (Taicang) Co., Ltd. is already operating at more than 100% capacity utilization. Thus, the claim of idle capacities and freely disposable capacity in China PR should be out rightly rejected as any relevant

basis to determine likelihood in the matter as the historical volume of imports nullifies such claims as bereft of any merit. Reference is placed on *Indian Spinners Association v. Designated Authority*, (2004 (170) ELT 144).

- u. The applicant made losses in the financial year of 2019-20 when further additions in capacity were made. The capacity addition was carried out when the prevailing capacity was also underutilized and any injury on such self-inflicted causes should not be attributed to subject imports.
- v. As mentioned in SRF Limited's Annual Report 2019-2020, there are 13% customer complaints registered against the petitioner in the Fluorochemicals Business which demonstrates the fact that the PUC produced in SRF Limited is of poor quality that prevents them from producing quality grades and specialty grades of the PUC.
- w. Not only does the petitioner have superior pricing capacity, but also there is an inverse relation between the landed price from China PR and the profitability of the petitioner.
- x. When the landed price increased from Rs 270 Kg during the base year to Rs 304 Kg in the financial year of 2019-20, profitability moved from 100 to (12) points which indicates that it is not the imports obstructing the profits of the petitioner. Further, when the landed price declined between POI and the previous year, profitability of the DI increased from (12) points to 11 points as well as selling price which would not have been possible if the petitioner was impacted by the fall in landed price.
- y. The anti-dumping duty has been in force for 12 years. The information provided by the domestic industry does not indicate existence of any special circumstance that require continuation of antidumping duty beyond a 12 years period. Reliance is placed on the findings in *Dry Cell Batteries* where the Authority endeavors to not continue duty beyond a period of 10 years except in special cases.

## **K.2. Submissions of the domestic industry**

116. The following post-disclosure comments have been made by the domestic industry.

- a. Sinochem Taicang has the obligation to ensure all their export sales of the subject goods to India are accounted. They have provided misleading and false information on channel of marketing of the goods for export sales to India in their questionnaire response.
- b. Sinochem Taicang concealed the fact that one of their exporters remained non-cooperative. This impairs the rights of the domestic industry and misdeclaration of such information warrants rejection of response. Instruction 4 to the exporter questionnaire and the certificate filed by the producer and declaration by the legal representative are relied on.
- c. The Authority failed to note the share of exports of Sinochem Taicang through the non-cooperative trader.
- d. The export price for the sales channel with the non-cooperative unrelated exporter should be calculated based on sale price of the subject goods from Sinochem Taicang to first exporter adjusted for ex-factory expenses.
- e. The non-cooperative unrelated exporter, Honeywell Trading (Shanghai) Co. Ltd. has a practice of non-cooperation despite exporting significant volumes to India. A responding producer from China PR was held non-cooperative in the recent final finding in AD investigation on "HFC Component R-32" due to non-cooperation by the same exporter.
- f. The residual dumping margin in the present investigation has tripled compared to previous investigations. The present residual injury margin is also significantly higher than those in previous investigations. The injurious effect of Chinese imports has increased in every investigation. As per Rule 23(1) of the AD Rules, the quantum of ADD maybe enhanced if necessary to counteract dumping which is causing injury. Hence, enhancement of ADD is warranted.
- g. The Authority may determine normal value on the basis of imports of the subject goods from UK to India since UK is an appropriate surrogate country to China PR. The information on the same, segregated as packed and unpacked, has already been provided by the domestic industry. UK is also a major producer and exporter to India using similar manufacturing process. The subject goods imported from UK to India is like article to those imported from China PR and those produced in India.
- h. The domestic industry has been unable to base their pricing decisions on their cost of sales. Since, the subject imports are not just undercutting but are also below the cost of sales of the domestic industry, it acts as the price benchmark for the PUC in the Indian market. During the POI, the domestic industry was forced to reduce selling price despite increase in costs leading to significant erosion of profits. Further the Authority may conclude the existence of a causal link.
- i. There is a likelihood of continuation/recurrence of dumping and injury in the event of cessation of ADD in light of the following:

- i. Just 38% of the unutilized capacities of the Chinese producers is sufficient to meet the entire Indian demand. Their capacity utilization of responding exporters have declined in the POI which shows they are capable of achieving higher capacity utilization. The Chinese producers maintain significant inventories which the Authority is requested to examine. Since the EU and the USA are phasing out the subject goods, the exports of the Chinese producers to third countries, which is 8 times the Indian demand, be largely diverted to India. Since India is not allowed to expand capacity for the subject goods after 2023 as per Kigali Amendment to the Montreal Protocol and China PR has established very large surplus capacities, the Chinese producers are incentivized to dump the product. In the event of cessation of the ADD, the subject imports to India would increase. Failure to protect domestic HFC industry will weaken the automobile manufacturing supply chain.
- ii. Since normal value is below the selling price of the domestic industry, third country exports below the normal value are also below selling price of the domestic industry, which makes Indian market attractive. The Authority is requested to compare prices for exports to third countries and those to India as it would show significant volumes is below export price with ADD to India making Indian market attractive.
- iii. Considering the declining demand in the USA and EU, the exports to India is bound to increase in light of the Authority's finding that the responding producers are export oriented.
- j. None of the users/ importers have provided any relevant information for non-imposition of the ADD. The only interested parties are the exporters who seek to protect their unfair trade practices. Lack of participation by users/ importers shows no adverse impact on them.
- k. The following shows that the ADD has no adverse impact on consumers and public at large:
  - i. Extension of ADD will arrest the deterioration in performance of the domestic manufacturer that is suffering injury due to dumping. Despite no demand-supply gap, the domestic industry has only 56% market share and 57% capacity utilization.
  - ii. If domestic industry is allowed to suffer injury, they would be wiped out and Chinese imports would gain total monopoly. The Indian consumers would be at their mercy and will have to maintain higher inventories and incur additional costs for the same. Procuring from the domestic industry will ensure fair price stability, uninterrupted supply, growth of downstream industry and a stable and reliable business partner.
  - iii. It is in public interest to have a strong, competitive domestic production of the subject goods. The objective of ADD is price correction and ensuring fair competition by encouraging imports from USA and UK.
  - iv. The cost of the PUC in the final product is very minimal and will have almost no effect on end users.
  - v. The domestic industry quadrupled their capacity with a huge investment to make India self-sufficient on imposition of the ADD in 2011. The domestic industry can meet current and potential demand in India. If injury continues, sustainable returns on these investments would not be generated.
  - vi. In the absence of dumped imports, the domestic industry would have capacity utilization of 87% compared to present 57%.
  - vii. Since India is not allowed to increase capacity on subject goods after 2023, the domestic industry had made investments and increased capacities. Safeguarding the domestic HFC industry is essential to protect existing investment and promote fresh investments.
  - viii. Adoption of innovative and viable alternatives to HFCs by the domestic industry will provide India a global competitive edge in the industry and boost growth. If injury is sustained, the domestic industry will be unable to invest in R&D to develop alternatives.
  - ix. There exist other sources that export the subject goods to India and have significant market share. Since the subject goods is phased out in EU and USA, any production would only serve export markets including India. Extension of ADD will neither give the domestic industry a monopoly not affect availability of the subject goods.
  - x. The domestic industry is able to maintain positive trade balance despite the dumping. If injury is allowed to continue, the same cannot be maintained.

### **K.3.Examination by the Authority**

117. The Authority has examined the post disclosure submissions made by all the interested parties and notes that some of the arguments are reiterations which have already been examined suitably and addressed adequately in the



relevant paras of the findings. The issues raised for the first time in the post-disclosure comments/submissions by the interested parties and considered relevant by the Authority are examined below:

- i. As regards the normal value, the likelihood, the injury and the public interest, the same are addressed by the Authority in the relevant paragraphs of these findings
- ii. As regards the argument of rejection of the response filed by Sinochem Taicang, the Authority notes that the non cooperating trader Honeywell Trading (Shanghai) Co. Ltd accounts for very less percentage of the total exports by Sinochem Taicang and, therefore, the response of the producer has been accepted. As regards the unreported exports, the Authority has applied best facts available for the exports made by this trader for the final determination of the export price for the producer.
- iii. As regards the calculation of the weightage average ex-factory export price and the landed value computed for Sinochem group, the Authority notes that the same has been calculated as per the Rules laid down and the prevailing practice of the Authority.
- iv. As regards the comparison on the packed and the unpacked forms of the PUC, the Authority notes that dumping margin and injury margin have been compared for the packed and the unpacked forms and then weighted average has been taken.
- v. As regards the calculation of the NIP, the Authority notes that the determination has been made as per the Rules laid down and the prevailing practice of the Authority.
- vi. As regards the inferior quality of the product produced by the domestic industry as compared to the imported product under consideration, the Authority notes that the other interested parties have not provided adequate information to establish the same. Also, in *DSM Idemitsu vs DA* [(2000(119) E.L.T.308], the Hon'ble Tribunal has noted that the difference in quality cannot be the relevant criteria for considering the imported product as different from the domestic like product.
- vii. As regards the argument on the statements in the annual report, the Authority notes that SRF manufactures around 71 products. The consolidated statement in the annual report is not reflective of the performance of the product under consideration. Further, the injury analysis carried out in the relevant paragraphs of these findings is self-explanatory to establish that the dumping has caused continued injury to the domestic industry. Further, the public statements like the annual reports of the company do not alter the conclusion that the dumping of the product has caused injury to the domestic industry.
- viii. As regards the argument of inverse relation between the landed price from China PR and the profitability of the petitioner, it is noted that the landed price of the imports is below the costs of the domestic industry over the injury period. Therefore, even after an increase in the landed price of the imports, it was still below the cost of sales of the domestic industry. Resultantly, while the costs have increased over the injury period, the domestic industry is unable to increase its selling price in proportion to the increase in the cost, resulting in price suppression and decline in the profitability.
- ix. As regards the need for extension of the anti-dumping duty, the Rules require the Authority to determine whether cessation of ADD is likely to lead to continuation or recurrence of the dumping and the injury to the domestic industry. It is further noted that the recommendation for extension of the anti-dumping duty is made only when the requisite legal requirements are met.
- x. As regards the argument on the appropriateness of the import price from the USA into India for considering the normal value, the same is addressed by the Authority in the relevant paragraphs of these findings. Para 7 of the Annexure I lays down hierarchy for determination of the normal value and provides that normal value shall be determined on the basis of the price or constructed value in a market economy third country, or the price from such a third country to the other countries, including India, or where it is not possible, on any other reasonable basis, including the price actually paid or payable in India for the like product, duly adjusted, if necessary, to include a reasonable profit margin. Thus, the Authority notes that the normal value is required to be determined having regard to the various sequential alternatives provided under Para 7 of the Annexure I. There is no information provided by any interested party to consider application of the first proviso of para 7 nor any material is available with the Authority for the same. The imports from USA constitute second largest imports of the product under consideration into India. Therefore, the Authority has considered USA as an appropriate surrogate country and determined the normal value based on the imports price from USA to India. As regards the argument on difference in level of development of China PR and USA, the Authority refers to *Kuitun Jinjiang Chemical Industry Co. Ltd. vs Union of India* wherein the Hon'ble CESTAT held that the level of development would be relevant only if the domestic sale price or the cost of production of a market economy third country is adopted since the level of development affects the price and the cost. The price in the international trade is a function of demand and supply in the international market and it is not affected by the level of development of the supplier country. The price to India is, therefore, the price meant for consumption in the Indian market. When the second option under paragraph 7 is exercised for determination of the normal value, what is relevant is the volume of exports and the country

concerned should not be dumping during the period of investigation, since these parameters will affect the price comparability in the Indian market. Further, it is noted that considering the cost of production in India as normal value would have led to higher dumping margin for all the responding exporters.

- xi. As regards the argument that the imports from the US are only in unpacked form, the Authority while calculating the normal value for the packed form has added verified packing cost. The Authority notes that since USA constitutes second largest share in the total imports into India, USA is being considered appropriate surrogate country.
- xii. As regards the argument on the likelihood of dumping and the injury, the relevant paragraphs of these findings address the same. As regards the argument on the price attractiveness, the Authority has examined the exports by responding exporters to third country. Summarized table is as follows:

Volume in MT	Sinochem Environmental Protection Chemicals (Taicang) Co. Ltd.	Shaanxi Sinochem Lantian New Chemical Material Co. Ltd.	Shandong Dongyue Chemical Co. Ltd.	Zhejiang Sanmei Chemical Ind. Co. Ltd.	Zhejiang Quhua Fluor-chemistry Co. Ltd.	Zhejiang Quzhou Lianzhou Refrigerants Co. Ltd.	Sinochem Lantian Fluoro Materials Co., Ltd	Total
Volume below DI NSR	***	***	***	***	***	***	***	63,422
Volume above DI NSR	***	***	***	***	***	***	***	161
Volume below CIF price into India	***	***	***	***	***	***	***	54,465
Volume above CIF price into India	***	***	***	***	***	***	***	9,118
Volume below CIF price into India with ADD (Without BCD)	***	***	***	***	***	***	***	62,321
Volume above CIF price into India with ADD (Without BCD)	***	***	***	***	***	***	***	1,262

xiii. It would be seen that

- 99.75% of exports from responding exporters are at a price lower than the export price to India.
- 85.66% of exports from responding exporters are at a price lower than the selling price of India
- 98.02% of exports from responding exporters are at a price lower than the CIF export price with Anti-dumping duty to India
- India is the prices attractive market for the responding exporters and in the event of cessation of Anti-dumping duty, the imports from China PR are likely to increase at dumped price causing injury to the domestic industry.

#### **L. INDIAN INDUSTRY'S INTERESTS AND OTHER ISSUES**

118. The Authority recognizes that the imposition of the anti-dumping duties might affect the price levels of the product in India. However, fair competition in the Indian market will not be reduced by the imposition of the anti-dumping measures. On the contrary, the imposition of the anti-dumping measures would remove the unfair advantages gained by the dumping practices, prevent the decline of the domestic industry and help maintain the availability of wider choice to the consumers of the subject goods. The purpose of the anti-dumping duties, in general, is to eliminate injury caused to the domestic industry by the unfair trade practices of dumping so as to re-establish a situation of open and fair competition in the Indian market, which is in the general interest of the country. The imposition of the anti-dumping duties, therefore, would not affect the availability of the product to the consumers. The Authority notes that the imposition of the anti-dumping measures would not restrict the imports from the subject country in any way and, therefore, would not affect the availability of the product to the consumers. On the contrary, the extension of the ADD would encourage imports from other sources including the USA and the UK.

119. The Authority considered whether extension of ADD shall have adverse public interest. For the same, the Authority examined whether the extension of the anti-dumping duty on imports of the product under investigation would be against the larger public interest. This determination is based on consideration of information on record and interests of various parties, including domestic industry, importers, and consumers of the product.

120. The Authority issued gazette notification inviting views from all interested parties, including importers, consumers, and other interested parties. The Authority also prescribed a questionnaire for the consumers to provide relevant information with regard to present investigations, including possible effect of ADD on their operations. The Authority sought information on, inter-alia interchange ability of the product supplied by various suppliers from different countries, ability of the domestic industry to switch sources, effect of ADD on the consumers, factors that are likely to accelerate or delay the adjustment to the new situation caused by extension of ADD.

121. None of the users, importers, or user associations have opposed the present investigation. As already noted in these findings, this leads to the presumption that the user industry in India is not adversely impacted by the extension of the ADD on the subject goods. Further, in this regard, the Authority re-iterates that the extension of the anti-dumping measures would not restrict the imports from the subject country in any way and, therefore, would not affect the availability of the product to the consumers.

122. Even though the Authority has prescribed formats for the users to quantify the impact of ADD and elaborate how extension of ADD shall adversely impact them, it is noted that none of the interested parties have provided relevant information. It is, thus, noted that the interested parties have not established impact of ADD on the user industry with verifiable information. Further the domestic industry has quantified the impact of the recommended anti-dumping duty on the consumer industry and submitted that the impact is minimal.

123. The Authority notes that the domestic industry has submitted that the PUC is produced globally. China has a capacity of 240 KTPA, North America has a combined capacity of 102 KTPA, and European Union and Japan have a capacity of 20 KTPA each. The product in under free category and, therefore, can be freely imported from various countries. The extension of the anti-dumping measures would not restrict imports from China in any way and, therefore, would not affect the availability of the product to the consumers. The extension of anti-dumping duties, therefore, would neither affect the availability of the product to the consumers nor create monopoly.

124. USA has also investigated the imports of the product under consideration into USA from China PR. USA imposed a significant quantum of duties on the said imports, on finding that the imports are causing material injury to their domestic industry.

125. The Authority notes that the product is consumed mainly in automobile air conditioning and the domestic industry has stated that India is likely to witness a robust growth in HFCs in the next decade. The domestic industry has also submitted that they have quadrupled their capacity since the initial imposition of ADD on the subject imports in 2011 with an investment of Rs. 530 crores. The domestic industry is, hence, capable of meeting the present and potential demand of the product under consideration in India.

126. Further the capacity utilization of the domestic industry is low in the period of investigation and declined as compared to preceding year as well as the base year. The domestic industry had the potential to cater the much higher degree of demand in India. However, due to dumping of the product under consideration, the domestic industry was faced with unutilized capacity.

127. It is noted that the interested parties have not demonstrated how the prices of subject goods have adversely impacted the consumers. On the other hand, the domestic industry has submitted quantified information showing that the impact of the proposed antidumping duty on the user industry would be miniscule. The domestic industry has submitted that the cost of product under consideration in the final product is very minimal and will have almost no effect on the end-users. For example, assuming that a compact car in India costs Rs. 2,50,000, the amount of R-134a used in the air conditioner would be less than 500g. Assuming that 500g of R-134a costs around Rs. 150, the cost of the product under consideration on the end-consumer of the final product is very meagre.

128. It is, thus, noted that while the interested parties have not established possible adverse impact of proposed ADD on the user industry with verifiable information, the domestic industry has established the lack of any such adverse impact. Despite the ADD being in force for 10 years, there is no publicly available evidence showing an adverse impact on the user industry either. Thus, even if it is considered that the extension of ADD might affect the price levels of the product manufactured using the subject goods, the impact of the antidumping duty on the eventual product would be grossly insignificant. Further, fair competition in the Indian market will not be reduced by the anti-dumping measure, particularly if the levy of the ADD is restricted to an amount necessary to redress the injury to the domestic industry. The objective of imposition of anti-dumping measure is to remove the unfair advantages gained by dumping practices; to prevent the injury to the domestic industry and help maintain availability of wider choice to the consumers of the subject goods.

129. The Authority further notes that the recommendation for extension of duty is made only when the requisite legal requirements are met. The interested parties contended that the domestic industry has been using trade defence quite often. It is, however, noted that the domestic industry has reported that it is engaged in production of 71 products and is at present protected by ADD only 4 products. The domestic industry has further submitted that they have not, in the past, taken advantage of the ADD in place on the subject goods to increase their selling price disproportionately. Considering the fact that the domestic industry has been able to maintain a positive trade

balance in the subject goods, the health of the domestic industry is also in the interest of the economy of the country.

130. From the information on record, it is also noted that the impact of anti-dumping duty is miniscule to the consumers of the product under consideration, and the Authority is of the view that the extension of anti-dumping duty will be in public interest.

#### **M. CONCLUSION & RECOMMENDATIONS**

131. After examining the submissions made by the interested parties and issues raised therein, and considering the facts available on record, the Authority concludes that:

- a. The petitioner constitutes domestic industry under Rule 2(b) of the Rules and the application satisfied the criteria of standing in terms of Rule 5(3) of the Rules.
- b. The product produced by the domestic industry is the like article to the product under consideration imported from the subject country.
- c. The petition contained all the information relevant for the purpose of initiation of investigation and the application contained sufficient evidence to justify initiation of the investigation.
- d. Considering the normal value and the export price for the subject goods, the dumping margins for the subject goods from the subject country have been determined, and the margins are significant.
- e. The domestic industry has suffered continued injury. The examination of the imports of the subject goods and the performance of the domestic industry clearly shows that the volume of the dumped imports from the subject country has declined over the injury period increased thereafter in absolute and relative terms in the period of investigation. The imports from the subject country are undercutting and suppressing the prices of the domestic industry. The capacity utilization, production, and domestic sales of the domestic industry has declined significantly in the POI. The domestic industry has been suffering significant deterioration in term of profits, cash profits and return on the capital employed.
- f. The material injury suffered by the domestic industry has been caused by the dumped imports.
- g. There exists a likelihood of continuation of dumping and injury in the event of cessation of anti-dumping duty in force in light of the surplus capacities maintained by the Chinese producers, declining demand for the subject goods in major markets like US and EU, tariff barriers placed on Chinese imports by the US, the attractiveness of the Indian market and the export orientation of the Chinese producers.
- h. Despite providing all formats for users/ importers to quantify the impact of ADD and elaborate on how extension of ADD will adversely impact them, none of the users/ importers have provided relevant information. The interested parties have not established impact of ADD on the user industry with verifiable information. Cessation of the anti-dumping duty in force will adversely impact the indigenous production of the product concerned and the fact that the impact of anti-dumping duty is miniscule to the consumers of the product under consideration, the Authority is of the view that the extension of anti-dumping duty will be in public interest.

132. The Authority notes that the investigation was initiated and notified to all interested parties and adequate opportunity was given to the domestic industry, exporters, importers and other interested parties to provide positive information on the aspect of dumping, injury, causal link and likelihood of recurrence/ continuation of dumping and injury. Having initiated and conducted the investigation into dumping, injury, causal link, and likelihood of recurrence/ continuation of dumping and injury in terms of the provisions laid down under the Anti-Dumping Rules, the Authority is of the view that extension of anti-dumping duty is required to offset dumping and injury. The Authority considers it necessary and recommends extension of anti-dumping duty on imports of subject goods from the subject country.

133. Having regard to the lesser duty rule followed by the Authority, the Authority recommends imposition of anti-dumping duty equal to the lesser of margin of dumping and the margin of injury, so as to remove the injury to the domestic industry. Accordingly, the Authority recommends imposition of antidumping duty on the imports of subject goods, originating in or exported from subject country, from the date of notification to be issued in this regard by the Central Government, equal to the amount mentioned in Col. 7 of the duty table appended below. The landed value of imports for this purpose shall be assessable value as determined by the Customs under Customs Act, 1962 and applicable level of custom duties except duties levied under Section 3, 3A, 8B, 9, 9A of the Customs Tariff Act, 1975.

Duty Table

SN	Heading	Description	Country of Origin	Country of Export	Producer	Amount	Unit	Currency
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	29033919	1,1,1,2-Tetrafluoroetha or R-134 a *	China PR	Any country including China PR	Sinochem Environmental Protection Chemicals (Taicang) Co., Ltd.	2.1	KG	US\$
2	-do-	-do-	China PR	Any country including China PR	Shaanxi Sinochem Lantian New Chemical Material Co., Ltd.	2.1	KG	US\$
3	-do-	-do-	China PR	Any country including China PR	Shandong Dongyue Chemical Co., Ltd	2.13	KG	US\$
4	-do-	-do-	China PR	Any country including China PR	Zhejiang Sanmei Chemical Ind. Co., Ltd.	1.29	KG	US\$
5	-do-	-do-	China PR	Any country including China PR	Zhejiang Quhua Fluor-chemistry Co. Ltd.	1.59	KG	US\$
6	-do-	-do-	China PR	Any country including China PR	Zhejiang Quzhou Lianzhou Refrigerants Co. Ltd.	1.59	KG	US\$
7	-do-	-do-	China PR	Any country including China PR	Any other than at SN 1 to 6	3.24	KG	US\$
8	-do-	-do-	Any other country other than China PR	China PR	Any	3.24	KG	US\$

\* Note: The cGMP certified R134a is excluded from the purview of the PUC.

#### N. FURTHER PROCEDURE

134. An appeal against the order of the Central Government that may arise out of this recommendation shall lie before the appropriate forum.

ANANT SWARUP, Designated Authority